



विचार

अनुक्रम

संपादकीय	1
विकास विचार	2
समुदाय केन्द्रित पुनर्वास : अभिमुखीकरण कार्यशाला का विवरण	
आपके लिए	20
87वाँ संविधान संशोधन और पंचायतें	
अपनी बात	23
स्थानीय नेताओं की क्षमता-वृद्धि हेतु शैक्षणिक व्यूहरचना	
गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम	30
संदर्भ सामग्री	35
अपने बारे में	38

संपादकीय टीम :

दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक
ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति'
विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद
के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

87वाँ संविधान संशोधन : पंचायती राज व्यवस्था के कदम पीछे हटाने का प्रयास

भारतीय प्रजातंत्र में वर्ष 1992 में सम्पन्न हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने क्रांतिकारी सुधार किए थे। स्थानीय स्तर पर प्रजातंत्र को अधिक प्रत्यक्ष एवं जीवंत बनाने का यह एक ऐतिहासिक प्रयास था। इन दोनों संविधान संशोधनों के पश्चात राज्यों में पंचायतें और पालिकाएँ अधिक जीवंत हुई हैं क्योंकि स्थानीय रूप से दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर इसने प्रजातंत्र को स्थानीय स्तर पर अधिक प्राणवान बनाया है तथा विकास व सामाजिक न्याय विषयक कार्यों को गति प्रदान की है। इसी कारण से राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र के अनेकानेक स्थापित हितों ने समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज को पंचायतों में दबाने की कोशिश की है। अब यह प्रयास और अधिक संगठित रूप में सामने आ रहा है। देश के कई राज्यों के राजनीतिक दबाव के कारण केन्द्र सरकार ने संसद में 87वाँ संविधान संशोधन प्रस्तुत किया है। इस संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया है कि तीन स्तरों की पंचायतों में से दो स्तरों अर्थात् तहसील, पंचायत और जिला पंचायत स्तरों पर सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा न हो, तथा साथ ही साथ तहसील, पंचायत और जिला पंचायत के प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता द्वारा हों।

इस नए संविधान संशोधन का प्रावधान वस्तुतः 73वें संविधान संशोधन के कार्य पर तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत पर ही प्रहार करने वाला है। किसी भी प्रजातांत्रिक शासन तंत्र में जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि शासन न करते हों तो ऐसे तंत्र का वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तहसील पंचायत में तहसील के सरपंच अपने आप सदस्य बन जाएं और जिला पंचायत में तहसील पंचायतों के प्रमुख अपने आप सदस्य बन जाएं तो इन दोनों पंचायतों में से चुनाव का तत्व ही लगभग समाप्त हो जाता है।

राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से ज्यादा से ज्यादा सत्ता की मांग करती रही हैं, पर वे स्वयं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सत्ता सौंपने को तैयार नहीं। इसी के परिणामस्वरूप यह प्रवृत्ति उद्भूत हुई है। अधिकांश राज्यों में पंचायतें सक्षम तरीके से काम करें, ऐसे निष्ठापूर्ण प्रयास राज्य सरकारों ने नहीं किए, बल्कि वे पंचायतों के प्रमुखों को अपने अंकुश में रखना चाहती हैं। इसी से वे तहसील और जिला पंचायतों के प्रमुखों के सीधे चुनाव चाहती हैं, पर सदस्यों के सीधे चुनाव नहीं चाहतीं। इस तरह 87वाँ संविधान संशोधन स्थानीय स्तर पर पंचायतों में गतिरोध पैदा करने वाला बनेगा और राज्य सरकारों को पंचायतों की कीमत पर सबल बनाने वाला बनेगा। प्रजातंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए परोक्ष और प्रतिनिधित्व वाले प्रजातंत्र से प्रत्यक्ष व सीधे लोकतंत्र की ओर अधिकाधिक आगे बढ़ना पड़ता है। 73वें संविधान संशोधन ने ग्राम सभा को सत्ता सौंप कर इस दिशा में कदम बढ़ाये थे। 87वाँ संविधान संशोधन उल्टी दिशा में जाने वाला है, इसी से यह पंचायती राज संस्थाओं के लिए अपने कदम पीछे हटाने के समान है। पंचायती राज संस्थाओं को और सीधी व प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिमायतियों को इस संशोधन का कड़ा विरोध करना जरूरी है।

समुदाय केन्द्रित पुनर्वास : अभिमुखीकरण कार्यशाला का विवरण

‘उन्नति’ द्वारा 1 से 3 जून, 2001 के मध्य समुदाय केन्द्रित पुनर्वास विषयक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कच्छ के मांडवी में आयोजित किया गया था। उसमें गुजरात के भूकम्पग्रस्त अंचलों में पुनर्वास कार्य में सम्मिलित स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। उसका विवरण ‘चरखा’ के श्री संजय दवे के द्वारा लिखा गया था, जो यहां प्रस्तुत है।

प्रस्तावना

किसी भी बड़ी विपत्ति के समय यह देखा गया है कि अनेक लोगों के द्वारा बचाव और राहत कार्य अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया जाता है, परंतु निराश्रित महिलाओं, अनाथ बालकों और विकलांगों जैसे समुदाय के सर्वाधिक कमजोर वर्गों की विशिष्ट जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। समाज के इन कमजोर वर्गों की विशिष्ट जरूरतों संबंधी समझ और संवेदनशीलता के अभाव में ही मुख्य रूप से ऐसा होता है। सामान्य मानस ऐसा है कि उनका पुनर्वास संस्थागत रीति से हो, जबकि इन वर्गों से हुई सघन चर्चाओं के दौरान यह जानने को मिला कि वे अपने समुदायों में ही अपना पुनर्वास चाहते हैं।

विशेष रूप से हाल ही भूकम्प जैसी बड़ी विपत्ति के बाद के पुनर्वास के अनेक पहलू हैं। पुनर्वास प्रक्रिया में सम्मिलित सभी लोगों की संवेदनशीलता को जगाने की जरूरत है तथा साथ ही साथ कमजोर वर्गों के विशिष्ट और प्रसंगोचित सवालियों के लिए समुदायों को भी तैयार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में तीन दिनों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 3 जून, 2001 के मध्य कच्छ जिले के मांडवी में आयोजित किया गया था। कार्यशाला में गुजरात के भूकम्पग्रस्त अंचलों में पुनर्वास में संलग्न 21 स्वैच्छिक संस्थाओं के 49 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। समुदाय की देखभाल करने वाले स्वयंसेवकों को इस संबंध में संवेदनशील बनाना तथा कमजोर वर्गों की विशिष्ट जरूरतों को समझने के लिए संवेदनशीलता उत्पन्न करना और इसके लिए प्रभावशाली कार्यनीति बनाना इस कार्यशाला का उद्देश्य था। इस कार्यशाला के उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- अनाथ बालकों, एकाकी महिलाओं, विधवाओं तथा विकलांगों आदि विशिष्ट वर्गों की विशिष्ट जरूरतों को समझना।
- समुदाय केन्द्रित पुनर्वास की कार्यनीति गढ़ने की समझ विकसित करना।

इस कार्यशाला में अनेक विशेषज्ञ व्यक्तियों ने अपना सहयोग प्रदान किया था : निराश्रित महिलाएं और कानून विषय में सुश्री सोफिया खान (विकास अध्ययन केन्द्र) और सुश्री उमा बहन (एक्शन एड आदिपुर), पुनर्वास और कानून के विषय में श्री मिहिर देसाई (इंडिया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, मुंबई)। विकलांगों की समस्या और सामुदायिक पुनर्वास विषय में श्री रामभाई जादव (अंधजन मंडल), वंचितों के आवास के बारे में श्री भानुप्रसाद मिस्त्री और श्री विवेक रावल (उन्नति) तथा हैंडिकेप इंटरनेशनल। समग्र कार्यशाला का संचालन श्री किशन कल्शी (यूनिसेफ) और श्री बिनोय आचार्य (उन्नति) ने किया था।

प्रभावशाली पुनर्वास हेतु सशक्तिकरण

कार्यशाला के प्रथम दिन सभी सहभागियों का स्वागत करके उन्हें शिविर का उद्देश्य समझाया गया। तदुपरांत परिचय निम्न पद्धति से आयोजित किया गया। सबसे पहले सभी सहभागियों को तीन-तीन के समूहों में विभक्त किया गया। तीनों व्यक्तियों को बारी-बारी से वक्ता, श्रोता और निरीक्षक की भूमिकाएं निभानी थीं। सहभागियों ने अपने नाम, संस्था के नाम, भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में किए गए अपने काम और उससे प्राप्त अनुभव, उसकी समयावधि, भूकंप से हुई व्यक्तिगत या पारिवारिक क्षति तथा अपने काम से मिले सबक के बारे में तीन-तीन के समूह में एक-दूसरे को अपना परिचय प्रदान किया था। तीन-तीन के समूह में पारस्परिक परिचय के उपरांत बड़े समूह में प्रत्येक सहभागी ने अपना परिचय दिया था।

परिचय के दौरान सहभागियों ने पुनर्वास प्रक्रिया से प्राप्त अपने अनुभव इस प्रकार प्रस्तुत किए :

- मानवीय व्यवहार के बारे में जानने को मिला।
- महिलाओं की मानसिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य की हिफाजत के बारे में जानकारी मिली।
- गरीब व अमीर व्यक्ति के बीच का फर्क पता चला।
- मरीज के शीघ्र उपचार का महत्त्व समझ में आया।
- लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना सीखा।
- समुदाय के विविध लोगों के साथ विचारों का प्रभावी तरीके से आदान-प्रदान करना सीखा।
- भूकम्प से प्रभावित लोगों के मन के डर को हंसी-मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए, वरन् उनके डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
- प्राकृतिक आपदा के बाद काम करते समय मन में बहुत धीरज होना चाहिए। बहुत धैर्य के साथ काम करेंगे, तभी अच्छी तरह और तेज़ी से काम कर सकेंगे।
- विपत्ति के बाद लोगों की मानसिक दशा के बारे में जानने को मिला।
- कच्छ के सामाजिक सम्बंध पसंद आए।
- लोगों के साथ सफलतापूर्वक काम करने का कौशल विकसित हुआ।
- भूकंपग्रस्त अंचल में काम करने वाले स्वयंसेवकों की तकलीफों को जानकर उनका समाधान करना सीखा।
- किसी भी तरह के भेदभाव के बगैर मानवीय अभिगम से काम करने की सीख मिली।
- सर्वप्रथम अनाथ बालकों का विचार आया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके प्रभावशाली प्रबंध करने का कौशल प्राप्त किया। आफत के समय निर्णय लेना सीखा।
- अहमदाबाद में भूकंपग्रस्त क्षेत्रों के बीच काम करने की जरूरत समझ में आई।
- प्राकृतिक आपदा के बाद किए जाने वाले कामों का संकलन करने का कौशल अर्जित किया।
- भूकंप के तीन माह बाद भी प्रभावित लोगों में लेने और मांगने की भावना ही देखने को मिली।
- प्रभावित लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखा।

पुनर्वास के बारे में प्राप्त अनुभवों की प्रस्तुति के उपरांत प्रत्येक

सहभागी ने कार्यशाला में अपनी अपेक्षाएं प्रस्तुत की थी। पिछड़े लोगों के लिए समुदाय को पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल करने, समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया में प्रभावितों को, विशेष रूप से महिलाओं को जोड़ने तथा परामर्श के बारे में जानने की अपेक्षाएँ सहभागियों ने प्रस्तुत कीं। द्वितीय सत्र में भूकंप के बाद की पुनर्वास प्रक्रिया में सहभागियों द्वारा अनुभूत पांच मुख्य समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। इसके लिए सहभागियों ने कुल चार समूहों में बंट कर मुख्य समस्याओं की सूची बनाई थी और उस पर समूह में सघन चर्चा की थी। चर्चा के अंत में तैयार की गई समस्याओं की सूची में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पांच समस्याओं को सहभागियों ने प्राथमिकता के क्रम में लिखा था। उसमें लोक सहभागिता का अभाव, भूकंप से सुरक्षित कामचलाऊ आवास लोक सहभागिता शीघ्र पूरे करवाने की निष्फलता, यथासमय रोजगार का अभाव, सामाजिक न्याय का अभाव, सूचनाओं का अभाव इत्यादि समस्याएँ मुख्य रूप से गिनाई गई थीं।

इसके उपरांत चारों समूहों के एक-एक प्रतिनिधि ने इन समस्याओं को समस्त सहभागियों के समक्ष फ्लिप चार्ट पर प्रस्तुत किया था। सहभागियों के चारों समूहों की प्रस्तुति के पश्चात संचालनकर्ताओं (फेसिलिटेटर्स) ने उनमें से निम्न तरीके से समस्याओं का सारांश दर्शाया था:

1. अभिगम
2. व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता
3. क्रियान्वयन के दौर की समस्याएँ
4. जोखिम

उपर्युक्त मुद्दों को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि पुनर्वास प्रक्रिया में जुड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं का काम करने का अभिगम अलग-अलग होता है। कोई संस्था मात्र दलितों के लिए ही काम करने का अभिगम रखती है। कोई सिर्फ महिलाओं या बालकों के लिए ही काम करने हेतु तत्पर रहती है। जबकि कुछ संस्थाएँ सभी लोगों के लिए काम करती हैं। कोई भी योजना शुरू करने से पहले कोई भी व्यक्ति या संस्था सबसे पहले अपना अभिगम स्पष्ट करती है। इसके बाद वे उसके आधार पर अपना काम शुरू करती हैं। तदुपरांत उन कार्यों का मूल्यांकन करने के आधार तय करने पड़ते हैं।

पुनर्वास प्रक्रिया में मुख्य समस्याओं के बारे में सहभागियों के समूह की प्रस्तुति

समूह-1

1. बालक और शिक्षण

- प्रभावित बालकों के साथ ठोस योजना
- स्कूल बंद - पुनः शिक्षण

2. समस्या का हल

- संस्थागत स्तर पर स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

3. सूचना का आदान-प्रदान

- भवन निर्माण कार्य
- पैकेज क्षतिपूर्ति - विधवा, विकलांग
- विकलांग और महिलाओं की आजीविका के स्रोत
- अलग-अलग सहयोगी संस्थाओं का संकलन

4. पुनर्वास प्रक्रिया में छूटती कड़ियाँ

- दत्तक गांव को दाता संस्था के द्वारा छोड़ना
- चिकित्सा राहत का फॉलोअप
- स्थानीय स्तर के संगठनों की भागीदारी का अभाव (पंचायत)

5. व्यावसायिक अवसरों की ठोस योजना

- महिलाओं को प्रशिक्षण और अवसर
- किसानों की जरूरतें

समूह-2

पांच प्रमुख मुद्दे

1. सामाजिक मानसिक, आर्थिक, तनाव के समक्ष संघर्ष
2. कार्यकर्ता की मर्यादा - व्यक्ति स्तर पर एवं संस्था स्तर पर
3. आर्थिक एवं वैचारिक संघर्ष
4. नेटवर्किंग और मानीटरिंग
5. सरकारी-गैर सरकारी संस्था का अभिगम

समूह-3

प्राथमिकता वाले प्रमुख मुद्दे

1. जन-सहभागिता का अभाव (सभी प्रक्रिया में)
2. भूकंप से सुरक्षित कामचलाऊ आवास उपलब्ध नहीं हुए (परिणाम स्वरूप खेती और आर्थिक विषयों पर असर)
3. यथा समय रोजगार मिलने का अभाव (परिणामतः स्वास्थ्य एवं स्थलांतरण की समस्या)
4. सामाजिक न्याय का अभाव (सर्वाधिक वंचित समुदाय को अधिकार नहीं मिले)

5. सूचना का अभाव (सरकारी नीति, गुमशुदा लोगों, आवास, मुआवजे, आदि के बारे में)
6. नेटवर्किंग का अभाव (संस्थाओं, सरकार और अन्य हितैषियों के मध्य)

समूह-4

1. सरकारी योजनाएँ और उनके सवाल

- बार-बार बदलती नीति
- सर्वे में भेदभावयुक्त व्यवहार
- सहायता के वितरण में भेदभाव
- राशन कार्ड का दुरुपयोग (नहीं, और है तो दुरुपयोग)
- मदद के लिए चार क्षेत्रों को ही प्राधान्य
- सरकार के साथ नेटवर्क में भेदभावयुक्त व्यवहार
- स्रोतों का अपर्याप्त उपयोग और दुरुपयोग
- सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार
- आश्रय, केश डोल्स, विकलांग सहायता, विधवा सहायता तथा अनाथ बालकों के पुनर्वास का प्रश्न)

2. नेटवर्क और संचालन का प्रश्न

- गैर सरकारी संस्थाओं के मध्य नेटवर्क के प्रश्न
- सत्ता का संघर्ष
- वितरण में पुनरावर्तन तथा अंदरूनी गांव तक न पहुंचना
- दत्तक लेने की वृत्ति

3. प्राथमिक सुविधा तथा ढांचागत सहूलियतें

- पानी, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, घास-चारे, शिक्षण आदि प्रश्न
- शिक्षण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव
- सवणों द्वारा जाति भेद के आधार पर दलितों एवं गरीबों का शोषण
- आघात के बाद सेवा-सुश्रूषा का अभाव

4. सामाजिक ढांचे का प्रश्न

- जाति प्रथा और उसकी मजबूत पकड़
- राजनीतिक व धार्मिक संगठनों द्वारा कार्यक्रमों में अवरोध तथा भेदभावयुक्त व्यवहार
- जाति आधारित वितरण, लालचयुक्त लोकवृत्ति

5. पुनर्वास और लोगों की लाचारी

सरकार एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के भरोसे लोगों ने अपने मकान बनवाने स्थगित रखे और अब आश्रय विहीन लोगों की दूसरों के आधार पर रहने, जीने की प्रवृत्ति।

भूकम्प के बाद की पुनर्वास प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने के आधार

सहभागियों ने कार्ड पर मूल्यांकन के आधार निम्नानुसार व्यक्त किए:

- संस्कृति के आधार पर पुनर्वास का काम हुआ है या नहीं; यह देखना।
- सर्वाधिक वंचित समुदाय की मूलभूत जरूरतें पूरी हुई हैं या नहीं, यह पता लगाना।
- राहत एवं पुनर्वास के कार्यों हेतु निश्चित किया गया भौगोलिक क्षेत्र।
- आवास, आजीविका और अधिकारों की पूर्ति हुई है या नहीं?
- लोग अपने सवालों के समाधान करने में कितने सफल हुए?
- व्यक्ति और समुदाय की प्राथमिक जरूरतें पूरी हुईं?
- पुनर्वास के काम से लोगों की आर्थिक और मानसिक परिस्थिति में फर्क पड़ा?
- आवास, भोजन तथा पानी के संदर्भ में पहले की और वर्तमान स्थिति?
- सरकारी योजनाओं का लाभ कितनों को, कितना और कब मिला?

सहभागियों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त आधार उनके द्वारा पहले प्रस्तुत मुख्य समस्याओं से काफी भिन्न थे। अतः मूल्यांकन के आधार कैसे होने चाहिए, यह समझाने हेतु संचालनकर्ताओं ने सहभागियों के समक्ष निम्न प्रश्न प्रस्तुत किए:

क्या प्राकृतिक आपदाएँ सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करती हैं?

उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में सहभागियों को तीन विकल्प प्रस्तुत करने थे: 1. हां, 2. नहीं, 3. नहीं, लेकिन....

सहभागियों ने अपने मंतव्य के अनुसार अपना विकल्प चुन लेने के बाद आपस में उस बारे में चर्चा की थी और अपने चुने गए विकल्प का कारण स्पष्ट किया था। अधिकांश सहभागियों ने 'नकार' में उत्तर दिया था। इसके बाद, इस विषय पर बड़े समूह में चर्चा हुई थी कि प्राकृतिक आपदाओं का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है। सहभागियों ने बताया था कि बालकों, महिलाओं, गरीब महिलाओं, वृद्धों, पिछड़े लोगों, विकलांगों, गरीबों, विधुरों, विधवाओं, अनाथ

निःसहाय दलित सशक्त बने

राजस्थान में हर वर्ष की तरह गत वर्ष भी अकाल की स्थिति थी। ऐसे में राजस्थान के गांवों में पशुओं के लिए पंजाब से घास-चारा लेकर आने वाले ट्रक जिले या तहसील मुख्यालय पर घास उतारते थे। फिर वहां से बैलगाड़ों के द्वारा गांवों तक घास ले जाया जाता था। एक गांव में तहसील मुख्यालय से जिन बैलगाड़ों के द्वारा घास लाया जाता था, वे बैलगाड़े गांव के मुखिया के थे। पंजाब से घास लेकर आने वाला ट्रक भी उनका ही था। अतः मुखिया के घर पर घास का ढेर लग जाता और गांव में जरूरतमंद दलितों को कम घास मिलता। गांव में दलितों के 15 परिवार थे। इन परिवारों को घास न मिल पाने के कारण हर वर्ष इन्हें स्थलांतरण करना पड़ता था। एक स्थानीय संस्था के ध्यान में जब यह बात आई तो उस संस्था ने गांव के दलितों को तीन बैलगाड़े दे दिए। परिणामस्वरूप उनको भी पर्याप्त मात्रा में घास मिलने लगी। गांव के मुखिया को भी सच्ची परिस्थिति समझाई गई। परिणामतः अगले वर्ष से स्थलांतरण रुक गया।

बालकों, दलितों, कोली, मुस्लिम, आदि पर प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक असर होता है। चर्चा के दौरान संचालनकर्ताओं ने बताया था कि दुनिया में अलग-अलग दुर्घटनाओं के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया कम से कम दो वर्षों से लेकर बाईस वर्षों तक चली है। इन तमाम दुर्घटनाओं के बाद देखने में आया है कि दुर्घटनाओं का सबसे बुरा प्रभाव अनाथ बालकों, विधवा महिलाओं, एकाकी महिलाओं, विकलांगों, दलितों और सर्वाधिक वंचित लोगों पर होता है। अतः राहत और पुनर्वास प्रक्रिया में उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन सिद्धांतों के मुताबिक प्राकृतिक आपदा के सभी प्रभावित लोगों का हमें राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया में ध्यान रखना है। इसके बावजूद उपर्युक्त व्यक्तियों को हमें विशेष रूप से लक्ष्य समूह के रूप में गिनते हुए अपनी रणनीति बनानी होगी। वैसे, समूह के लिए हम काम करना तय करेंगे तो कैसी तैयारियां करनी पड़ेगी, इस सवाल के उत्तर में सहभागियों ने निम्न प्रकार के मुद्दे गिनाये थे:

- ऐसे समूहों के लिए काम करने की क्षमता चाहिए।
- कौशल चाहिए।
- तत्काल परिणाम नहीं दिखेगा।
- शायद वे सहभागी न हो सकें।
- शायद उनके लिए किया गया काम उल्लेखनीय न दिखे।

बलम देवी की बात

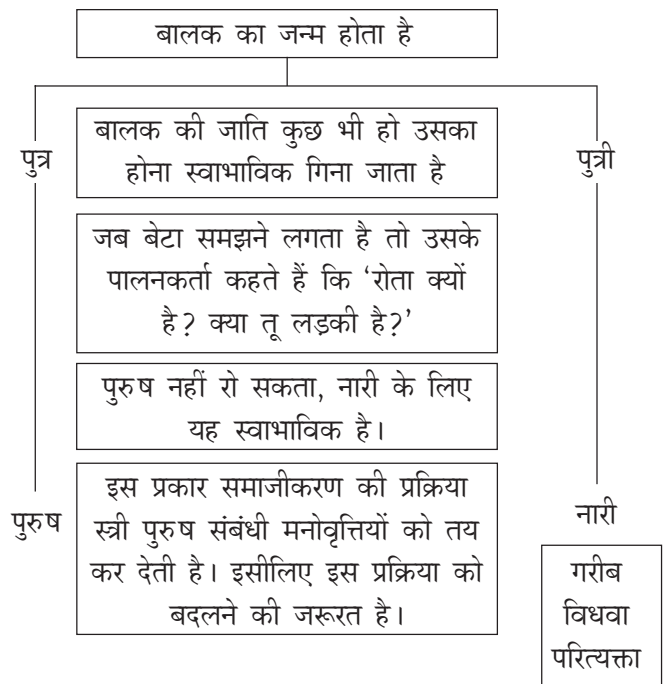
बलम देवी उत्तरांचल राज्य के पहाड़ी अंचल में रहती है। उसका पति उसे रोज बहुत मारता था। एक दिन मार की वेदना सहन न कर पाने पर उसने अपने पति पर पीछे से कुल्हाड़ी मार दी। परिणामतः उसका पति मर गया। गांव के पुरुषों ने पति की लाश के साथ उसको और उसकी सास को रात भर कमरे में बंद रखा। इस पर स्थानीय महिला स्वैच्छिक संगठन 'सहारा संघ' ने पुरुषों को बलम देवी के साथ किए गए इस कृत्य के लिए क्षमा मांगने को कहा। पुरुषों ने बलम देवी से क्षमा मांगी। पुलिस द्वारा बलम देवी की धरपकड़ हुई। ससुर पक्ष के पुरुष बलम देवी की हत्या की मांग कर रहे थे। उसकी सास को भी उसके प्रति उग्र रोष था। स्वाभाविक रूप से बलम देवी को उसके वकीलों ने बड़ी मुश्किल से जमानत दिलाई। परंतु जेल से बाहर उसे सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था। अतः 'सहारा संघ' ने जेल के अंदर ही एक व्यवस्था कर दी। उस दौरान 'सहारा संघ' की कुछेक महिला कार्यकर्त्रियों ने उसकी सास के साथ उसके घर में ही रहना शुरू किया। कार्यकर्त्रियों ने सास को समझाया। उसके साथ बहुत बातें की। इससे सास ने अपनी बहू बलम देवी के प्रति अपना रोष संघ की कार्यकर्त्रियों के समक्ष प्रकट कर दिया। धीरे-धीरे बलम देवी के प्रति उसका मनोभाव नरम पड़ा। तदुपरांत बलम देवी को उसकी सास के साथ रहने के लिए लाया गया। शुरूआत में 'सहारा संघ' की बहनें बारी-बारी से कुछ दिनों तक उन दोनों के साथ उनके घर में ही रहीं। 'सहारा संघ' द्वारा उनकी आर्थिक मदद करने की बात कहने पर सास-बहू ने मना कर दिया और खेत में साथ-साथ मजदूरी करना तय किया। आज बलम देवी अपनी सास के साथ शांतिपूर्वक रह रही है।

चर्चा का मुख्य सार यह था कि हमने पुनर्वास प्रक्रिया में सहभागी प्रक्रिया के द्वारा कितने असहाय लोगों को सशक्त किया, यह बात विशेष रूप से देखनी चाहिए। उपर्युक्त चर्चा के उपरांत समुदाय आधारित पुनर्वास की समझ विकसित की गई। समुदाय आधारित पुनर्वास का महत्त्व समझाने हेतु एक खेल आयोजित किया गया। खेल के सहभागी के रूप में सर्वप्रथम सहभागियों के समक्ष एक विचारणीय स्थिति रखी गई : अनाथ बालक अनाथाश्रम में सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि वहां सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सहभागियों को अपने उत्तर हां, ना, अथवा ना, लेकिन... में से एक देना था। अधिकांश सहभागियों ने बताया कि अनाथ बालक अनाथाश्रम में सुरक्षित नहीं रह सकते। उसके बजाय बालक को समुदाय में ही

रखा जाए तो वह सुरक्षित रह सकता है और उसका अच्छी तरह से लालन-पालन हो सकता है। इसके लिए हमको समाज पर, समुदाय पर भरोसा करना पड़ेगा। समाज के पास बालक को संभालने का कौशल है ही, यदि न हो तो विकसित हो सकता है। अगर किसी बालक का समुदाय में लालन-पालन संभव न हो तो अनाथाश्रम को अंतिम उपाय के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। परंतु यथार्थ में यह बहुत जरूरी है कि बालक को समुदाय में ही रखा जाए।

निःसहाय समूहों का सशक्तिकरण

निःसहाय समूहों के बारे में समझ विकसित करने के बाद उनके सशक्तिकरण के बारे में तीसरा सत्र लिया गया। विशेषज्ञ व्यक्ति ने प्रभावित हो वाली महिलाओं के कानूनी अधिकारों की बात कहने से पहले स्त्री-पुरुष संबंधों, स्त्रियों के प्रति लोगों का अभिगम व दृष्टिकोण तथा स्त्रियों की स्थिति की बात दृष्टांतों के साथ प्रस्तुत की थी। महिलाओं के प्रति देखने का लोगों का दृष्टिकोण किस तरह निर्मित होता है, यह समझाने के लिए उन्होंने सहभागियों के समक्ष निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किया:



उपर्युक्त दृष्टांत प्रस्तुत करके उन्होंने महिलाओं के प्रति पुरुषों के तीन अभिगम समझाये थे:

1. **रक्षणात्मक अभिगम:** इस अभिगम में पुरुष यह मानते हुए कि नारी दुर्बल है, और उसे रक्षा की जरूरत है, अतः रक्षा करने

का प्रदर्शन करता है।

2. **उदासीन अभिगम:** पुरुष (पति) नारी (पत्नी) को कुछ भी करने की छूट देने का मानों भाव दर्शाता है।
3. **एक-दूसरे का पूरक होने का अभिगम:** स्त्री के काम में पुरुष मदद देकर तथा पुरुष के काम में स्त्री मदद देकर एक-दूसरे के पूरक बनने का भाव रखें। कोई भी संबंध एक-दूसरे का पूरक बनने पर ही स्थिर रह सकता है - ऐसा अभिगम विकसित करने की जरूरत है।

समाज में महिलाओं के साथ उपरोक्त प्रकार का अभिगम देखने में आता है। वस्तुतः प्रत्येक पुरुष को स्त्री को अधिकारों, उसके मन के भावों तथा भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

पुनर्वास प्रक्रिया में महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने बताया था। उसके पश्चात सहभागियों से कहा गया कि वे विधवा की भूकंप से पहले की और बाद की स्थिति का विश्लेषण करें। सहभागियों ने इस संदर्भ में अपने मंतव्य इस प्रकार प्रस्तुत किए थे:

- पुत्रवती युवा विधवा की दशा बहुत खराब होती है।
- वृद्ध महिला की स्थिति खराब है।
- दलित महिला की स्थिति खराब है।

सहभागियों के मंतव्यों को जोड़ते हुए विशेषज्ञ व्यक्ति ने बताया कि प्राकृतिक विपत्तियों में सभी वर्गों की महिलाओं पर असर पड़ता है। उनमें से विधवा, एकाकी और परित्यक्ता महिलाओं पर और ज्यादा असर पड़ता है। इन महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमें स्वयं को उनकी स्थिति में रखकर देखना चाहिए। हमें उनके दृष्टिकोण से सोचना चाहिए।

हमें निःसहाय महिलाओं को सशक्त करने का बीड़ा उठाना चाहिए। जैसे, पुनर्वास प्रक्रिया में हम किसी को भी बाकी नहीं रख सकते और न ही रखना चाहिए। विशेषज्ञ व्यक्ति ने आपदा की स्थिति के बाद महिलाओं की निःसहाय स्थिति को लेकर समझ विकसित करने के लिए सहभागियों के समक्ष कारगिल का उदाहरण प्रस्तुत किया था। कारगिल में भारतीय सेना के मृत जवानों की विधवाओं की दशा अत्यंत दयनीय बनी थी। उनकी सम्पत्ति और मिलने वाली

विधवा अजी बहन की बात

अजी बहन रामसिंह मेरिया कच्छ जिले के भचाऊ नगर में रहते थे। कुछ वर्ष पहले अजी बहन और रामसिंह ने अपना नया मकान बनावाया था, और उसमें रहना शुरू किया था। उनके पास वाले मकान में अजी बहन के जेठ रहते थे। अजी बहन घर की सभी बहुओं में सबसे छोटी हैं। रामसिंह भूकंप में मारे गए। अपने पीछे वे अजी बहन और पांच वर्ष की एक पुत्री छोड़ गए। अजी बहन को पति की मृत्यु के मुआवजे के रूप में एक लाख रुपए मिले। परंतु उसके जेठ अपने और उसके संयुक्त नाम से खाता खुलवाने हेतु दबाव देने लगे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि एक लाख रुपये उन्हें मिलें। जैसे, वे अजी बहन से यों कहते थे कि संयुक्त खाता खोलने पर पैसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जेठ के मन में ऐसी धारणा थी कि अजी बहन अपनी पुत्री को छोड़कर तथा रुपये लेकर किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग जाएगी।

सरकारी आर्थिक सहायता परिवार में ही रहे, इस विचार से महिला को 10 वर्ष के छोटे देवर के साथ ब्याह देने के किस्से भी देखने में आए थे। यही नहीं, अपितु उसके पति का उत्तराधिकार पुत्र को मिले, इसके लिए महिला को बहलाकर सम्मति-पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। कई स्थानों पर महिलाओं की हत्या भी हुई थी। उत्तरांचल के पहाड़ी प्रदेश की महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था कि, वहां पुरुष की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थि निकलती है। परंतु अविवाहिता महिला की मृत्यु होती है तो उसकी लाश बड़े से थैले में डालकर अंतिम-क्रिया के लिए ले जाया जाता है। इस प्रकार समाज में स्थान-स्थान पर अलग-अलग ढंग से महिलाओं का शोषण हो रहा है। भूकंप के बाद भी पुनर्वास प्रक्रिया में भी महिलाओं के साथ अन्याय हो सकता है। अतः प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवकों को महिलाओं के कानूनी अधिकार जानने चाहिए।

वंचित महिलाओं की कानूनी रक्षा

विशेषज्ञ व्यक्ति ने सहभागियों के समक्ष महिलाओं से सम्बंधित कानूनी धाराओं की भी चर्चा की। सहभागियों ने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली कानूनी कठिनाइयाँ सबके सामने प्रस्तुत कीं और संचालनकर्ता ने उनका समाधान बताया। उन्होंने बताया कि हमें कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ सामाजिक प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी। उदाहरणार्थ भूकंप

प्रभावित अंचलों में अनाथ बालकों से हमें कहना पड़ेगा कि मुआवजे का पैसा उनके नाम ही है और उस राशि पर उन्हीं का अधिकार है।

पैतृक-सम्पत्ति/ स्व-उपार्जित सम्पत्ति

भारतीय कानून की व्यवस्था के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति पर पुरुष को जन्म लेने के साथ ही हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त है। जबकि पुत्री को वह हिस्सा नहीं मिलता। सामान्यतया लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि कानूनी दृष्टि से परिवार की सम्पत्ति में से पुत्र-पुत्री को समान हिस्सा मिलता है, परंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। संयुक्त परिवार के मालिक के घर में स्त्री को विभाजन का अधिकार नहीं है। यदि स्त्री विधवा, परित्यक्ता, निराधार हो तो वह घर में रह सकती है।

भारतीय दंड-संहिता की धारा 498-ए

इस धारा के तहत स्त्री को शारीरिक या मानसिक दृष्टि से यातना दी जाए तो त्रास देने वाले की गिरफ्तारी हो सकती है। अगर अपराध प्रज्ञेय हो तो गिरफ्तारी हो सकती है, और अप्रज्ञेय हो तो गिरफ्तारी नहीं होती। यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि कोई भी अपराध प्रज्ञेय है अथवा नहीं, क्योंकि पुलिस को जब गिरफ्तार करने की कानूनी सत्ता मिल जाती है तो वह उसका दुरुपयोग कर सकती है। हमने किसी स्त्री पर होने वाले अत्याचार को लेकर उसके पति

पति की वृत्ति बदल गई

रूपी बहन 50 वर्षीया ग्रामीण वृद्धा हैं। वे अपने विवाह के बाद से पति का बहुत ध्यान रखती, हर आदेश का पालन करती थी। एक बार रूपी बहन ने एक संस्था के द्वारा आयोजित सामाजिक लिंग समानता के प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण में स्त्री-पुरुष, समानता के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद एक दफा रोजमर्रा के नियमानुसार रात के समय वे कोई काम निपटा रही थीं कि उनके पति ने उनसे उनका बिस्तर लगाने कहा। रूपी बहन विनोदी और सौम्य स्वभाव की हैं। उन्होंने हौले से पति को अपना बिस्तर खुद लगाने को कह दिया। पहले तो उनके पति अवाक् रह गए। विवाह के बाद के इतने वर्षों में रूपी बहन ने बिस्तर बिछाने के लिए कभी इनकार नहीं किया था। उस रात पहली बार रूपी बहन के पति ने अपना बिस्तर खुद बिछाया। रूपी बहन के पति की वृत्ति बदल गई और वे पत्नी के कामों में उमंग से सहयोग देने लगे।

या ससुर पक्ष के विरुद्ध शिकायत की हो तो पुलिस द्वारा उस पर अत्याचार करने या रुपये ऐंठने की संभावना रहती है। इसका ध्यान रखना चाहिए कि धारा-498 को दुरुपयोग न हो। जब हम कोई एफ.आई.आर. (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज करते हैं तो उसकी एक प्रति और अपराध रजिस्टर्ड नंबर पुलिस से मांग लेना चाहिए। स्त्रियों के उत्तराधिकार विषयक सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक सहभागी को तद्विषयक साहित्य प्रदान किया गया था।

विकलांगों का पुनर्वास

अगले दिन प्रारंभ में पूरे दिन लिए जाने वाले सत्र का सार प्रदान किया गया। उसके बाद सहभागियों ने कार्यशाला के प्रथम दिन के सत्रों का संक्षिप्त पुनरावर्तन प्रस्तुत किया। उस दौरान सभी सहभागियों ने वंचित समूह, उनके परिवार और समुदाय इन तीनों को सम्मिलित करके सारे काम किए जाने की जरूरत पर बल दिया था। समुदाय आधारित पुनर्वास में विधवा, परित्यक्ता, तथा एकाकी महिलाओं, अनाथ बालकों, विकलांग आदि समुदाय के सबसे कमजोर वर्गों को केन्द्र में रखकर पुनर्वास के काम करने का सभी सहभागियों को विश्वास हुआ। ऐसे वंचित समूह के प्रति समाज में दया का नहीं अपितु स्वीकृति का भाव पैदा किया जाना चाहिए। तदुपरांत प्रथम दिवस का वंचित महिलाओं से संबंधित सत्र को आगे बढ़ाया गया। समुदाय के स्तर पर आप महिलाओं के साथ कौनसे काम करते हैं? ऐसे प्रश्न के उत्तर में सहभागियों ने पानी, स्वास्थ्य, आवास, बालक आदि मुद्दे बताये थे। यहीं एक महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में आया कि ये तमाम तथाकथित स्त्री-विषयक कार्य वाकई स्त्री को क्या और कितना लाभ पहुंचाते हैं। उसके व्यक्तिगत जीवन में होने वाली हिंसा को लेकर हम कितनी चर्चा करते हैं। तब सहभागियों को बताया गया कि आज अधिकांश स्वसहाय समूहों की महिलाएँ अपने हिसाबों में डूब गई हैं, परंतु उसके पीछे का सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अगर एक महिला 10 रुपये भी कमाए तो उस पर उसका नियंत्रण है या नहीं, इसका पता लगाना चाहिए।

गुजरात में रोजाना 18 महिलाओं की अपमृत्यु घटित होती है। प्राकृतिक आपदा के अलावा महिला पर होने वाली हिंसा में तिगुनी वृद्धि हुई है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने में आया है। गुजरात में भूकंप के बाद स्त्रियों पर अत्याचार बढ़े हों तो भी उनके बारे में समाचार

बाहर नहीं आते। महिलाओं पर हिंसा का होना स्वाभाविक है, ऐसा समाज के बहुत से लोग मानते हैं, क्योंकि वे लोग महिलाओं के चरित्र के बारे में स्वयमेव धारणा कर बैठते हैं।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए हमें अपने से ही शुरूआत करनी पड़ेगी। हमें अपने घर की महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। उनके प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा। हम अपनी जरूरतों के लिए महिलाओं का कितना अधिक उपयोग करते हैं, इस बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे समाज में पुरुष घर का काम करता है तो उसे 'जनाना' कहा जाता है। परंतु अगर पति-पत्नी को अच्छी तरह से घर-गृहस्थी चलानी है तो उन्हें एक-दूसरे को समझना पड़ेगा और परस्पर पूरक बनना पड़ेगा। पुनर्वास प्रक्रिया में भी भवन निर्माण के काम पर ध्यान देने के साथ-साथ उसमें रहने वाली नारी का भी ध्यान रखना होगा। भूकंप के बाद के पुनर्वास के दौरान महिलाओं के संग काम करते समय सामने आने वाले अवरोधों के बारे में सहभागियों ने कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति दी। इस बारे में बात करते हुए विशेषज्ञ व्यक्तियों ने बताया कि यदि महिलाओं के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित करना हो और महिलाओं को उनके परिजनों द्वारा गांव से बाहर न भेजा जा सके तो उनके घर पर या गांव में ही प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। उस दौरान उन महिलाओं के परिवारों का तथा समुदाय का विश्वास अर्जित करना चाहिए।

हमारा वाणी-व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उससे समुदाय के मन में विश्वास जम सके। पुनर्वास प्रक्रिया में गठित समितियों में भी महिलाओं को स्थान देना चाहिए। फिर, महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में सतत निरीक्षण करते रहना चाहिए। हिंसा रोकने के लिए महिलाओं को अपनी समस्या व्यक्त करने का अवसर और वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। महिलाओं के प्रभावी पुनर्वास के लिए उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी करनी जरूरी हैं। उनको जाग्रत करके उन्हें अबला से सबला बनाना जरूरी है।

विशेषज्ञ व्यक्ति ने विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास विषयक द्वितीय सत्र की शुरूआत में विकलांगों के समुदाय आधारित पुनर्वास पर बल दिया था। उन्होंने भारत के विकलांग लोगों की तथा समुदाय

विकलांग बालक, विकलांग महिला और विकलांग किसान हेतु सहभागियों द्वारा किया गया प्रवृत्ति आयोजन

- 1. आमदनी का उपार्जन:** महिलाओं को ऐसा काम दें कि वे बैठे-बैठे निगरानी रख सकें। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। स्वसहाय समूह में उन्हें शामिल करके रोजगार दिलाने का प्रयास करना। किसान स्वयं खेती करके रोजगार पैदा कर सकें, इसके लिए सहयोग प्रदान करना।
- 2. शिक्षण:** शिक्षक की ऐसी व्यवस्था की जाए कि वे बालकों को पढ़ाएं, उन्हें विविध गतिविधियों में शामिल करें तथा मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रखें। उनके लिए व्हीलचेयर (पहियों वाली कुर्सी) की व्यवस्था करना। समुदाय के लोग ऐसे बालक के लिए सहयोगी बनें, ऐसा प्रयास करना।
- 3. आवास:** बालक, किसान और महिला के लिए ऐसा घर बनाए जाएं ताकि वे सरलता से घूम-फिर सकें। उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जाए ताकि वे व्हीलचेयर पर बैठे-बैठे चीज-वस्तुएं ले सकें। किसान के आवास में अनाज का संग्रह करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- 4. स्वसहाय समूह:** महिलाओं का स्वसहाय समूह बनाकर ऐसा महिला को उसका सदस्य नियुक्त करना। ऐसी व्यवस्था करना ताकि उस समूह में निर्णय प्रक्रिया में उसकी सक्रिय भूमिका हो।

आधारित पुनर्वास के लाभों की जानकारी प्रदान की थी:

- भारत में 1 करोड़ व्यक्ति नेत्रहीन हैं, जिनमें से 85 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं।
- भारत में विकलांगों के लिए 250 संस्थाएं कार्यरत हैं।
- गुजरात में अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर में अंधजनों और विकलांगों हेतु स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं।
- 45 वर्ष से ऊपर की आयु के अंधजन या विकलांग को संस्था में रखना मुश्किल है। अतः जरूरी है कि उनका समुदाय आधारित पुनर्वास हो।
- आज गुजरात में 3000 विकलांग बालक सामान्य विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं।
- समुदाय आधारित पुनर्वास में हर उम्र के व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है।
- यदि विकलांगों का समुदाय में ही पुनर्वास होता है तो ग्रामीण जनता का शहर की ओर पलायन घटता है। इसके अलावा, संस्था के निर्माण और संचालन का खर्च भी नहीं करना पड़ता।

- विकलांग व्यक्ति को कोई भी प्रशिक्षण देने से पहले उसकी भविष्य की उपयोगिता के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि ग्रामीण-विकलांग हो तो गांव की जरूरत और वातावरण के अनुरूप प्रशिक्षण देना चाहिए। उदाहरणार्थ, ग्रामीण विकलांग व्यक्ति को अगर कुर्सी बनाना सिखाएंगे तो शायद भविष्य में यह कला उसे गांव में अच्छी रोजी नहीं दे पाएगी।
- एक गांव में एक संस्था ने अंधजनों को पाय दान बनाने की रोजी दी। परंतु यह नहीं सिखाया कि उसके लिए कच्चा माल कहां से मिल सकता है। परिणामतः वह रोजी लंबे समय तक नहीं टिक सकी।

उपर्युक्त जानकारी प्रदान करने के बाद उन्होंने अंधजन मंडल की प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी दी। अंधजन मंडल निम्न प्रकार के पक्षों पर बल देता है:

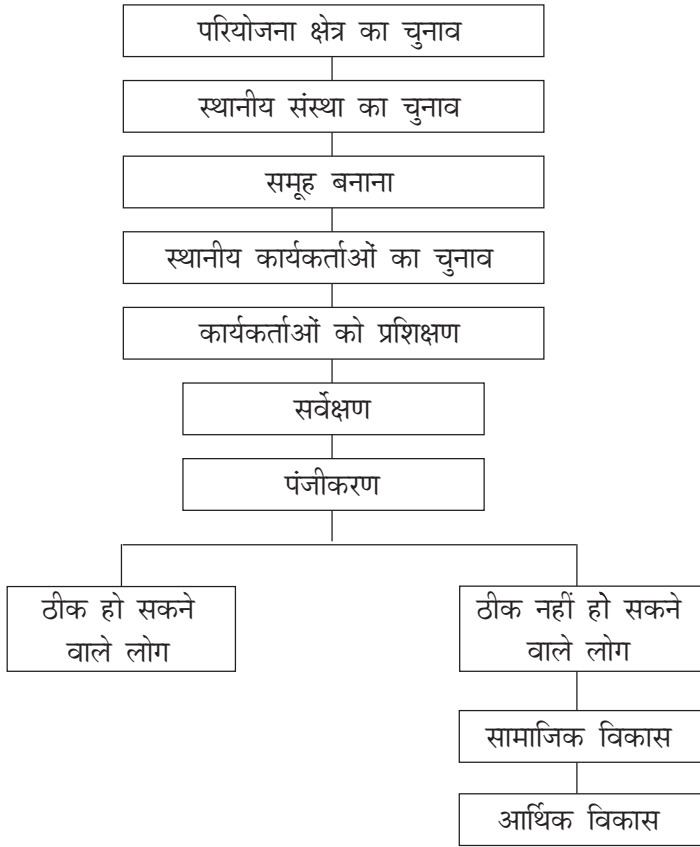
1. **अंधत्व निवारण:** अंधत्व निवारण के लिए मंडल नेत्र शिविर लगाता है। विटामिन 'ए' की गोलियां बांटता है। इसके अलावा, शिक्षकों के लिए जागृति कक्षाओं का आयोजन करता है। अहमदाबाद जिले की विरमगाम तहसील के 182 गांवों में केवल मांडल में अस्पताल होने से मंडल की प्रवृत्तियां वहां अत्यंत उपादेय सिद्ध हुई हैं।
2. **सामाजिक पुनर्वास:** मंडल हमेशा अंधजनों का समुदाय आधारित पुनर्वास पर बल देता है और इसके लिए निरंतर कार्यरत रहता है।
3. **आर्थिक पुनर्वास:** अंधजन अंधे होने से पहले जो व्यवसाय करते थे, उसी व्यवसाय में उन्हें फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जैसे बीड़ी या ईंटें बनाने वालों को उसी व्यवसाय में फिर से जुड़ने को तैयार किया जाता है।
4. **सहायक सेवाएँ:** मंडल अंधजनों को सरकार की सेवाओं का लाभ दिलाता है। उन्हें पेंशन दिलाने, एस.टी. बस का पास या पुस्तकें दिलाने में मदद दी जाती है। विकलांगों हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में मंडल सक्रियता से प्रयास करता है।
5. **पहली जांच:** बालक जन्म से ही अंधा हो तो उसे सबसे पहले जांचने के लिए मंडल जागरूक रहता है। इसका कारण यह है कि विकलांग व्यक्ति को उसकी आयु के मुताबिक बाल्यकाल

से ही प्रशिक्षित किया जाता है तो वह जल्दी ही स्वनिर्भर बन सकता है।

6. **जन जागृति:** कोई एक संस्था तमाम विकलांग व्यक्तियों तक नहीं पहुंच सकती। प्रत्येक संस्था अपनी क्षमता के आधार पर काम करती है। अतः अंधता के बारे में सच्ची जानकारी लोगों तक पहुंचाने तथा उनके पुनर्वास के लिए जागृति फैलाने के लिए मंडल द्वारा प्रदर्शन, निदर्शन और मेले आयोजित किए जाते हैं।
7. **संकलित शिक्षण योजना:** मंडल की संकलित शिक्षण योजना के तहत नेत्रहीन, मंदबुद्धि और बहरों-गूंगों आदि सभी बालकों को सामान्य विद्यालय में एक साथ ही पढ़ाया जाता है। फिर, गांव के विद्यालय में ही वही शिक्षकों के द्वारा उन बालकों को सभी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ऐसा सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि सभी विकलांग सामान्य विद्यालय में पढ़ सकते हैं। फिर भी अंधजनों के लिए सरकारी अधिकारियों का अभिगम उदासीन ही रहता है। इसी से अधिकारी यह मानकर चलते हैं कि इन लोगों को कोई काम करने की या शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

तदुपरान्त विशेषज्ञ व्यक्तियों ने अंधजन मंडल की कार्य पद्धति क्रमानुसार समझाई। अंधजन मंडल सर्वप्रथम अपना कार्य विस्तार पसंद करता है। कार्य विस्तार गुजरात में कहीं भी हो सकता है। चयनित तहसील को विविध समूहों में विभक्त किया जाता है। तहसील के प्रत्येक गांव को समीपवर्ती किसी केन्द्र का गांव पसंद करके उसे एक क्लस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे, विरमगाम तहसील में मालवण क्लस्टर। क्लस्टर तय कर लेने के पश्चात् स्थानीय स्वयंसेवकों का चुनाव किया जाता है। स्थानीय व्यक्ति अपने आसपास के गांवों का जानकार होता है। वह गांव के मार्गों से वाकिफ होता है। फिर, स्थानीय व्यक्ति को समुदाय जल्दी ही स्वीकार कर लेता है और उस पर विश्वास करता है। कार्यकर्ता के चयन पर मंडल बहुत ध्यान देता है, क्योंकि संस्था की सफलता स्थानीय कार्यकर्ता पर निर्भर करती है। मंडल के अनुभव के मुताबिक स्थानीय महिला कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाती हैं।

कार्यकर्ता के चयन के बाद उसे छह सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनमें से पांच सप्ताह के दौरान विकलांगता, अंधत्व, झामर



(ग्लुकोमा) मोतिये आदि की जानकारी दी जाती है। आंख के ऑपरेशन होते दिखाये जाते हैं। अंधे व्यक्ति का नाम लिखते समय गलत व्यक्ति का नाम न लिख दिया जाए, इस बारे में सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया। उसके पश्चात् एक सप्ताह तक क्षेत्र कार्य कराया जाता है। क्षेत्र-कार्य के दौरान कार्यकर्ता अंधजनों से मिलकर अधिक संवेदनशील होते हैं।

मंडल ने जब काम की शुरुआत की थी, तब कई गांवों की अंधी महिलाएँ लकड़ी पकड़ने में सकुचाती थी। परंतु महिला कार्यकर्त्रियों की अथाह मेहनत के सफल परिणामस्वरूप आज अंधी महिलाएँ बिना किसी संकोच के लकड़ी का सहारा लेती हैं। मंडल के सर्वेक्षण के समय बहुत से लोग अपने अंधे पुत्र-पुत्री के नाम नहीं लिखवाते, क्योंकि वे ऐसा मान बैठते हैं कि अंधता के कारण कोई उनसे विवाह नहीं करेगा। मंडल हमेशा समुदाय की भागीदारी और सहयोग से काम करता है। आज सम्पूर्ण भारत में विकलांगों के समुदाय आधारित पुनर्वास का प्रशिक्षण सिर्फ अंधजन मंडल में दिया जा रहा है। मंडल के संनिष्ठ प्रयासों के बाद आज अंधजन समुदाय में रहते हुए आत्मनिर्भर बने हैं। आज अंधजन सभी प्रकार के काम

आत्मविश्वासपूर्वक कर सकते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जी सकते हैं।

प्राकृतिक विपत्ति में विकलांगों के प्रति वैश्विक अभिगम
सत्र की शुरुआत दोपहर के भोजन से पहले हुई। विशेषज्ञ व्यक्तियों ने किन्हीं छह सहभागियों को स्वयंसेवक के रूप में आगे आने को कहा। तब उन छह में से दो सहभागियों की आंखों पर पट्टियाँ बांध दी गईं। उन्हें अंधा बना दिया गया। अन्य दो सहभागियों के हाथ बांध दिए गए। शेष सहभागियों में से एक का एक पैर और दूसरे के दोनों पैर बांध दिए गए। इसके बाद भोजन का विश्राम दिया गया। भोजन के दौरान और भोजन के बाद का सत्र शुरू होने से पहले इन छहों स्वयंसेवकों ने सत्र के समक्ष अपने अनुभव प्रस्तुत किए:

अंधे बने स्वयंसेवकों के अनुभव

- ऐसा लगा मानो अंधे में भोजन कर रहा हूँ।
- यह समझ में आया कि अंधजनों को कैसी तकलीफ होती होगी।
- दूसरों पर बराबर निर्भर रहना पड़ता, जो अच्छा नहीं लगा।
- सरलतापूर्वक घूम-फिर पाना संभव नहीं था।
- हालांकि, लोगों ने बहुद मदद की।

हाथ-विहीन स्वयंसेवकों के अनुभव

- दायां हाथ बंधा था अतः बायां हाथ अधिक क्रियाशील था। जिसके परिणामस्वरूप बायां हाथ बहुत दुखने लगा।
- दोनों हाथ बंधे थे अतः तमाम क्रियाएँ मुंह और पैरों से ही करनी पड़ीं।
- लिखने का पैड मुंह से उठाना पड़ा।
- दूसरे हाथ से भोजन ग्रहण करना पड़ा, जिससे बचपन याद आ गया।
- दोनों हाथ न हों तो बहुत कष्टदायक स्थिति है।
- बहुत लाचारी महसूस होती थी।



पैर-विहीन स्वयंसेवकों के अनुभव

- जब मांगी तभी मदद मिली।
- लोग मुझे बेचारी, लंगड़ी कहते थे, जो अच्छा नहीं लगा। यह बहुत अपमानजनक लगता था।
- अंधे व्यक्ति को देखकर लगा कि मेरी स्थिति उससे बहुत अच्छी है।
- अपंग लोगों के साथ थोड़ा काम किया है, परंतु जब खुद अपंग बने तो सच्ची परिस्थिति समझ में आई।
- किसी पर निर्भर रहना अच्छा नहीं लगता था।
- दोनों पैर न होने पर भी अपने आप पर विश्वास रखकर दैनिक क्रियाएँ करने का आनंद मिलता था।

सहभागियों के उपर्युक्त अनुभवों की प्रस्तुति के बाद विशेषज्ञ व्यक्तियों ने बताया कि विकलांग व्यक्ति सम्पूर्ण स्वावलंबी हो सकता है। अतः हमें उनकी क्षमताओं को कम करके नहीं आंकना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में काम करेंगे वहां कोई न कोई व्यक्ति तो विकलांग होगा ही। अपंगता बढ़ ही रही है। अपंगता और गरीबी एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और कुपोषण अपंगता के लिए उत्तरदायी बन सकते हैं। अपंगता के कारण गरीबी बढ़ती है। यों, यह चक्र चलता जाता है। हालांकि गरीब, मध्यम और उच्च - इन सभी वर्गों में अपंग व्यक्ति होते हैं। क्या हमें सभी वर्ग के अपंग व्यक्तियों के साथ काम करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में सहमति व्यक्त करते हुए सहभागियों ने कहा कि प्रत्येक वर्ग के विकलांग व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए। तदुपरांत विशेषज्ञ व्यक्तियों ने मानव-विकास को प्रभावित करने वाले परिबलों के बारे में बात बताई।

प्रत्येक व्यक्ति के विकास में निम्न परिबल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

1. **जन्मगत:** व्यक्ति की जाति, उम्र, परिवार, देश, संस्था और सामाजिक-आर्थिक बातों का उसके विकास पर असर होता है।
2. **वातावरण या परिवेश:** व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उसका उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जन्मगत और वातावरण-इन दो के सम्मिश्रण से हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। हम जो क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ करते हैं वे हमारे बाह्य परिवेश की परिणति

हैं। विकलांग बालक के लिए बाह्य वातावरण दो प्रकार से अवरोधक बन जाता है। एक शारीरिक और दूसरा सामाजिक तरीके से। उदाहरणार्थ, पोलियोग्रस्त बालक का विद्यालय तीसरी मंजिल पर हो तो वह उसके शिक्षण में बाधा बन सकता है। यह हुआ शारीरिक अवरोध। शिक्षक की और माता-पिता की वृत्ति बालक के प्रति उदासीनता की हो और बालक को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता हो तो यह एक बड़ा सामाजिक अवरोध है, और उसे दूर करने की जरूरत है।

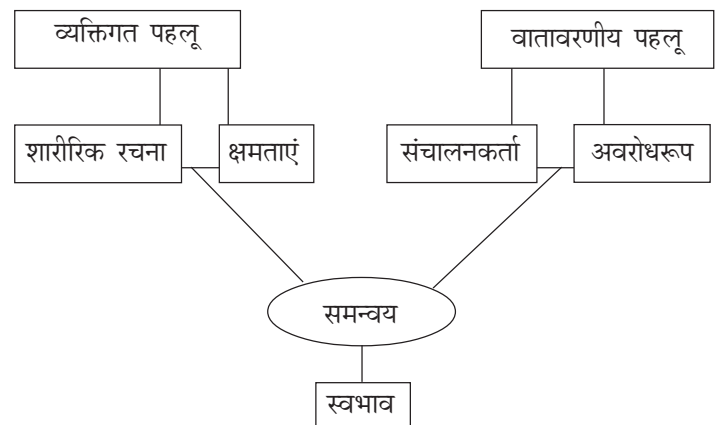
अपंगता को दूर करने के लिए सिर्फ चिकित्सकीय अभिगम पर्याप्त नहीं है। समाज का अभिगम सहयोगयुक्त हो, तभी अपंगता दूर हो सकती है। अपंगता सामाजिक प्रक्रिया है। हम भूकंप-संभावित क्षेत्र में रहते हैं, अतः हमें सुरक्षित स्थिति में रहना चाहिए। भूकंप को रोक पाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भूकंप से बचना तो हमारे हाथ में है। हम अपने बचाव की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे।

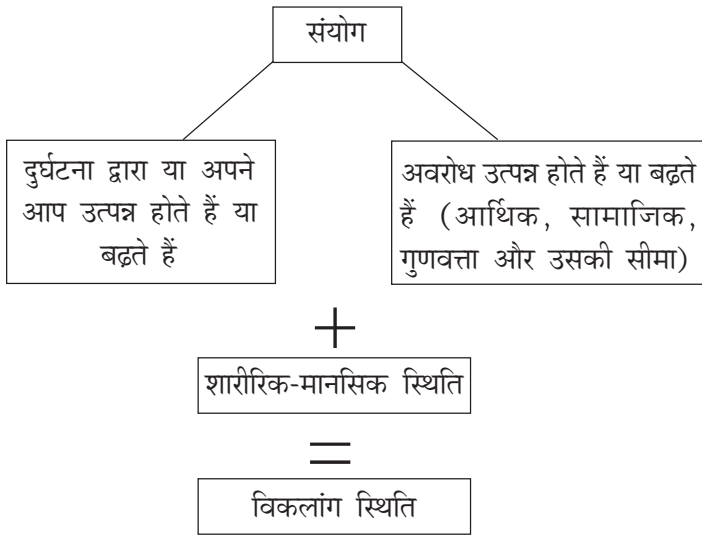
विकलांगता के सर्जक संयोग

विकलांगता को रोकने के लिए निम्न तीन स्तरों पर प्रयास होने चाहिए:

1. स्वास्थ्य, शिक्षा और टीकाकरण के द्वारा विकलांगता के खतरे दूर करना।
2. दुर्घटना या रोग की दशा में शारीरिक दुष्प्रभावों को उपचार के द्वारा कम करना तथा बाह्य वातावरण अनुकूल बनाना।
3. आपसी सामाजिक संकलन को प्रोत्साहन देना।
 - मात्र विकलांग व्यक्ति को ही नहीं, वरन् उसके परिवार तथा आसपास के लोगों को भी सहयोग प्रदान करने के लिए जोड़ा

मानव विकास का स्वरूप





जाना चाहिए। इसमें सामुदायिक कार्यकर्ताओं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों, फीजियोथेरेपिस्ट डॉक्टरों आदि का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

- निर्णय लेने की प्रक्रिया में हर चरण और हर स्तर पर विकलांग व्यक्तियों को अवसर देना चाहिए।
- विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को सक्रिय रहना चाहिए।

विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की संवेदनशीलता पर विशेषज्ञ व्यक्तियों ने बल दिया था तथा बाह्य परिवेश के व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझाया था। तदुपरांत सहभागियों को चार समूहों में बाँटकर निम्न विषय पर चर्चा आयोजित की गई थी:

1. 30 वर्षीया महिला - दोनों पैरों से अपंग - उसके पास साइकिल है।
2. 8 वर्षीय बालक - पोलियोग्रस्त - केवल हाथ का उपयोग कर सकता है।
3. 45 वर्षीय किसान - भूकंप में एक पैर कट गया है।

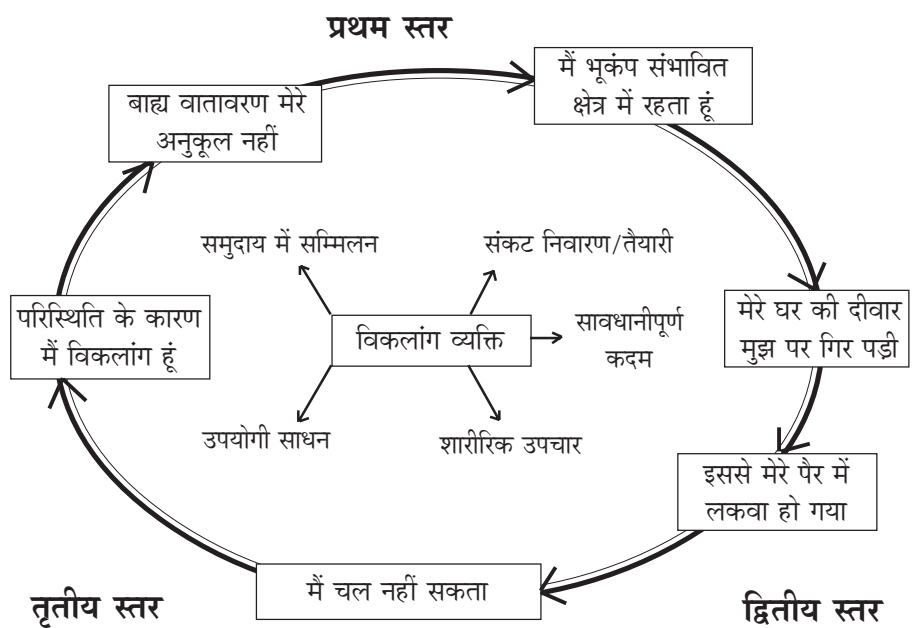
उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों के लिए चारों समूहों को निम्नानुसार चार प्रवृत्तियों आयोजित करने का निर्देश दिया गया था:

1. आमदनी उपार्जन
2. शिक्षण
3. आवास
4. स्वसहाय समूह

चारों समूहों ने चर्चा करके उपरोक्त महिला, बालक एवं किसान के लिए प्रवृत्तियों का आयोजन किया था। समूह चर्चा द्वारा तैयार की गई प्रवृत्तियों के बारे में टिप्पणी करते हुए विशेषज्ञ व्यक्तियों ने बताया कि विकलांगों हेतु ये सभी प्रवृत्तियाँ की जानी संभव हैं, यदि हम ऐसा मानते हैं, तो हमें भूकंप प्रभावित क्षेत्र की पुनर्वास प्रक्रिया में ये प्रवृत्तियाँ शुरू कर देनी चाहिए। विकलांगों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि विकलांगों की स्वयं के प्रति धारणा तथा लोगों की उनके प्रति धारणा बदलने की जरूरत है, विकलांगों के लिए अलग विद्यालय नहीं होने चाहिए। उनको सामान्य विद्यालयों में ही बैठने देना चाहिए। विकलांग बालक सामान्य शाला में पढ़ेगा तो दूसरे बालक सहज ही उसे अपना दोस्त बनाएंगे और वह मुख्य धारा में मिल सकेगा। हमें विकलांगों के प्रति दया दिखाने के बजाय उन्हें स्वनिर्भर बनाने के प्रयास करने चाहिए।

प्राकृतिक विपत्तियों में बालकों की स्थिति और उनकी विशेष जरूरतें

विशेषज्ञ व्यक्ति ने 'यूनिसेफ' की प्रवृत्तियों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की थी। यूनिसेफ प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति सुधारने, स्वैच्छिक संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करने तथा स्वास्थ्य के बारे में कार्यरत है। गुजरात में भूकंप के बाद प्रभावित समुदाय तक पहुंचने के उद्देश्य से कच्छ की भुज, रापर, भचाऊ और अंजार तहसीलों में योजना संचालित कर रहा है। विशेषज्ञ व्यक्ति ने यूनिसेफ का परिचय प्रदान



करने के बाद भूकंप के पश्चात् बालकों की स्थिति के बारे में बात शुरू की। इसके लिए सहभागियों को कुल तीन समूहों में बांटा गया। प्रत्येक समूह को निम्न प्रकार का एक प्रश्न देकर उस बारे में चर्चा के लिए कहा गया:

समूह-1 बालकों को भूकंप का आघात कैसा लगा?

समूह-2 भूकंप के बाद बालकों की प्रतिक्रिया कैसी है?

समूह-3 भूकंप के बाद बालकों की जरूरतें क्या हैं?

उपर्युक्त प्रश्नों के बारे में सहभागियों के तीनों समूहों ने चर्चा करके सभी ने फ्लिप चार्ट पर सामने प्रस्तुति दी।

परामर्श द्वारा समस्या का निवारण

तीसरे दिन के प्रथम सत्र में विगत दिनों का संक्षिप्त पुनरावर्तन करने के पश्चात् विशेषज्ञ व्यक्ति ने परामर्श (काउन्सेलिंग) के बारे में प्रस्तुति की। शुरूआत में बड़े समूह में सहभागियों के समक्ष यह सवाल प्रस्तुत किया गया था: 'क्या विवाह किए बगैर स्त्री-पुरुष एक साथ जीवन-यापन कर सकते हैं?'

सहभागियों ने उपर्युक्त प्रश्न पर अपने-अपने विचार रखते हुए गहन चर्चा की थी। चर्चा के उपरांत विशेषज्ञ व्यक्ति ने बताया था कि परामर्श देते समय परामर्शदाता को अपनी विचारधारा एक तरफ रखकर अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। अच्छे श्रोता में सुनने, समझने और स्वीकारने की क्षमता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में दूसरों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। प्रभावशाली परामर्श के बारे में समझाने हेतु विशेषज्ञ व्यक्ति ने सहभागियों को तीन-तीन के समूह में विभक्त होने का निर्देश दिया। तीन व्यक्तियों में से एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा निरीक्षण करने वाला था। कार्यशाला की शुरूआत में परिचय के समय बताए गए समूह के प्रत्येक व्यक्ति को बारी-बारी से तीनों भूमिकाएं (वक्ता, श्रोता, निरीक्षणकर्ता) अदा करनी थीं। इसके लिए कुल 15 मिनट की समयावधि दी गई थी। वक्ता को पांच मिनट में अपने जीवन के बारे में कोई बात कहने का निर्देश दिया गया था। इस समूह प्रक्रिया के अंत में सहभागियों ने अपने अनुभव प्रस्तुत किए थे। सहभागियों द्वारा प्रस्तुत मुद्दे पर चर्चा के बाद विशेषज्ञ व्यक्ति ने एक सहभागी के साथ प्रस्तुत काउन्सेलिंग के दो निर्देशन आयोजित किए थे। सहभागियों ने उसका अवलोकन किया और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

परामर्श के बारे में ध्यान देने लायक बातें

1. मन में ऐसा भाव न रहे कि परामर्शदाता (काउन्सेलर) के रूप में महानता व्यक्त करनी है। 'मैं अहमदाबाद से आपकी मदद के लिए आया हूँ।' ऐसा वाक्य आपकी महानता दर्शाता है, अतः ऐसे वाक्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
2. दुःखी व्यक्ति छोटा या नीचा है और काउन्सेलिंग करने वाला बड़ा और ऊँचा है, ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
3. दुःखी व्यक्ति के साथ अन्य दुःखी व्यक्ति के दुःख की तुलना नहीं करनी चाहिए। वह व्यक्ति दुःखी है, ऐसा हमें स्वीकारना चाहिए।

गीता बहन की बात

परिस्थिति-1

गीता बहन 30 बरस की हैं। वे कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। भूकंप में पैर पर दीवार गिर जाने के कारण उनका एक पैर काटा गया। उसकी जगह नकली पैर लगाया गया। अतः वे थोड़ा चल पाती थी। वे बैंक में नौकरी करती थी। बैंक तीसरी मंजिल पर था और टॉयलेट ठेठ नीचे था। परिणामतः मैनेजर ने उनसे कह दिया कि तुमसे नौकरी नहीं हो सकती। तुम घर बैठ जाओ। गीता बहन के माता-पिता ने भी उनसे घर में बैठने को कह दिया। जिस व्यक्ति की गीता बहन के साथ सगाई हुई थी उसने अपंगता के कारण सगाई तोड़ दी। गीता बहन ने घर, आफिस और जीवन-साथी का साथ खो दिया। उनकी जिंदगी एकाएक बदल गई। उनका बाह्य वातावरण अनुकूल न होने के कारण उनकी ऐसी दशा हुई। निम्नलिखित किस्से में उनका वातावरण सहयोगी था। अतः वे जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो सकीं।

परिस्थिति-2

अस्पताल के स्टाफ और गीता बहन के परिवार ने उन्हें सान्त्वना प्रदान की। उनमें अच्छी तरह से जी सकने की आशा जगाई। वे जहां नौकरी कर रही थीं, वहां के स्टाफ ने भी उनको झटपट फिर से काम पर आ जाने हेतु शुभकामनाएँ भेजीं। जिस युवक से गीता बहन की सगाई हुई थी, वह पहले तो बहुत हताश हो गया था। पर अब वह एकदम प्रसन्न है और गीता बहन से विवाह करने के लिए तैयार है। इस प्रकार गीता बहन के बाह्य परिवेश ने उनकी मदद की और वे नया जीवन पा सकीं। हमारे आसपास के लोग हमें प्रोत्साहन प्रदान करें, सहयोग प्रदान करें तो उसका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है।

4. हम समझाने की भावना से दुःखी व्यक्ति के पास जाते हैं। समझाने की भावना में सलाह का भाव आ जाता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि काउन्सेलर के नाते दुःखी व्यक्ति को हम समझाने या सलाह देने जा रहे हैं। वस्तुतः काउन्सेलिंग में सलाह देनी नहीं होती।
5. दुःखी व्यक्ति के दुःख की बात पूछी जानी चाहिए। हमें उसकी पीड़ा सुननी चाहिए। हमें उसको हमारे सामने अपना दुःख हल्का करने का अवसर देना चाहिए। उसे ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना चाहिए।
6. हमें अपनी मान्यताएं और विचार दूसरों पर नहीं थोपने चाहिए। हमें उनके कष्ट व तकलीफों में भागीदार बनना चाहिए।
7. दुःखी व्यक्ति को अपना दुःख प्रकट करते समय अत्यंत व्यथापूर्वक कहना चाहिए कि, 'बहुत दुःख हुआ', 'बहुत बुरा हुआ'। वैसे काउन्सेलर को स्वयं भावना में बहते हुए रोने नहीं लगना चाहिए।
8. किसी भी व्यक्ति का दुःख व्यक्त करने से हृदय का भार अवश्य हलका होता है।
9. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के बाद छह महीनों तक लोगों को अपनी दुःख भरी व्यथाएँ व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए।
10. काउन्सेलर को दुःखी व्यक्ति के साथ अपनी पहली मुलाकात में 30 से 45 मिनट का समय बिताना चाहिए।
11. कौंसिलिंग के समय काउन्सेलर को उचित ढंग से बैठना चाहिए। बार-बार हिलने-डुलने से या ज्यादा दूर-पास बैठने से काउन्सेलिंग में बाधा उत्पन्न होती है।
12. सुनने के लिए सिर्फ कान ही नहीं अपितु शारीरिक हाव-भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
13. काउन्सेलर को यह दर्शाना चाहिए कि वह हंकारा देकर, सिर हिलाकर तथा आंखों के हाव-भाव से स्वयं की बातों को सुन रहा है।
14. काउन्सेलर की वेशभूषा उचित होनी चाहिए।
15. जब सही मूड हो तभी काउन्सेलर को काउन्सेलिंग करनी चाहिए।

काउन्सेलिंग शुरू करने से पूर्व काउन्सेलर द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली बातें

1. काउन्सेलर को अपने शारीरिक हावभाव से दुःखी व्यक्ति का अभिनंदन करना चाहिए। सामान्य बातें करके उसे मानवीय

बालक और विपत्ति

- विपत्ति में बालकों की कई जरूरतें पूरी नहीं होतीं।
- दुनिया भर में शहरों में गलत रास्तों पर भटकते बालकों की आबादी बढ़ रही है। अतः आपत्ति के निवारण में बालकों के प्रति ध्यान दिए जाने की विशेष आवश्यकता है। ऐसे बालकों की तादाद बढ़े नहीं, इसके लिए उनके सामने उपस्थित खतरों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।
- बालकों को अपनी बात और अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर देने चाहिए।
- प्रभावित इलाकों में विद्यालय शीघ्र शुरू होने चाहिए।
- जिन बालकों ने विपत्ति के दौरान विनाश, चोटें या मृत्यु देखी है, ऐसे प्रभावित बालकों को व्यावसायिक उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। अपने बालकों के बारे में चिंतित माता-पिता को अपने निजी डाक्टर, बच्चों के डाक्टर या फिर मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए।

व्यवहार का एहसास कराना चाहिए। आरंभ के इस प्रथम चरण में पांच मिनट बिताने चाहिए।

2. दुःखी व्यक्ति जब अपना दुःख व्यक्त करे, तब उसी बात को हमें अपने शब्दों में दोहराना चाहिए। जैसे 'आपके पैर में बहुत दर्द होता है न!', 'पैर में बहुत पीड़ा होती है' आदि। इस चरण में 20 मिनट बिताने चाहिए।
3. दुःखी व्यक्ति जब भविष्य और भविष्य के आयोजन की बात करने लगे तो काउन्सेलर को यह समझ लेना चाहिए कि बात का अंत रहा है। उस समय सारी बातों को संक्षेप में दोहरा देना चाहिए।

काउन्सेलिंग के दौरान दुःखी व्यक्ति स्वयं ही अपनी समस्या के निवारण हेतु विकल्पों की बात करेगा। उन विकल्पों का उल्लेख करते हुए काउन्सेलर को उनमें से एक विकल्प को चुनने की बात दुःखी व्यक्ति के समक्ष करनी होगी। उदाहरणार्थ:

समस्या: माँ-विहीन बालक का क्या करें?

विकल्प: 1. बालक को पिता के पास रहने दें।

2. मौसी के पास छोड़ दें।

3. पिता दूसरा विवाह कर ले, ताकि बालक को नई माँ मिल जाए।

काउन्सेलर को दुःखी व्यक्ति को ऐसा एहसास कराना चाहिए कि कोई उसके साथ है। अपनी समस्या के निवारण के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ेगा, ऐसी बात काउन्सेलर को दुःखी व्यक्ति के समक्ष व्यक्त करनी चाहिए।

प्राकृतिक आपदा के समय कानून की स्थिति

विशेषज्ञ व्यक्ति ने सर्वप्रथम प्राकृतिक और मानवसर्जित आपदा की बात बताई। कानूनी बात बताने से पहले उन्होंने आपदा की दशा में सरकार के उत्तरदायित्वों के बारे में निम्न बातें बताई थी:

- सरकार आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजा दे, यह सरकार की कानूनी जवाबदारी है। सरकार प्रजा की पिता समान है। जो नागरिक (विधवा, अनाथ, अपंग आदि) अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, उनका उत्तरदायित्व वहन करना सरकार का कर्तव्य है। राहत और पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार की है। एक नागरिक के नाते हम सरकार से अपना अधिकार मांगते हैं, भीख नहीं मांगते।
- राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन की कोई नीति नहीं बनाई। वस्तुतः हर राज्य में 'डिज़ास्टर मैनेजमेंट पालिसी' होनी चाहिए।
- हमारे देश के संविधान की धारा-21 में कहा गया है, 'प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। कानूनी अधिकार के बिना किसी का जीवन नहीं छीना जा सकता।' इसमें मात्र सांस लेकर जीवित रहने की बात नहीं है, परंतु एक मनुष्य के नाते रोटी, कपड़े, मकान, प्राथमिक स्वास्थ्य, जल इत्यादि मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए जीने की बात है।
- कानून में कहा गया है कि आपदा के बाद यदि सरकार के पास पैसे हों, याने क्षमता हो तो उसे लोगों का पुनर्वास करना चाहिए। परंतु गुजरात के उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री बी. जे. दिवान ने भूकंप के बाद कोर्ट में सरकार के विरुद्ध किए गए केस में निम्न प्रकार के मुद्दे उठाए हैं:
 - क. आने वाली वित्तीय सहायता का कोर्ट को निरीक्षण करना चाहिए।
 - ख. निरीक्षण करने के लिए एक निष्पक्ष समिति बनाई जानी चाहिए।
 - ग. भूकंप पीड़ितों के लिए प्राप्त राशि किसी अन्य फंड में नहीं जानी चाहिए।

उपर्युक्त केस के संदर्भ में अदालत ने फरवरी में निम्न निर्णय दिया है:

- क. आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त राशि को अलग खाते में जमा किया जाए।
- ख. भूकंप पीड़ितों के लिए प्राप्त धन उन्हीं के लिए काम में लेना चाहिए।
- ग. कोई भी व्यक्ति इस बारे में सम्पूर्ण सूचनाएँ मांग सकता है।

उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ फरवरी के द्वितीय सप्ताह में जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में लोकपाल की व्यवस्था की गई। इसमें प्रभावित लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। अभी तक इस व्यवस्था के अधीन 11,000 प्रभावित लोगों ने क्षतिपूर्ति न मिलने के बारे में शिकायतें दर्ज कराई हैं। सामान्यतया वहां क्षतिपूर्ति और आवास संबंधी शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है। दिनांक 18-19 मई के दौरान भूकंपग्रस्त इलाकों के अवलोकन हेतु आए 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' के न्यायाधीश श्री वर्मा ने भी पुनर्वास के बारे में राज्य सरकार को कई निर्देश दिए थे। उपर्युक्त सूचना प्रदान करने के पश्चात् विशेषज्ञ व्यक्ति ने प्रभावित होने वाले लोगों के लिए उपयोगी कानूनी व्यवस्था की जानकारी प्रदान की थी।

विकलांग व्यक्ति सरकारी अस्पताल की लिफ्ट में व्हील चेयर के साथ जा सके, ऐसी लिफ्ट होनी चाहिए। हालांकि, निजी अस्पतालों पर यह कानून लागू नहीं है। विकलांग व्यक्ति को मुआवजा, हेल्पर के संग यात्रा करने का पास, सरकारी ऋण आदि लेने का अधिकार है। भूकंप से प्रभावितों के लिए कानूनी व्यवस्था की चर्चा के दौरान सहभागियों ने विशेषज्ञ व्यक्ति के समक्ष उलझन में डालने वाले प्रश्न प्रस्तुत किए थे। विशेषज्ञ व्यक्ति ने प्रत्येक प्रश्न की चर्चा की तथा उससे संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की थी। उसने न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर के फैसले का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जिम्मेदार है। सरकार के पास आर्थिक क्षमता न हो तो सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके बाद विशेषज्ञ व्यक्ति ने कच्छ में प्रभावित लोगों को कानूनी मार्गदर्शन और सहायता देने के उद्देश्य से शुरू हुए 'ह्यूमन राइट्स लॉ नटवर्क' के बारे में जानकारी

प्रदान की थी। यह नेटवर्क आदिपुर में कार्यरत है। यह लोगों को अलग-अलग कानूनों की जानकारी देगा तथा स्थानीय वकील तैयार करेगा।

वंचितों हेतु आवास

विशेषज्ञ व्यक्ति ने तीसरे सत्र की शुरुआत में भूकंप के बाद पुनर्वास प्रक्रिया के बारे में बात की। लातूर में आए भूकंप के बाद पुनर्वास प्रक्रिया अनेक वर्षों तक चली थी। विशेष रूप से स्थायी आवास का काम पूरा करने की चर्चा की जो लंबे समय तक काम चला था। ग्रामीण अंचलों में 70 से 75 प्रतिशत मकान लोगों द्वारा स्वयं बनाये हुए होते हैं। ग्रामीण मकान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से बने होते हैं। घरों पर प्लास्टर के बजाय स्थानीय माटी का लेपन किया होता है। जहां वर्षा अधिक होती है, वहां दो ढलानों के नीचे छपरे वाले मकान देखने में आते हैं। ऐसे घरों में श्रम का मूल्य आंकना चाहिए। ग्रामीण व्यक्ति अपनी आजीविका के अनुसार और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विस्तार दिए जाने जैसे घर बनाते हैं। अधिकांशतः खेती के काम से जब-जब फुरसत मिलती है तब धीमे-धीमे घर बनाये जाते हैं। ऐसे घरों का एक से अधिक उद्देश्य के लिए उपयोग होता है। कई घरों में रसोई, अनाज आदि संग्रहीत करने का स्थान और ढोरों को बांधने का स्थान एक साथ ही देखने को मिलता है। ऐसे घर का मूल्य हमें लगभग 800 रु. लगता है, पर उनके श्रम का मूल्य गिना जाए तो वह मकान 1600 रु. का होता है।

भूकंपग्रस्त लोगों को मकान की सहायता प्रदान करने वाली सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा अन्य व्यक्तियों को प्रभावित होने वाले लोगों के घर की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लातूर में एक कोयलानगर बनवाया गया था। उसकी जरूरतों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं पूछा गया था। परिणामस्वरूप चूल्हे पर खाना बनाने के अभ्यस्त उन प्रभावित लोगों के लिए स्टैंडिंग किचन बनवाये गए थे। वे खुले में निपटने के अभ्यस्त थे, फिर भी उन्हें अटेचड टॉयलेट वाले घर दिये गए थे। आज उन घरों में लोग अपने ढोर बांधते हैं, पर खुद नहीं रहते। हमें लोगों को पक्का मकान नहीं, वरन् भूकंप से सुरक्षित मकान देने की बात पर बल देना चाहिए। सीमेंट के प्रयोग से मकान मजबूत बन जाता है, ऐसा मानना गलत है। कई अंचलों में पेय जल की तंगी होती है, वहां सीमेंट के घरों

पर छिड़कने के लिए पानी कहां से मिलेगा? हमें लोगों को ही पूछना चाहिए कि वे अपने घर को फिर से किस तरह खड़ा करना चाहते हैं?

प्रभावितों के लिए एक आदर्श घर कैसा हो?

1. उनकी जरूरत के मुताबिक -
उदाहरणार्थ, बुनकर के लिए बनाये गए घर में बुनाई के काम के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसे में उनका कमरा 12 फीट के बजाय 18 फीट का होना चाहिए।
2. माल-सामान या मेहनत के रूप में उनका योगदान हो, ऐसा।
3. समुदाय के सामूहिक प्रयास से सभी के लिए बनाया गया।
4. भूकंप से सुरक्षित रह सके, ऐसा।

सूरत जिले की वालोड तहसील के गांवों में आदिवासियों को अपने घर बनाने के लिए लकड़ी लाने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा था। उन्होंने अपने बाड़े के नीलगिरी को काट कर अपने घर बनाए थे। उनके सामने उन्होंने ही पौधे लगाकर उन्हें विकसित किया था। प्रभावित लोगों के घर बनाते समय स्थानीय निर्माण-कार्य-सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। घर बनाने के लिए मौजूद श्रम, साधन व सूझ का उपयोग होना चाहिए। विशेषज्ञ व्यक्ति ने घर बनाने की प्रक्रिया और बने हुए घरों को महत्वपूर्ण बताया था। प्राकृतिक आपदा के पश्चात् सामान्यतया आवास बनाने की प्रक्रिया तीन तरह से होती है: 1. कोई एजेंसी (संस्था) द्वारा बनाये जाने वाले आवास, 2. बाजार-आधारित खड़े होने वाले आवास। प्राकृतिक आपदा के बाद ज्यादातर एजेंसियों या संस्थाओं द्वारा बनते मकान देखने में आते हैं। वे ग्रामवासियों के लिए हितकर नहीं हैं। एजेंसियाँ अपनी समझ के अनुसार मकान की डिज़ाइन बनाती हैं। कोई एजेंसी दो लाख रुपयों में 250 वर्ग फीट का मकान खड़ा कर देती है। परंतु उसमें रहने वाला किसान अपना अनाज कहां रखेगा, इस बारे में कोई विचार नहीं किया जाता। अतः विपत्ति के बाद की स्थिति में मकान-मालिक खुद ही अपना मकान बनाए, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मकान-मालिक द्वारा बनाए जाने वाले मकान की प्रक्रिया में इन बातों पर उसका नियंत्रण रहता है:

1. निर्माण कार्य हेतु सामग्री कहां से, किस भाव मिलेगी?
2. भविष्य में घर का विस्तार कैसे किया जाना है?

3. स्थानीय भवन-निर्माण कौशल उपलब्ध रहेगा। वे कौशल विकसित कर सकेंगे,
4. निर्माण-कार्य की तकनीक। यथा, पत्थर काम में लेना या ईंटें;
5. आर्थिक स्रोत। विशेषज्ञ व्यक्ति ने प्रक्रिया की बात बताने के पश्चात् मकान के बारे में प्रकाश डाला।

कच्चा घर और पक्का घर अर्थात् क्या?

घर की व्याख्या में कच्चे घर और पक्के घर - ऐसा कुछ नहीं कहा

जा सकता। भूकंप के दौरान बड़े मकान धराशायी हो गए और छोटे मकान ज्यों के त्यों खड़े हैं। तो कौनसा घर पक्का हुआ? विशेषज्ञ व्यक्ति ने घर की व्याख्या समझाते हुए घर के दो प्रकार बताए थे:

1. अधिक संभाल-व्यय वाले, 2. कम संभाल-व्यय वाले। प्रभावित लोगों के पास भवन-निर्माण सामग्री का कौशल है पर भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित मकानों के बारे में ज्ञान नहीं। अतः प्रभावित इलाके में कार्यरत स्वयंसेवकों को इससे संबंधित जानकारी हासिल करके प्रभावित अंचलों तक पहुंचानी चाहिए।

कार्यशाला के बाद सहभागियों द्वारा विकलांगों के समुदाय केन्द्रित पुनर्वास हेतु उठाए गए कदम

मीना परमार, 'सेवा' (अहमदाबाद)

प्रशिक्षण के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिन विकलांग व्यक्तियों के साथ हम काम करते हैं, उनको छोड़ नहीं देना चाहिए। सन् 1994 में दोनों पैरों से अपंग आशा बहन को ध्यान में रखकर साक्षरता के केन्द्र चलाये गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने केन्द्र में आना बंद कर दिया। अब हमने आशा बहन को साथ रख करके ही उनके इलाके में शिक्षण हेतु कक्षाएँ चलाने का काम किया है।

रजाक तुरिया, 'सेंट जेवियर्स सोशियल सर्विस सोसाइटी', कच्छ विकास ट्रस्ट (नलिया)

मैं रायघण में कार्यकर्ता के बतौर काम करता हूँ। वहाँ अंधे अपंग बालकों और प्रौढ़ वय के विकलांगों के पुनर्वास हेतु काम करता हूँ। समुदाय-केन्द्रित पुनर्वास के प्रशिक्षण के उपरांत मैंने अंधे व्यक्तियों को उनके पैरों पर खड़े करने का प्रयास किया है। आज वे खेती का काम कर सकते हैं और वाहनों में भी आ-जा सकते हैं।

नीला पटेल, 'गणतर' (अंजार)

वे विकलांग कार्यकर्ता को क्षेत्र कार्य हेतु वाहन में लेकर जाती थी अतः उनको वाहन-भत्ता देने का निर्णय लिया गया। उस समय अन्य कार्यकर्ताओं ने इस बारे में कोई विरोध नहीं किया, यही नहीं, वरन् अन्य कार्यकर्ताओं ने उसे स्वीकार कर लिया। यह विकलांग बहन बालकों को सिर्फ पढ़ाने का काम ही करती थीं। परंतु उन्हें सर्वेक्षण का काम भी सौंपा गया तो वे उस काम को भी उत्साहपूर्वक करने लगीं। इस तरह उनकी क्षमता का उन्हें पता लगा। लगता है, विकलांग लोगों को मौका देने की विशेष आवश्यकता है ताकि समाज भी उनकी क्षमताओं को पहचान सके।

कांति पटेल, 'प्रयास' (अंजार)

अंजार तहसील के सतापर गांव में एक विकलांग भाई को स्नेहकर्ता के रूप में दायित्व सौंपा गया। पहले तो वे मानते थे कि वे यह काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाद में पास के अस्वारिया गांव में तीन किलोमीटर चल कर गए और उन्होंने गांव की पेय जल की समस्या दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तहसील पंचायत में प्रस्तुति भी की तथा गांव में पानी का टैंकर ले आए।

जयंत भोजिया, 'उन्नति' (भचाऊ)

भचाऊ तहसील के वेर गांव की परवी बहन पक्षाघात की शिकार हो गईं। उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। वे ठीक हो रही थीं। उनके मन में सामान्य जीवन जी सकने की आशा विद्यमान थी। वे महिला कारीगरों के समूह में शामिल हुईं। वे कसीदाकारी के द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करना चाहती थी। 'उन्नति' उनकी तथा अन्य विकलांगों की सहायता कर रही है।

जिज्ञासा जोशी, 'महिला सामख्य-गुजरात' (अहमदाबाद)

महिला सामख्य की प्रवृत्तियों में विकलांग लोगों को समाविष्ट करने के कदम उठाये गए हैं। अंधजन मंडल के सहयोग से हमने काम करने की तैयारी की है।

सपना, 'सेवा अकादमी' (अहमदाबाद)

प्रशिक्षण लेने के बाद अकादमी की शोध इकाई से काउन्सेलिंग और विकलांगों के पुनर्वास के बारे में बात की। उनमें इस विषय को लेकर समझ उत्पन्न हुई। अंदरूनी गांवों में वे लोगों से रोजाना मिलती हैं और उनमें सहभागिता पैदा करने का प्रयास करती है।

घर बनाते समय ये मुद्दे ध्यान में रखने चाहिए:

1. घर की चारों दीवारें एक-दूसरे के साथ बंधी हुई या जुड़ी हुई होनी चाहिए।
2. दीवार का अंदर वाला और बाहर का भाग एक-दूसरे से सटा हुआ होना चाहिए। उनके बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए।
3. सभी तरह के घरों की छतें चारों दीवारों के साथ बंधी होनी चाहिए।
4. छत के सभी भाग (नलिये, बटनपट्टी, बल्ली आदि) एक-दूसरे के साथ बंधे होने चाहिए।

उपर्युक्त मुद्दों के बारे में चर्चा होने के बाद विशेषज्ञ व्यक्ति ने समुदाय आधारित आवास-निर्माण के चरण दर्शाए:

- सर्वप्रथम गांव के लाभार्थी का चयन करने हेतु बैठक की जाए। उसमें यह स्पष्ट किया जाए कि घर बनाने में संस्था की और लाभार्थी की भूमिका क्या रहे। इसके अलावा संस्था का और लाभार्थी का योगदान क्या रहेगा, यह भी तय कर लेना चाहिए।
- मान लें कि पांच लोगों के घर बनाने हैं तो वे पांचों व्यक्ति एक-साथ मिलकर बारी-बारी से एक-एक व्यक्ति का घर बनाने का जिम्मा ले लें।
- घर बनाने हेतु जरूरी निर्माण-सामग्री तय करना। इसके लिए खंडित घर की उपलब्ध सामग्री भी उपयोग में ले लें।
- घर की डिज़ाइन और उसकी गुणवत्ता के बारे में स्पष्टता कर लें। उपर्युक्त चरणों में एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किसी भी तरह की आवास की डिज़ाइन न ले जाएँ। हमें तो अपने आप चलने वाली आवास की प्रक्रिया को सिर्फ सहयोग देना है। जैसे, गांव में दो वृद्धों के घर ही बनाने हों तो हमें अपनी प्रक्रिया वहां से शुरू करनी चाहिए। सहभागी प्रक्रिया में कहा गया

है कि लोग जहां तक पहुंचे हैं, वहीं से प्रक्रिया शुरू की जाए। अगर पुनर्वास की प्रक्रिया समुदाय आधारित होगी तो लोग शांतिपूर्वक जी सकेंगे, अन्यथा वे अलग-थलग पड़ जाएंगे। स्थायी समाज बनाने हेतु समुदाय आधारित पुनर्वास का होना अत्यंत जरूरी है।

कार्यशाला के अंत में सहभागियों को अपने प्रश्न प्रस्तुत करने देने हेतु खुला सत्र आयोजित किया गया था। उसमें समस्त सहभागियों ने कार्यशाला के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की थीं:

- हम प्रभावित लोगों के लिए मात्र घर बनवाकर देने के बारे में ही जानते थे। समुदाय आधारित पुनर्वास के बारे में पहली बार जानकारी मिली और यह बहुत उपयोगी लगी।
- नये विषयों के बारे में जानने को मिला।
- पुनर्वास के काम को अब नयी दिशा मिली।
- दिन के दौरान देर तक सत्र चलते थे, जो लंबे लगते थे।
- पुनर्वास का काम करने की हिम्मत मिली।
- हमारा ज्ञान प्रखर हुआ।
- फॉलो-अप कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए।
- इस कार्यशाला का दूसरा चरण आयोजित करना चाहिए।
- अभी तक हम अपने लक्ष्य-समूह के साथ ही काम करते थे, परंतु अब समुदाय आधारित पुनर्वास की बात जानने को मिली।
- पुनर्वास में लोक-भागीदारी की बात बहुत पसंद आई।
- ऐसा शिविर हमारे वरिष्ठ व्यक्तियों हेतु होना चाहिए।
- कार्यशाला में सीखी बातें दूसरों को बतानी चाहिए।
- प्रभावी-पुनर्वास-प्रक्रिया की गहन जानकारी मिली।
- विकलांगों के साथ काम करना सीखने हेतु एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

पृष्ठ 22 का शेष भाग

यह अनिवार्य हो जाए। इसी भांति तहसील और जिला पंचायतों के प्रमुखों के चुनाव भी सीधे लोगों में से हो, ऐसी व्यवस्था की जाए।

2. सांसदों और विधानसभा के सदस्यों को तहसील और जिला पंचायत में मताधिकार के साथ नियुक्त करने का जो अधिकार राज्य विधानसभा को सौंपा गया है, वह रद्द होना चाहिए। कम से कम उन्हें मत देने का अधिकार तो नहीं

होना चाहिए। अगर सांसदों और विधान सभा सदस्यों को तहसील और जिला पंचायतों की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा तो जो सीधे जनता के द्वारा पंचायतों में सदस्य के रूप में चुने गए हैं, उनका पंचायतों में होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।

3. तीनों स्तरों की पंचायतों के सभी सदस्यों के चुनाव लोगों में से होने की जो व्यवस्था है वह चालू ही रहनी चाहिए।

યુ.એન.ડી.પી.ના માનવ વિકાસના આંકનું વિવેચન

સંદર્ભ

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ(યુનાઈટેડ નેશન ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ યુ.એન.ડી.પી.) વિકસતા દેશોને ટેકનિકલ સહાય આપવામાં સૌથી મોખરે છે. તેનું વાર્ષિક અંદાજપત્ર આશરે એક અબજ ડોલરનું છે અને તે દુનિયાભરમાં તેની ૧૩૬ જેટલી કચેરીઓ ધરાવે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગરીબીની નાબૂદી, રોજગારીનું સર્જન, પર્યાવરણનું પુનર્સર્જન અને મહિલાઓનો વિકાસ છે. યુ.એન.ડી.પી. દ્વારા ૧૯૯૦થી માનવ વિકાસ અંગે એક વાર્ષિક અહેવાલ બહાર પડે છે. આ અહેવાલમાં દુનિયાના દેશોના માનવ વિકાસ અંગેના પ્રશ્નો તેમ જ અભિગમની

ચર્ચા કરવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે માનવ વિકાસના કેટલાક આંક(ઈન્ડેક્સ) વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવે છે. આ અહેવાલોમાં દર વર્ષે માનવ વિકાસના કોઈ એક ખાસ પાસા ઉપર લંબાણથી ચર્ચા કરવામાં આવે છે. જેમ કે, ૧૯૯૫માં સ્ત્રી-પુરુષના તુલનાત્મક વિકાસની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ૧૯૯૬માં આર્થિક વિકાસ અને માનવ વિકાસના સંબંધોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. અને ૧૯૯૭માં વિશ્વવ્યાપી ગરીબી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ બધી ચર્ચાઓ દ્વારા યુ.એન.ડી.પી.એ માનવ કેન્દ્રિત ટકાઉ વિકાસના અભિગમને રજૂ કર્યો છે જે ઘણું નોંધપાત્ર છે.

સ્ત્રીઓના માનવ વિકાસના જુદા જુદા ક્ષેત્રીય આંકો પ્રમાણે ગુજરાતના જિલ્લાઓનો અનુક્રમ : વ્યક્તિગત પરિબલો

અનુ.નં.	જિલ્લો	આવક આંક	શિક્ષણનો આંક	તંદુરસ્તીનો આંક	રહેણાંકનો આંક	માનવહક્કનો આંક	સંયુક્ત આંક
૧.	અમદાવાદ	૧૮	૫	૧૨	૨	૭	૫
૨.	અમરેલી	૧	૬	૮	૧૦	૯	૩
૩.	બનાસકાંઠા	૧૨	૧૯	૧૫	૧૯	૨	૧૮
૪.	ભરૂચ	૧૪	૪	૧૪	૪	૧૮	૧૨
૫.	ભાવનગર	૬	૧૬	૭	૧૨	૧૭	૧૪
૬.	ડાંગ	૯	૧૭	૧૬	૧૪	૭	૧૬
૭.	ગાંધીનગર	૧૯	૧	૨	૧	૧૩	૧
૮.	જામનગર	૧૧	૧૨	૧૧	૯	૧૬	૧૩
૯.	જૂનાગઢ	૨	૨	૫	૧૩	૧૨	૨
૧૦.	કચ્છ	૧૩	૧૪	૧૭	૫	૧૧	૧૫
૧૧.	ખેડા	૧૬	૮	૧૦	૩	૬	૬
૧૨.	મહેસાણા	૪	૧૦	૧૩	૬	૮	૮
૧૩.	પંચમહાલ	૫	૧૮	૧૮	૧૬	૩	૧૭
૧૪.	રાજકોટ	૮	૧૧	૯	૭	૧૪	૯
૧૫.	સાબરકાંઠા	૭	૧૩	૩	૧૧	૫	૭
૧૬.	સુરત	૧૭	૩	૪	૧૭	૧૦	૧૧
૧૭.	સુરેન્દ્રનગર	૩	૧૫	૧૯	૧૫	૧૯	૧૯
૧૮.	વડોદરા	૧૫	૯	૬	૮	૧૫	૧૦
૧૯.	વલસાડ	૧૦	૭	૧	૧૮	૧	૪

પુરુષોના માનવ વિકાસના જુદા જુદા ક્ષેત્રીય આંકો પ્રમાણે ગુજરાતના જિલ્લાઓનો અનુક્રમ : વ્યક્તિગત પરિબલો

અનુ.નં.	જિલ્લો	ગરીબીનો આંક	શિક્ષણનો આંક	તંદુરસ્તીનો આંક	રહેણાંકનો આંક	માનવહક્કનો આંક	સંયક્ત આંક
૧.	અમદાવાદ	૮	૭	૧૫	૨	૧૫	૭
૨.	અમરેલી	૩	૧૦	૭	૧૦	૫	૩
૩.	બનાસકાંઠા	૯	૧૮	૧૦	૧૯	૪	૧૬
૪.	ભરુચ	૧૪	૪	૧૮	૪	૧૧	૧૪
૫.	ભાવનગર	૨	૧૬	૫	૧૨	૧૦	૬
૬.	ડાંગ	૧૯	૧૯	૧૩	૧૪	૭	૧૮
૭.	ગાંધીનગર	૧૬	૧	૬	૧	૧૪	૫
૮.	જામનગર	૫	૧૨	૨	૯	૮	૨
૯.	જૂનાગઢ	૧	૩	૧	૧૩	૧૮	૧
૧૦.	કચ્છ	૭	૧૩	૧૬	૫	૧૨	૧૧
૧૧.	ખેડા	૧૮	૨	૧૨	૩	૩	૮
૧૨.	મહેસાણા	૧૧	૬	૧૧	૬	૬	૯
૧૩.	પંચમહાલ	૧૭	૧૭	૧૯	૧૬	૧	૧૯
૧૪.	રાજકોટ	૪	૯	૪	૭	૧૭	૪
૧૫.	સાબરકાંઠા	૧૨	૫	૮	૧૧	૨	૧૦
૧૬.	સુરત	૧૩	૧૧	૧૪	૧૭	૧૬	૧૭
૧૭.	સુરેન્દ્રનગર	૬	૧૫	૧૭	૧૫	૧૩	૧૩
૧૮.	વડોદરા	૧૦	૮	૯	૮	૧૯	૧૨
૧૯.	વલસાડ	૧૫	૧૪	૩	૧૮	૯	૧૫

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમના આ અહેવાલોમાં વિશ્વના ૧૭૫થી પણ વધુ દેશો માટે મુખ્યત્વે નીચેના વિકાસના આંકો દર વર્ષે બહાર પડે છે :

૧. માનવ વિકાસનો આંક (હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઈન્ડેક્સ), જેમાં માનવ વિકાસનાં મહત્વનાં પાસાઓને માપવામાં આવે છે (આવક, તંદુરસ્તી અને શિક્ષણ). ૨. લિંગ સબંધી વિકાસ આંક (જેન્ડર રિલેટેડ ડેવલપમેન્ટ ઈન્ડેક્સ), જેમાં સ્ત્રી-પુરુષના વિકાસનું તુલનાત્મક માપન કરવામાં આવે છે. ૩. લિંગ સબંધી સક્ષમતા આંક (જેન્ડર એમ્પાવરમેન્ટ મેઝર), જેમાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષોની સક્ષમતાનું તુલનાત્મક માપન કરવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત, ૧૯૯૭થી માનવ ગરીબીનો આંક (હ્યુમન પોવર્ટી ઈન્ડેક્સ) પણ બહાર પાડવામાં આવે છે, જેને આધારે જુદા જુદા દેશોની ગરીબીની પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવે છે.

વિશ્વના દેશો માટે અને ખાસ તો વિકસતા દેશો માટે ઉપરોક્ત

અહેવાલો તેમ જ માનવ વિકાસના આંકો ઘણા મહત્વના છે. તેઓ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે, રાષ્ટ્રીય આવક કે રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન કરતાં પણ માનવ વિકાસ ઘણો મહત્વનો છે. રૂઢિગત અર્થશાસ્ત્રીઓ રાષ્ટ્રીય આવકના વધારાના દરને ઘણું મહત્વ આપે છે અને તે જ વિકાસનું ધ્યેય છે તેમ માને છે. પરંતુ આ અહેવાલો પ્રતિપાદિત કરે છે કે, ફક્ત આર્થિક વિકાસ માનવ વિકાસ માટે મદદરૂપ થતો નથી. અને ખરું કહીએ તો, ઘણી વાર આર્થિક વિકાસ જોબલેસ (રોજગારી વિનાનો), રુથલેસ (ગરીબો તરફ ફૂરતાભર્યો), રુટલેસ (મજબૂત પાયા વિનાનો), વૉઈસલેસ (ગરીબોના અવાજ વિનાનો), અથવા તો પોઈન્ટલેસ (સ્પષ્ટ હેતુ વિનાનો) હોય છે. આવો વિકાસ ગમે તેટલો ઊંચો હોય તો પણ માણસોના વિકાસને આગળ વધારતો નથી. જે આર્થિક વિકાસ માનવ વિકાસને મદદ કરે છે, તે જ ટકાઉ અને તંદુરસ્ત હોય છે.

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમના આ વાર્ષિક અહેવાલોનું મહત્વ ઘણું

માનવ વિકાસના જુદા જુદા ક્ષેત્રીય આંકો પ્રમાણે ગુજરાતના જિલ્લાઓનો અનુક્રમ : વ્યક્તિગત પરિબળો

અનુ.નં.	જિલ્લો	આવકનો આંક	શિક્ષણનો આંક	તંદુરસ્તીનો આંક	રહેણાંકનો આંક	માનવહક્કનો આંક	સંયુક્ત આંક
૧.	અમદાવાદ	૧૧	૬	૧૨	૮	૮	૫
૨.	અમરેલી	૨	૭	૭	૧૦	૮	૩
૩.	બનાસકાંઠા	૮	૧૮	૧૩	૧૮	૨	૧૮
૪.	ભરુચ	૧૬	૫	૧૭	૪	૧૫	૧૪
૫.	ભાવનગર	૩	૧૬	૪	૧૨	૧૪	૮
૬.	ડાંગ	૧૫	૧૮	૧૫	૧૪	૬	૧૭
૭.	ગાંધીનગર	૧૮	૧	૩	૧	૧૨	૨
૮.	જામનગર	૬	૧૩	૫	૮	૧૩	૬
૯.	જૂનાગઢ	૧	૨	૨	૧૩	૧૭	૧
૧૦.	કચ્છ	૭	૧૫	૧૬	૫	૧૧	૧૩
૧૧.	ખેડા	૧૮	૩	૧૧	૩	૫	૭
૧૨.	મહેસાણા	૮	૮	૧૪	૬	૭	૮
૧૩.	પંચમહાલ	૧૩	૧૭	૧૮	૧૬	૧	૧૮
૧૪.	રાજકોટ	૪	૧૧	૬	૭	૧૮	૪
૧૫.	સાબરકાંઠા	૧૨	૧૦	૮	૧૧	૩	૧૦
૧૬.	સુરત	૧૭	૪	૧૦	૧૭	૧૦	૧૫
૧૭.	સુરેન્દ્રનગર	૫	૧૪	૧૮	૧૫	૧૬	૧૬
૧૮.	વડોદરા	૧૦	૮	૮	૮	૧૮	૧૨
૧૯.	વલસાડ	૧૪	૧૨	૧	૧૮	૪	૧૧

છે તેમાં કોઈ શંકા નથી. પરંતુ આ અહેવાલોમાં માનવ વિકાસને જે રીતે માપવામાં આવે છે તે સંતોષજનક જણાતું નથી. એમ લાગે છે કે માનવ વિકાસને માપવાની પદ્ધતિઓ વિકસિત દેશોના આર્થિક વિકાસના અભિગમને તેમ જ તેમનાં વિકાસનાં મૂલ્યોને વધારે અનુરૂપ છે. દક્ષિણના વિકસતા દેશોને માટે આ માપવાની પદ્ધતિઓ અને આંકો બહુ અનુરૂપ નથી. વિકાસના આંકની આ મર્યાદાઓને લીધે તે દક્ષિણ અને ઉત્તરના દેશોની વાસ્તવિક તુલનાત્મક પરિસ્થિતિને દર્શાવી શકતા નથી. અમારું એવું માનવું છે કે, વિકાસનું માપન જરા જુદી રીતે થવું જોઈએ જેથી દુનિયાના બધા દેશોના માનવ વિકાસને વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં માપી શકાય તેમ જ તેમનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી શકાય.

યુ.એન.ડી.પી.ના માનવ વિકાસના આંકની કેટલીક મર્યાદાઓ

યુ.એન.ડી.પી. દ્વારા માનવ વિકાસની જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે તે અત્યંત યોગ્ય છે. માનવ વિકાસ એટલે જીવનમાં મળતી તકોના વિસ્તારની પ્રક્રિયા કે જેથી માનવો પોતાની સુષુપ્ત શક્તિઓનો પૂર્ણ રીતે ઉપયોગ કરીને જીવનમાં વિકાસ કરી શકે. આ વ્યાખ્યા સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે, આર્થિક વિકાસ અને માનવ વિકાસ એ બે જુદી પ્રક્રિયાઓ છે. અને એકની પ્રાપ્તિ થવાથી બીજાની તરત પ્રાપ્તિ થાય તે જરૂરી નથી. કમનસીબે આવી સુંદર વ્યાખ્યાને માપવા માટે બનાવવામાં આવેલો માનવ વિકાસનો આંક ઘણો નબળો છે.

માનવ વિકાસનો આ આંક ફક્ત ત્રણ પરિબળો માપે છે: ક. તંદુરસ્તી કે જે જન્મ વખતે અપેક્ષિત આયુષ્યને આધારે માપવામાં

આવે છે. ખ. શિક્ષણ કે જે સાક્ષરતા તેમ જ નિશાળે જનારાં બાળકોના ટકા દ્વારા માપવામાં આવે છે. અને ગ. પ્રતિવ્યક્તિ આવક કે જે વ્યક્તિનાં સાધનો ઉપરનો અંકુશ આપે છે.

આ પરિબલોમાં રહેલા અંગેની પરિસ્થિતિ, રોજગારી કે બેરોજગારી, આર્થિક ગરીબી, સલામતી અને સુરક્ષા, માનવ અધિકારો વગેરે કોઈ પણ પરિબલોને કે જે વિકાસની તકો પર અસર કરે છે તેમને ગણવામાં આવ્યાં નથી. આના લીધે માનવ વિકાસનો આંક વ્યાખ્યાની તુલનામાં ઘણો સંકુચિત બની ગયો છે.

જો માનવ વિકાસ જીવનમાં મળતી વિકાસની તકો અંગે નિર્દેશ કરતી હોય તો, ફક્ત વ્યક્તિગત પરિબલોને આધારે તે માપવો એ પૂરતું

નથી. કારણ કે, વિકાસની તકો વ્યક્તિગત ઉપરાંત સામગ્રિક પરિબલો ઉપર પણ આધાર રાખે છે. દા.ત. પર્યાવરણ વિકાસની તકો પર ઘણી અસર કરે છે. કથળેલું પર્યાવરણ કે જ્યાં પ્રદૂષણ, પાણીની તંગી કે દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ હોય તો તેની લોકોના વિકાસ પર માઠી અસર પડે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં લોકો સ્થળાંતર પણ કરી જાય છે. તેને લીધે તેમની તંદુરસ્તી, શિક્ષણ તેમ જ એકંદર વિકાસ પર પણ ખરાબ અસર પડવાની સંભાવના છે. આ જ પ્રમાણે પ્રાદેશિક અસમાનતા તેમ જ વિકૃત આર્થિક વિકાસ માનવોને મળતી તકો પર અસર કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વ્યક્તિગત પરિબલો ઉપરાંત, વ્યાપક (મેકો) પરિબલો પણ માનવને પ્રાપ્ત થતી તકો પર અસર કરે છે. કમનસીબે માનવ વિકાસના આંકોમાં આ પરિબલોનું કોઈ માપન નથી.

માનવ વિકાસના જુદા જુદા ક્ષેત્રીય આંકો પ્રમાણે ગુજરાતના જિલ્લાઓનો અનુક્રમ:સામગ્રિક પરિબલો

અનુ.નં.	જિલ્લો	આવકનો આંક	શિક્ષણનો આંક	તંદુરસ્તીનો આંક	રહેણાંકનો આંક	માનવહક્કનો આંક
૧.	અમદાવાદ	૩	૯	૧૭	૩	૯
૨.	અમરેલી	૧૨	૧૫	૧૫	૯	૧૬
૩.	બનાસકાંઠા	૧૮	૧૨	૭	૮	૧૪
૪.	ભરુચ	૯	૧૧	૫	૧૯	૧૦
૫.	ભાવનગર	૧૧	૧૦	૧૨	૬	૧૧
૬.	ડાંગ	૧૪	૧૭	૧	૧	૭
૭.	ગાંધીનગર	૧	૧	૧૯	૧	૧
૮.	જામનગર	૧૬	૧૩	૧૩	૧૦	૧૫
૯.	જુનાગઢ	૧૩	૮	૧૪	૧૮	૧૨
૧૦.	કચ્છ	૧૯	૧૭	૧૧	૧૬	૧૯
૧૧.	ખેડા	૨	૧	૮	૪	૨
૧૨.	મહેસાણા	૮	૫	૧૬	૫	૬
૧૩.	પંચમહાલ	૧૭	૧૬	૨	૧૩	૧૩
૧૪.	રાજકોટ	૭	૧૪	૧૮	૧૧	૧૮
૧૫.	સાબરકાંઠા	૧૦	૪	૪	૧૨	૩
૧૬.	સુરત	૬	૧	૬	૧૫	૪
૧૭.	સુરેન્દ્રનગર	૧૫	૧૭	૧૦	૧૪	૧૭
૧૮.	વડોદરા	૫	૬	૯	૧૭	૮
૧૯.	વલસાડ	૪	૭	૩	૭	૫

માનવ વિકાસના આંકની ત્રીજી મર્યાદા એ છે કે, જાણે કે અજાણે એ માનવ વિકાસને આર્થિક વિકાસને વધારવાના એક સાધનરૂપે જ જુએ છે. દાખલા તરીકે, સારી તંદુરસ્તી કે સારું શિક્ષણ શ્રમની ઉત્પાદકતામાં વધારો કરે છે અને રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન વધારે છે. એ વાત માનવ વિકાસના આંકની નીચે ધરવામાં આવી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ આંક ઉત્તરના દેશોના વિકાસનાં સ્થાપિત મોડેલોની તરફેણ કરે છે. અને માનવ વિકાસને આ સ્થાપિત મોડેલોથી સ્વતંત્ર રીતે જોતું નથી. દરેક વાર્ષિક અહેવાલમાં માનવ કેન્દ્રિત વિકાસના નવા પેરેડાઈમનાં જુદાં જુદાં પાસાંઓની ચર્ચા કર્યા પછી પણ યુ.એન.ડી.પી. માનવ વિકાસને સ્થાપિત વિકાસનાં મોડેલોની છત્રછાયા નીચે જ જુએ છે એ ખરેખર કમનસીબ છે.

ગરીબ દેશોના મુખ્ય બે પ્રશ્નો છે : ગરીબી/બેકારી અને અસમાનતા. આ બંને પ્રશ્નો માનવ વિકાસને ઘણો મર્યાદિત બનાવી દે છે. પરંતુ, યુ.એન.ડી.પી.ના આંકોમાં આ બંને બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. પ્રતિવ્યક્તિ આવક ગણી છે પણ તે દ્વારા આવકની અસમાનતાનો કે શોષણનો ખ્યાલ આવતો નથી. અસમાન આવક નીચલા વર્ગોનું શોષણ થતું હોવાનો નિર્દેશ કરે છે. તે જ રીતે, વિકસેલા વિસ્તારો અને ખાસ તો શહેરો પછાત વિસ્તારોનું અને ગામડાંઓનું શોષણ કરે છે. પછાત વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોના વિકાસ પર આની માઠી અસર પડે છે. આ બધાં માળખાકીય પરિબલો માનવ વિકાસના આંકોમાં ક્યાંય નોંધવામાં આવ્યાં નથી. અને છેવટે, યુ.એન.ડી.પી.એ શિક્ષણ અને તંદુરસ્તીના માપકો પણ યોગ્ય રીતે પસંદ કર્યાં નથી એમ લાગે છે. લોકોની તંદુરસ્તી ફક્ત જન્મ વખતે અપેક્ષિત આયુષ્ય દ્વારા માપી શકાય નહીં. તંદુરસ્તી માપવા માટે રોગચાળાનું પ્રમાણ, બાળકોનો મૃત્યુ દર, માતાઓનો મૃત્યુ દર પણ એટલાં જ મહત્વનાં છે. શિક્ષણની બાબતમાં પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ અંગેના આંકડાઓનો તેમ જ ટેકનિકલ શિક્ષણ અંગેના આંકડાઓનો ઉપયોગ થવો જોઈએ કારણ કે, તો જ શૈક્ષણિક પ્રાપ્તિની યોગ્ય માપણી થઈ શકે. પ્રતિ વ્યક્તિ આવકને બદલે ગરીબીનો દર પણ વાપરી શકાય. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, શિક્ષણ, તંદુરસ્તી અને આવકના માપકો પણ યોગ્ય રીતે પસંદ કરાયા નથી તેમ લાગે છે.

લિંગ સંબંધી સક્ષમતાના આંક તેમ જ લિંગ સંબંધી માનવ વિકાસના આંકની બાબતમાં પણ કેટલીક મર્યાદાઓ જોવા મળે છે. ગરીબ દેશોની સ્ત્રીઓની ખાસ પરિસ્થિતિનો અહીં ખ્યાલ કરાયો નથી. દાખલા તરીકે, સ્ત્રીઓની સક્ષમતા તેમની સંસદમાં સંખ્યા ઉપરથી કે મેનેજરોના હોદ્દા ઉપર તેમની ટકાવારી દ્વારા માપી શકાય નહીં. ગરીબ દેશોમાં તેમની સક્ષમતા માપવા માટે સ્ત્રીઓની પંચાયતોમાં ભાગીદારી, સહકારી મંડળીઓમાં ભાગીદારી, યુનિયનોમાં ભાગીદારી

તેમ જ અન્ય આર્થિક તેમ જ રાજકીય સંગઠનોમાં ભાગીદારી જોવી જોઈએ. જે દેશોમાં ૧ ટકા કરતાં ઓછી સ્ત્રીઓ ઉચ્ચ કક્ષાની નોકરીઓમાં ભાગ લેતી હોય ત્યાં તેમની સક્ષમતા ફક્ત ઉચ્ચ કક્ષાની નોકરીઓમાં તેમની ભાગીદારીને આધારે માપી શકાય નહીં. આ ઉપરાંત સ્ત્રીઓમાં વિકાસની તકો પર તેમની સુરક્ષા અંગેની પરિસ્થિતિ તેમ જ સમાજની પુરુષપ્રધાનતા પણ અસર કરે છે. પરંતુ આ પરિબલોનો સ્ત્રીઓના વિકાસના આંકમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી.

માનવ વિકાસનો વૈકલ્પિક આંક (હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ મેઝર)

યુ.એન.ડી.પી.ના માનવ વિકાસના આંકોની મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં લેતાં એમ લાગે છે કે, વિકસિત તેમ જ અવિકસિત દેશોમાં માનવ વિકાસ તેમ જ લિંગ સંબંધી વિકાસને માપવા માટે વૈકલ્પિક આંકોની જરૂર છે. આ આંકો નીચે પ્રમાણે હોવા જોઈએ :

અ. વ્યક્તિગત પરિબલો

૧. પ્રતિ વ્યક્તિ આવક અને અથવા ગરીબીનો આંક. ૨. તંદુરસ્તી તેને માપવા માટે માતાનો મૃત્યુ દર, બાળકોનો મૃત્યુ દર, માંદગીનું પ્રમાણ અને આયુષ્યની મર્યાદાનો ઉપયોગ થઈ શકે. ૩. શિક્ષણ. તેને માપવા માટે સાક્ષરતાનો દર, છથી અગિયાર વર્ષ દરમિયાન શાળામાં ન જનાર બાળકોનું પ્રમાણ તેમ જ સાત ધોરણ સુધી શાળામાં ટકી રહેનારાં બાળકોના પ્રમાણનો ઉપયોગ થઈ શકે. ૪. રહેઠાણ. તેમાં રહેઠાણ વિનાના લોકોના ટકા, દર ઓરડીમાં રહેનાર સરેરાશ વ્યક્તિની સંખ્યા અને રહેઠાણની પ્રાથમિક સવલતો જેવી કે ; પાણી, ગટર અને વીજળીના પ્રમાણનો સમાવેશ થઈ શકે. ૫. રોજગારી કે બેરોજગારી અને બિનખેતી ક્ષેત્રે રોજગારીનું પ્રમાણ, અને ૬. માનવ અધિકારો (જીવવાનો અધિકાર), જેમાં અપમૃત્યુ, ખૂન, અત્યાચાર વગેરેનું પ્રમાણ ગણી શકાય.

વ્યાપક સ્તરનાં પરિબલોમાં નીચેનાં પરિબલો માનવ વિકાસને માપે છે :

૧. પર્યાવરણ પરિસ્થિતિ જે પ્રદૂષણ તેમ જ કુદરતી સંપત્તિના વિનાશની પરિસ્થિતિ દ્વારા ગણવામાં આવે છે. ૨. પ્રાથમિક સવલતો જેવી કે, વીજળી, પાણી, રસ્તા, વાહનવ્યવહાર, શાળાઓ અને દવાખાનાંઓનું ગામડાંમાં કે સ્થાનિક વિસ્તારમાં પ્રમાણ. ૩. સલામતી અને સુરક્ષા કે જે કોમી રમખાણો કે અન્ય ગુનાના દર દ્વારા માપવામાં આવે છે. ૪. આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય સંસ્થાઓમાં લોકોની ભાગીદારી. ૫. અસમાનતા, જેમાં પ્રાદેશિક અસમાનતા, મૂડીનાં સાધનોની અસમાનતા તેમ જ પિતૃપ્રધાનતા કે જે સ્ત્રી-પુરુષની અસમાનતાના મૂળમાં છે તેને ગણવામાં આવે છે.

ઉપરનાં પરિબલોનો આધારે અમે ભારતનાં જુદાં જુદાં રાજ્યોમાં માનવ વિકાસનું માપન કર્યું છે. આ સાથે ગુજરાતના જુદા જુદા

જિલ્લાઓમાં પણ એ જ રીતે માનવ વિકાસનું માપન કર્યું છે. આ બંને અભ્યાસો દ્વારા એક બાબત ઘણી સ્પષ્ટ બની છે કે, આર્થિક વિકાસ હોય ત્યાં જ માનવ વિકાસ વધારે હોય તે વાત જરૂરી નથી. માનવોને પોતાના વિકાસ માટે વધારે તકો મળે તે માટે ખાસ પ્રયત્નો, ખાસ નીતિઓ અને ખાસ કાર્યક્રમો ઘડવાની જરૂર પડે છે. યુ.એન.ડી.પી.ના માનવ વિકાસના આંકો કરતાં અમારો આંક દક્ષિણના ગરીબ દેશોને માટે વધારે અનુરૂપ છે. કારણ કે, તે આ દેશોની વિશેષ પરિસ્થિતિને લક્ષમાં રાખીને તેમ જ તે દેશોના વિકાસની વિશેષ મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં લઈને માનવ વિકાસનું માપન કરે છે. અમને એમ લાગે છે કે, દુનિયાના બધા દેશોએ માનવ વિકાસનું માપન યોગ્ય રીતે કરવા માટે અમારા આંકોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ અને અમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, યુ.એન.ડી.પી.એ આ બાબતમાં ઘણો રસ બતાવ્યો છે.

અમારા અભ્યાસ દ્વારા એમ પણ પ્રતિપાદિત થાય છે કે, કોઈ પણ રાજ્ય કે પ્રદેશ માનવ વિકાસના દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ કે પાછળ હોય એ જરૂરી નથી. ઘણી વાર કેટલાંક રાજ્યો કે પ્રદેશો અમુક ક્ષેત્રોમાં

આગળ હોય છે. જ્યારે કેટલાંક ક્ષેત્રોમાં પાછળ હોય છે. દાખલા તરીકે, કોઈ રાજ્ય શિક્ષણમાં આગળ હોય પણ માનવ અધિકારોમાં અને ખાસ તો સુરક્ષા અને સલામતીની બાબતમાં પાછળ હોઈ શકે છે. અથવા તો આર્થિક ગરીબીમાં આગળ હોય પણ પર્યાવરણમાં પાછળ હોઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે માનવ વિકાસના એક જ સંયુક્ત આંકને વધુ પડતું મહત્ત્વ ન આપવું જોઈએ. જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોના અલગ આંકો દ્વારા માનવ વિકાસનું વિગતવાર ચિત્ર મળે છે, જેનો નીતિ અને કાર્યક્રમો ઘડવામાં ઘણો ઉપયોગ થઈ શકે છે.

નોંધ

૧. ઈન્દિરા હિરવે અને દર્શિની મહાદેવિયા, ક્રિટિક ઓફ હ્યુમન ડેવલોપમેન્ટ ઈન્ડેક્સ, માનવ વિકાસ પરના આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદમાં રજૂ કરેલું પેપર, માર્ચ-૧૯૯૬. ૨. ઈન્દિરા હિરવે અને દર્શિની મહાદેવિયા, 'લિંગ સંબંધી માનવ વિકાસનો આંક : નવા વિકલ્પ તરફ', ઈકોનોમિક એન્ડ પોલિટિકલ વીકલી, ઓક્ટોબર-૧૯૯૬.

રજૂઆત : ઈન્દિરાબહેન હિરવે, ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન, અમદાવાદ.

પૃષ્ઠ ૩૮નો શેષ ભાગ

ટય મી ટય મી નોટ

વુમન પ્લાન્ટસ એન્ડ હીલિંગ

ભારતમાં આજે મહિલા આરોગ્યની ચળવળને વેગ મળી રહ્યો છે. મહિલાઓનાં જૂથો રાષ્ટ્ર સ્તરે આરોગ્ય સેવાઓ વધુ સારી થાય તે અંગે સક્રિય બનીને કાર્ય કરી રહ્યા છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે તેઓ આધુનિક આરોગ્ય સેવાઓને આંગળી ચીંધી રહ્યાં છે. આ સંદર્ભમાં જ શોધીનીનો અનુભવ અહીં પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે. આ પુસ્તકમાં એવી મહિલાઓના અનુભવોનો નિષ્કર્ષ છે જે વર્તમાનમાં સિક્કો જમાવી બેઠેલી આરોગ્ય રક્ષાની પદ્ધતિનાં વિકલ્પ સ્વરૂપે મહિલા કેન્દ્રિત વિકલ્પ શોધવા માટે ભેગી થઈ હતી. આ પ્રક્રિયામાં ભારતના જુદા જુદા પ્રાંતમાંથી મહિલાઓના આરોગ્ય પર કાર્યરત મહિલા કર્મશીલોએ ભેગા થઈને 'શોધીની' નેટવર્ક બનાવ્યું તથા આ નેટવર્ક દ્વારા પ્રસ્તુત પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવ્યું. આ પુસ્તકમાં પ્રથમ ચાર પ્રકરણો આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં જોડાયેલા સભ્યોના અનુભવને સાંકળે છે. જ્યારે પછીનાં ચાર પ્રકરણમાં કેટલાંક શારીરિક પ્રશ્નો પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તેના પર શોધીનીએ કાર્યલક્ષી સંશોધન (એક્શન રિસર્ચ) કર્યું હતું. આ ઉપરાંત કેટલીક ઉપયોગમાં લેવાયેલી અને ચકાસણી કરાયેલી આયુર્વેદિક દવાઓ પણ જણાવાઈ છે. અંતિમ પ્રકરણમાં આવા નારીવાદી કાર્યલક્ષી સંશોધનમાંથી ઉદ્ભવેલા કેટલાક તાર્કિક મુદ્દાઓ ઉઠાવાયા છે. અંતે પુસ્તકમાં વાચકોના ઉપયોગ માટે શબ્દ સૂચિ આપેલી છે. આ પુસ્તકની ભાષા અંગ્રેજી અને કિંમત રૂ. ૧૫૦ છે. પ્રાપ્તિસ્થાન: કાલી ફોર વિમેન બી-૧/૮, હૌઝ ખાસ, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૧૬. ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લાનાં સંતરામપુર

તાલુકામાં હાથ ધરાયેલા સંશોધન બાદ નીચે મુજબના અહેવાલો પ્રકાશિત થયા છે:

૧. સ્ત્રી અને પુરુષના જાતીયતાથી ફેલાતા રોગોમાં વપરાતી રૂઢિગત સ્થાનિક ઔષધીય વનસ્પતિની પ્રમાણભૂતતા.
૨. જાતીયતાથી ફેલાતા રોગો પ્રત્યેની પુરુષોની માન્યતા અને જાતિ અને જાતિયતા તરફ, પુરુષોનું વલણ અને વર્તન.

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક સાધો : વિમેન્સ હેલ્થ ટ્રેઈનિંગ એન્ડ એડવોકેસી સેન્ટર / વિમેન્સ સ્ટડીઝ રિસર્ચ સેન્ટર, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૧.

વિશ્વ બેંક અને આપણે

વિશ્વ બેંક જેવી સંસ્થાઓ કઈ રીતે કામ કરે છે અને કઈ પદ્ધતિથી નિર્ણયો લે છે તે જાણવા માટે ગુજરાતીમાં સાહિત્ય અપૂરતું છે. કટ્ટર વિરોધ માટે કે સાથે રહી સુધારણા માટે કામગીરીની પદ્ધતિ સમજવી અનિવાર્ય છે. ગુજરાતનાં જે ત્રણ કે ચાર ગરીબોનાં સંગઠનો આ સમજે છે તેમની અસરકારકતા આપોઆપ દેખાઈ આવે છે. કેમ કરી આવાં સંગઠનોની અસરકારકતા હજુ વધે અને બીજાં સંગઠનો પણ આમાં જોડાય તે ભાવનાથી ફાઉન્ડેશન ફોર પબ્લિક ઈન્ટરેસ્ટ દ્વારા આ પુસ્તિકા પ્રગટ કરાઈ છે આ પુસ્તિકામાં વિશ્વ બેંકનાં આરંભ અને હેતુઓ, ધિરાણના પ્રકારો, વિશ્વ બેંક અને બિનસરકારી સંસ્થાઓ તથા મૂલ્યાંકન વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. પ્રાપ્તિસ્થાન: ફાઉન્ડેશન ફોર પબ્લિક ઈન્ટરેસ્ટ, ૪૧૧, સાકાર-૫, નટરાજ સિનેમા પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૮. ફોન. ૬૫૮૨૯૬૨.

સ્થાનિક જૂથોનું મહામંડળ : આજીવિકાની યોજનાઓને ચિરંજીવ બનાવવાનો માર્ગ

પગભરતા (સસ્ટેઈનેબિલિટી)એ બહેનો માટે કોઈ નવો ખ્યાલ નથી કારણ કે તેઓ સદીઓથી માનવજાતને ટકાવવાનું બક્ષતી રહી છે. જો કે, મહિલાઓ માટે પગભરતાનો શો અર્થ છે તેની વ્યાખ્યા કરવાના ભાગ્યે જ કોઈ પ્રયાસો થયા છે. ગુજરાતમાં શ્રમજીવી ગરીબ મહિલાઓના સંગઠનનો બે દાયકા કરતાં વધુ સમયનો અનુભવ અહીં વ્યક્ત થયો છે. ‘સ્વાશ્રયી મહિલા સેવા સંઘ-સેવા’ સંગઠન અને સામૂહિક સાહસિકતા દ્વારા શ્રમજીવી મહિલાઓની ગરીબી સામે સંઘર્ષ ઝીલી તેના નિવારણ માટે કાર્યરત છે. આ કાર્યક્રમોમાં પગભરતા ઊભી કરવામાં ‘સ્વાશ્રયી મહિલા સેવા સંઘ’ (સેવા) એ અપનાવેલા અભિગમનું આ લેખમાં આલેખન કરવામાં આવ્યું છે.



સ્થાનિક લોકોને લગતા કાર્યક્રમો ઘડવા

‘સેવા’નું દર્શન

‘સેવા’ લગભગ બે લાખ જેટલી અસંગઠિત ક્ષેત્રની શ્રમજીવી મહિલા કામદારો અને ઉત્પાદકોનું સંગઠન છે. ‘સેવા’ એ માત્ર સંગઠન નથી. એ તેની સાથે સંકળાયેલાં ગુજરાતના નવ જિલ્લા અને અમદાવાદ શહેરનાં લગભગ ૧૦૦ જેટલાં સ્વસંચાલિત મહિલા સંગઠનોનું એક આંદોલન છે.

‘સેવા’નો હેતુ તેના સભ્યોને પૂર્ણ રોજગાર અને સ્વાવલંબન પૂરાં પાડવાનો છે. પૂર્ણ રોજગારનો અર્થ એ છે કે જે મહિલા કામદારો ઉત્પાદકો છે તેમને નિયમિત આવક મળે, પોષક આહાર અને આરોગ્ય સંભાળ, બાળ સંભાળ તથા આવાસ જેવી સામાજિક સલામતી મળે. સ્વાવલંબનનો અર્થ એ છે કે આ મહિલા ઉત્પાદકો સ્વાયત્ત હોવી જોઈએ અને તેઓ વ્યક્તિગત તથા સામૂહિક બંને રીતે પોતાના નિર્ણયો લેવા શક્તિમાન હોવી જોઈએ. અનુભવ એમ દર્શાવે છે કે કોઈ પણ આંદોલન, સંગઠન કે પરિયોજનાને લાંબા ગાળા સુધી ટકાવવા માટે તેમાં સ્વાવલંબન ઊભું થાય તે જરૂરી છે. જો કે, કાર્યક્રમ ટકાવે તે માટે ઉત્પાદકો પોતે જ તેમના કાર્યક્રમોના અને સ્થાનિક સ્તરનાં સંગઠનોના સંચાલકો અને માલિકો બને તે અનિવાર્ય છે. આ સિદ્ધ કરવા માટે તેના મોટા ભાગના કાર્યક્રમો માટે ‘સેવા’ એ જે સિદ્ધાંતો અપનાવ્યા છે તે નીચે મુજબ છે:

માંગ પ્રેરિત અભિગમ :

તમામ કાર્યક્રમો સમુદાય દ્વારા વ્યક્ત થતી સ્થાનિક જરૂરિયાતો અને માંગને આધારે શરૂ થાય છે. કાર્યક્રમની તૈયારીમાં જેમનું હિત સમાયેલું છે તેવી મહિલાઓ સામેલ થાય છે. આથી લોકોમાં માલિકીની અને ભાગીદારીની ભાવના વધે છે.

સ્થાનિક લોકભાગીદારી :

સ્થાનિક સમુદાયના સભ્યો પ્રવૃત્તિના ખર્ચનો અમુક ભાગ ભોગવે છે અને તેમને એ પ્રવૃત્તિમાં પોતાનું પ્રદાન આપવા માટે પ્રેરવામાં આવે છે. એમાં એકબીજાની જવાબદારી અને ખર્ચમાં ભાગીદારીની વૃત્તિ ઊભી થાય છે અને તેથી લાંબે ગાળે કાર્યક્રમ અસરકારક બને છે.

સ્થાનિક સંબંધો અને સંસાધનો ઊભાં કરવાં :

સમાંતર કાર્યક્રમો ઊભા કરવાને બદલે સ્થાનિક જરૂરિયાતો અથવા પ્રશ્નોને વ્યૂહાત્મક રીતે વર્તમાન સરકારી કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ સાથે તેમને સાંકળવામાં આવે છે. આ અભિગમને પરિણામે સ્થાનિક સંસાધનો ઊભાં કરી શકાય છે અને જિલ્લા સ્તરે સંગઠનની હકારાત્મક છાપ ઊભી કરી શકાય છે.

સ્થાનિક સ્તરે સંગઠનનું નિર્માણ :

તમામ કાર્યક્રમોમાં ગામ, વિસ્તાર તેમ જ જિલ્લા સ્તરે સંગઠનો ઊભાં કરવામાં આવે છે. તેમાં મહિલાઓ પોતે જ તેમનાં સંગઠનોનાં સંચાલક હોય છે.

ક્ષમતા વિકાસનો અભિગમ :

સ્થાનિક સંગઠનના સ્તરે તમામ કાર્યક્રમોમાં સ્થાનિક સંગઠકો અને સંચાલકોની ટુકડી તૈયાર કરાઈ છે. ‘સેવા’ ગ્રામીણ સંચાલકોની આ ટુકડીની ક્ષમતા વિકસાવવા જરૂરી સાધનો અને ટેકો પૂરાં પાડે છે. તેમને ‘ઉઘાડપગા સંચાલક’ (બેરફૂટ મેનેજર) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધીમે ધીમે આ ટુકડી સ્વાવલંબી બને છે અને પછી ‘સેવા’ કાર્યક્રમના અમલીકરણ અને સંચાલનમાંથી ખસી જાય છે અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

‘સેવા’નો અભિગમ

ટકાઉપણા અંગે સેવાની ચિંતા ફક્ત એક ટેકો પૂરી પાડનારી સંસ્થા તરીકે નથી પરંતુ તેના ચાલુ કાર્યક્રમોના અમલમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા અનુભવોમાંથી એ ચિંતા ઊભી થઈ છે. આ ટકાઉપણું ત્રણ વિવિધ સ્તરોએ ઊભું કરવાની જરૂર છે: ૧. વ્યક્તિ અને તેના કુટુંબનું, ૨. જૂથનું અથવા સંગઠનનું, અને ૩. પ્રવૃત્તિનું સ્વાવલંબન. આ ત્રણે સ્તરનું ટકાઉપણું પરસ્પર સંકળાયેલું છે અને પરસ્પરના ટેકા વિના એ સંભવી શકતું નથી. ટકાઉપણું ઊભું કરવા માટે નીચેનાં પાસાંઓ પર પૂરતું ધ્યાન આપવાની જરૂર છે:

નાણાકીય : પ્રવૃત્તિ, સંગઠન અને કુટુંબ નાણાકીય રીતે સ્વાવલંબી હોવાં જોઈએ.

સંચાલકીય : સભ્યોએ પોતે અથવા સંચાલક રાખીને નિર્ણયો લેવાના છે અને રોજિંદો વ્યવહાર ચલાવવાનો છે.

સંબંધો : પ્રવૃત્તિ ત્યારે જ લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે જ્યારે બજાર અને સરકારી સંસ્થાઓ સાથે ઉત્પાદન પહેલાના અને ઉત્પાદન થયા પછીના સંબંધો ઊભા થયા હોય અને તેમને માળખાગત ટેકો મળતો હોય.

‘સેવા’નો અનુભવ

‘સેવા’ દ્વારા શ્રમજીવી સભ્યોની જે સહકારી મંડળીઓ અને જૂથો રચાયેલાં છે તેમની સંયુક્ત લડતમાંથી ‘સેવા’નું હાલનું માળખું ઊભું થયું છે. પગભરતા માટે અને સ્વાવલંબન સિદ્ધ કરવા માટે સભ્યો જૂથો અને સહકારી મંડળીઓ હેઠળ સંગઠિત થયા છે. ગ્રામ વિસ્તારોમાં ‘દ્વાકરા’ (ગ્રામીણ મહિલા અને બાળ વિકાસ કાર્યક્રમ)ની સરકારી યોજના હેઠળ ઉત્પાદક જૂથોમાં સંગઠિત થવાનું મહિલાઓ વધારે પસંદ કરે છે. ‘દ્વાકરા’ કાર્યક્રમ હેઠળ રચાયેલાં જૂથો સરકારની માન્યતા મેળવે છે અને તેથી તેમને સરકારનાં અન્ય કાર્યક્રમો અને યોજનાઓનો મહત્તમ લાભ મળે છે.

ગુજરાત દેશમાં સૌથી વધુ ૮૦ ટકા જેટલું મીઠું ઉત્પન્ન કરે છે. એમાંનું ૭૦ ટકા મીઠું કચ્છના નાના રણમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ગુજરાતના ૪ જિલ્લામાં ૪૦થી ૫૦ હજાર કામદારો મીઠાના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના સાંતલપુર અને રાધનપુર તાલુકાઓમાં કામ કરતી વખતે ‘સેવા’ને અનેક અગરિયા કુટુંબોના સંપર્કમાં આવવાનું થયું. વર્ષમાં છથી આઠ માસ દરમિયાન તેમને માટે મુખ્ય વ્યવસાય મીઠું પકવવાનો જ હોય છે. આ પ્રવૃત્તિ સાથે સંબંધિત અનેક પાસાં અંગે ૧૯૯૦માં ‘સેવા’ દ્વારા એક અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. તેમાં ટેકનિકલ પાસું, વેચાણની સ્થિતિ અને અગરિયાઓની કામની તથા જીવનની પરિસ્થિતિ વગેરે પાસાં આવરી લેવાયાં હતાં. અભ્યાસમાં એમ દર્શાવાયું છે કે અનેક પેઢીઓથી અગરિયાઓની કામની અને જીવનની પરિસ્થિતિ અમાનવીય છે.

અગરમાં મીઠું પકવવાની કામગીરી સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થાય છે અને તે આગામી વર્ષના એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહે છે. જે પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો આ કામ કરે છે તે અગરિયા તરીકે ઓળખાય છે. મીઠાના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં અનેક તબક્કા હોય છે : જમીન સરખી કરવી, પાટા બનાવવા, પગલી પાડવી, ઘનતા સરખી કરવી, પાટામાં પાણી ભરવું, મીઠું પકવવું, મીઠાની પડી જામે ત્યારે તેને તોડી તૈયાર મીઠું બજારમાં મોકલવામાં આવે છે. મીઠું ક્યાં અને ક્યારે મોકલવું તે ખરીદનારા પર અને પરિવહનની સવલતો પર આધાર રાખે છે.

મીઠાની મોસમ દરમિયાન અગરિયાનું કુટુંબ રૂ. ૩૦૦૦થી રૂ. ૪૦૦૦ની આવક મેળવે છે. વધુ સભ્યો ધરાવતાં કુટુંબો વધુ આવક રળે છે. આમાંનાં મોટા ભાગનાં કુટુંબો વેપારીઓના દેવાદાર છે. આ વેપારીઓ જ મોસમ પૂરી થતાં મીઠું ખરીદે છે અને પછી તેઓ ખુલ્લા બજારમાં વેચે છે. જે રકમ દેવા તરીકે લેવાઈ હોય એ મોસમ પૂરી થતાં નફામાંથી બાદ કરવામાં આવે છે. ઘણી વાર જ્યારે અગરિયા પૂરતું મીઠું ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી ત્યારે તેઓ દેવું ભરપાઈ કરી શકતા નથી. તેવે વખતે તેઓ બીજા વર્ષે વ્યાજ સાથે દેવું ભરપાઈ કરે છે અને એ જ વેપારીને એને માટે મીઠું વેચે છે. દેવું પૂરું ભરપાઈ થઈ જાય ત્યાં સુધી એ પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે. આમ, દેવાનું ચક્ર ચાલુ રહે છે અને અગરિયા ભાગ્યે જ વેપારીઓની પકડમાંથી બહાર આવે છે. પરિણામે, તેમની જિંદગી દરમિયાન તેમની આર્થિક સ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર આવતો નથી. આમ, ધિરાણની પ્રાપ્તિ એ મહત્વની બાબત છે. તેનાથી જ અગરિયા તેમની ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા પર અંકુશ મેળવે છે અને વેઠિયાની સ્થિતિમાંથી પોતે મુક્ત થઈ શકે છે.



મજૂરોને તેમની મજૂરીનું યોગ્ય વળતર વચેટિયાઓના કારણે મળતું નથી આ અભ્યાસનાં તારણોને આધારે કરાયેલી ભલામણોના સંદર્ભમાં ‘સેવા’એ ગુજરાત સરકારને અગરિયાઓની કામની અને જીવનની પરિસ્થિતિ સુધારવા માટે જરૂરી સેવાઓ પૂરી પાડવાની યોજનાઓ ઘડવા સૂચવ્યું હતું. ગુજરાત સરકારના ગ્રામ મજૂર કમિશનરની કચેરી સાથે સતત વાટાઘાટો ચાલી. તેને પરિણામે ૧૯૯૦-૯૧માં આ અંગેના એક કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ. એમાં બાળ સંભાળ, આરોગ્ય સંભાળ અને આવાસની સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.

આ યોજનાઓનો લાભ અગરિયાઓને મળે તે માટે તેમને સંગઠિત કરવાના પ્રયાસો 'સેવા' એ કર્યા. એને પરિણામે 'ડે કેર સેન્ટર' શરૂ થયાં. આ સેન્ટરો માત્ર કામના સ્થળે નહિ પણ અગરિયાઓ જે ગામોમાંથી સ્થળાંતર કરીને આવ્યા હોય તે ગામોમાં પણ શરૂ થયાં. એક હરતીફરતી મોબાઈલ આરોગ્ય વાન રણમાં અગરો ઉપર જવા લાગી. તેથી અગરિયાઓને સ્થળ પર જ સારવાર મળી રહે તેની શરૂઆત થઈ.

બીજો એક હેતુ અગરિયાઓને વેપારીઓની પકડમાંથી મુક્ત કરવાનો હતો અને તેમને ઉત્પાદકનો દરજ્જો આપવાનો હતો. એ જ સમયે ગ્રામ વિકાસ કમિશનરની કચેરી ગરીબી નિવારણની યોજનાઓ તળે અગરિયાઓ માટેના કાર્યક્રમ શરૂ કરતી હતી. આ તકનો લાભ લઈને 'સેવા'એ બહેનોને દ્વાકરા યોજના હેઠળ સંગઠિત કરવાનું કામ શરૂ કર્યું. આ યોજના હેઠળ દરેક જૂથને રૂ.૬૦,૦૦૦નું ભંડોળ આપવામાં આવે છે. તે મીઠાના ઉત્પાદન માટે તથા બજાર સાથેના જરૂરી જોડાણ ઊભાં કરવા માટે સાધનસામગ્રી ખરીદવા ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

સહાયક સેવાઓની પ્રાપ્તિ અંગે માગણી કરવાની પ્રક્રિયા દ્વારા અગરિયાઓ સાથે સંપર્ક સ્થપાઈ ગયો હતો તેથી સંગઠનની જરૂરિયાતો અને લાભો અંગે તેમની જાગૃતિ વધારવામાં આવી. સભ્યોના શિક્ષણ માટે સઘન ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી અને અગરિયાઓ તથા તેમનાં કુટુંબો સાથે નિયમિતપણે બેઠકો યોજવામાં આવી. આ બેઠકોમાં વિવિધ સંગઠનોના લાભાલાભ તેમને જણાવવામાં આવ્યા. સંગઠનના સ્વરૂપ તરીકે 'દ્વાકરા' અને તેના લાભો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી. ખાસ કરીને સરકારના ગરીબી નિવારણના અન્ય કાર્યક્રમો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. 'દ્વાકરા' હેઠળ જૂથની રચના કરવા માટે કેવા પ્રકારનાં અને કેટલાં સંસાધનોની જરૂર રહેશે તે વિશે પણ તેમને માહિતી આપવામાં આવી. આવી ઉપરોક્ત પ્રક્રિયાથી સ્થાનિક સ્તરના સંગઠનમાં તેમની શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ વધ્યાં. અગરિયાઓના દ્વાકરા જૂથે ગ્રામવાસીઓનો સંપર્ક સાધ્યો અને તેમના સક્રિય ટેકાથી સ્થાનિક સંગઠનની રચના કરવામાં આવી. ૧૦ એકર જમીન લીઝ ઉપર ધરાવનારા નાના અગરિયાઓ પાસેથી ભાડે લેવામાં આવી અને એમાં અગરની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી.

'સેવા' દ્વારા કાર્યવિસ્તારમાં 'બનાસકાંઠા દ્વાકરા મહિલા સેવા એસોસિયેશન, (બી.ડી.એમ.એસ.એ.)ની રચના કરવામાં આવી છે જે ૮૦ દ્વાકરા જૂથોનો સંઘ છે. એસોસિયેશન દ્વાકરા જૂથના અગરિયાઓને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવાનું કામ કરે છે. તેમાં ખાસ કરીને 'દ્વાકરા' જૂથોના અગરિયાઓને જૂથની નોંધણી માટેની દરખાસ્ત તૈયાર કરવામાં, તાલુકા પંચાયતની કચેરીએથી જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવવામાં અને અંતે 'ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ'ને દરખાસ્ત સુપરત કરવામાં મદદ કરે છે. અગરમાં મીઠું પકવવાનું કામ ખેતીની જેમ જ ઋતુગત

કામ છે તેથી સાધનો સમયસર મળવાં જરૂરી છે કે જેથી ઉત્પાદન સમયસર હાથ ધરી શકાય. દરખાસ્ત તૈયાર કરવામાં સમય જાય છે તેથી મંડળ દરેક જૂથને તેની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવા માટે આરંભમાં રૂ. ૧૦,૦૦૦નું ધિરાણ આપે છે. એક વાર જૂથને ફરતું ભંડોળ મળી જાય પછી ધિરાણ તરીકે અપાયેલી રકમ 'બી.ડી.એમ.એસ.એ'ને પરત ચૂકવવામાં આવે છે. આ રીતે બી.ડી.એમ.એસ.એ દ્વારા અનેક દ્વાકરા જૂથોને સંગઠિત કરી શરૂઆતના તબક્કામાં મદદ કરવામાં આવી છે.



સાહસિકતા અને વહીવટી કુશળતા વધારવી

વર્ષોથી અગરિયાઓ આ પ્રવૃત્તિ કરતા આવ્યા છે તેથી કૌશલ્ય વિકાસ માટે આરંભમાં કોઈ તાલીમની જરૂર નહોતી. જો કે, બી.ડી.એમ.એસ.એની ટીમે તેમને જરૂરી ટેકો અને સાધનો પૂરાં પાડ્યાં છે. એસોસિયેશન તેનાં સભ્ય જૂથોને આયોજન, જૂથની કામગીરી, બજાર સાથે જોડાણ ઊભું કરવા અને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા પર દેખરેખ રાખવા જેવી બાબતોમાં મદદ કરી છે. મીઠું ઉત્પન્ન કરતાં 'દ્વાકરા' જૂથોને કામના સમયે જ તાલીમ આપવામાં આવી છે. બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું, એ ખાતું ચલાવવું, 'દ્વાકરા' જૂથના દસ્તાવેજો જાળવવા, ઓડિટિંગ, એકંદર ખર્ચની ગણતરી કરવી અને નાણાકીય સંચાલન જેવી બેંકિંગને અને હિસાબોને લગતી બાબતો માટે પણ તેમને તાલીમ આપવામાં આવી છે.

બી.ડી.એમ.એસ.એના સ્થાનિક સંચાલકોએ 'દ્વાકરા' જૂથના નેતાઓ માટે અનેક તાલીમ બેઠકો ગોઠવી છે. તેમાં 'દ્વાકરા' જૂથના નેતાઓ અને સભ્યો ભાગ લે છે. આ તાલીમમાં 'દ્વાકરા' કાર્યક્રમનો ખ્યાલ, જૂથના સભ્યોની ભૂમિકા, જૂથના નેતાઓની ભૂમિકા જૂથની કામગીરી, સંચાલન અને વેચાણની વ્યૂહરચનાઓ વગેરે વિશે ચર્ચા કરવામાં આવે છે અને સ્પષ્ટતાઓ કરવામાં આવે છે. એ પછી દરેક જૂથની માસિક જૂથ મીટિંગ યોજવામાં, એ બેઠકોની કાર્યસૂચિ તૈયાર કરવામાં અને બેઠકોની કાર્યનોંધ તૈયાર કરવામાં તેમને ટેકો પૂરો પાડવામાં આવે છે. આ રીતે જૂથના નેતાઓ અને સભ્યો સંચાલકીય કુશળતાઓ પ્રાપ્ત કરે છે. જૂથનો દરેક સભ્ય આ પ્રક્રિયામાં સામેલ થાય છે અને

તે જૂથની તમામ પ્રવૃત્તિઓ તથા નાણાકીય સ્થિતિથી માહિતગાર હોય છે. આથી જૂથમાં સાહસિકતા ઊભી થાય છે અને પારદર્શકતા જળવાય છે.

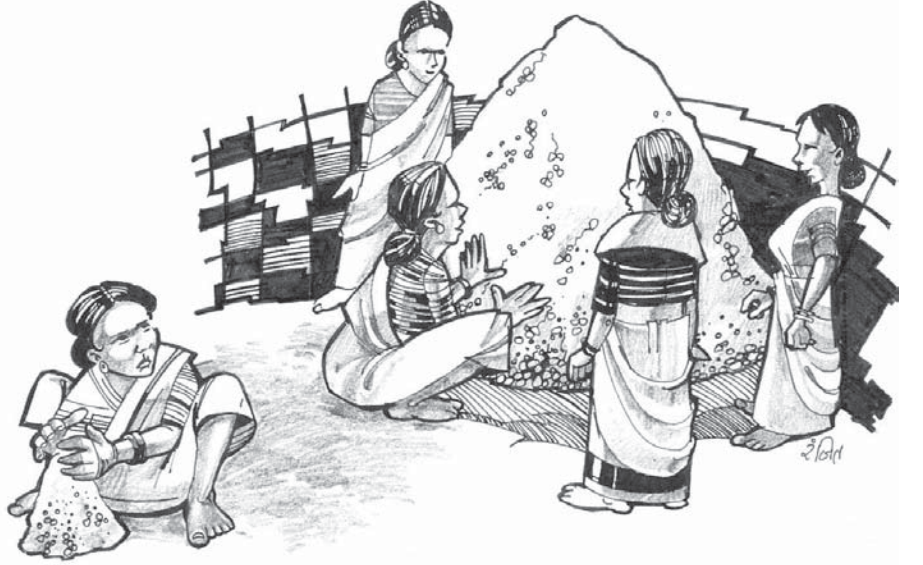
‘દ્વાકરા’ જૂથના અગરિયાઓને ઉત્પાદન પ્રક્રિયાના આયોજન, પ્રાપ્ય સંસાધનોના આધારે ઉત્પાદન ક્ષમતાનું આકલન, ઉત્પાદન અને વેચાણની યોજનાઓની તૈયારી, વધારાનાં નાણાંની પ્રાપ્તિ વગેરે માટે ઔપચારિક અને અનૌપચારિક તાલીમ આપવાનું અને જરૂરી ટેકનિકલ સાધનો પૂરાં પાડવાનું કામ બીડીએમએસએની ટીમે કર્યું છે. ઘડાયેલી યોજનાઓનો અમલ થાય છે અને જૂથની બેઠકો દરમિયાન તેના પર નિયમિત દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. દર મહિને ‘દ્વાકરા’ જૂથોના તમામ સભ્યોની અને દરેક જૂથની બેઠક યોજવામાં આવે છે. આ બેઠકોમાં ભાવિ યોજના અંગેના મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવે છે અને વ્યૂહરચનાઓ નક્કી કરવામાં આવે છે. આથી જૂથો માટે ભણતરની પ્રક્રિયાનો માર્ગ મોકળો થાય છે અને તેમની ક્ષમતા વધે છે.

મીઠાના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા પૂરી થાય પછી એક સંમેલન બોલાવવામાં આવે છે. તેમાં તમામ ‘દ્વાકરા’ જૂથો, સરકારનો ગ્રામ વિકાસ વિભાગ અને મોટાં ઉદ્યોગ ગૃહો હાજર રહે છે. આ સંમેલન ગ્રામ મજૂર કમિશનર, મીઠા કમિશનર જેવા સરકારી વિભાગો તથા નિરમા અને ગુજરાત હેવી કેમિકલ્સ લિમિટેડ જેવી મીઠાની ખરીદાર કંપનીઓ સાથે સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

બજાર સાથે મજબૂત સંબંધો ઊભા કર્યા પછી ખુલ્લા બજારમાં સ્પર્ધા વચ્ચે ટકવા માટે બીડીએમએસએ બજારની માંગ અનુસાર ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સુધારવા માટે ‘સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરિન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુટ’ દ્વારા ટેકનિકલ સાધનો પૂરાં પાડે છે. ઇન્સ્ટિટ્યુટ મીઠાના ઉત્પાદનની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ અંગે ‘દ્વાકરા’ જૂથોને ત્રિમાસિક તાલીમ આપે છે. એમાં સ્થળની પસંદગી, અગરનાં લે-આઉટ અને ડિઝાઇન, બ્રાઇનની માત્રા, બ્રાઇનના પ્રવાહનો લે-આઉટ અને નિયંત્રણ, મીઠા માટે રેકનો ઉપયોગ અને મીઠાનું ગઠન વગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. તાલીમ ઔપચારિક વર્ગખંડોમાં નિદર્શન દ્વારા પણ અપાય છે અને પ્રત્યક્ષ પ્રયોગો દ્વારા પણ અપાય છે. આ તાલીમથી જૂથ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા મીઠાના જથ્થા અને ગુણવત્તા બંનેમાં સુધારો થયો છે. હાલ મીઠું વાપરતી મોટી કંપનીઓ ‘દ્વાકરા’ જૂથો દ્વારા ઉત્પન્ન થતું મીઠું સીધું જ ખરીદવા માટે તત્પર થઈ છે.

અગરિયાઓની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધે તે માટે આરોગ્ય અને બાળ સંભાળ જેવી સહાયક સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. ગ્રામ મજૂર

કમિશનરની કચેરી દ્વારા અગરિયાઓ માટે ખાસ જે કલ્યાણ યોજનાઓ ઘડાઈ છે તેમનો લાભ લઈને આ સેવાઓ પૂરી પડાય છે. બીડીએમએસએ તેનાં સભ્ય ‘દ્વાકરા’ જૂથોને નાણાકીય, ટેકનિકલ અને વેચાણને લગતી બાબતો અંગેનો અવકાશ અને સાધનો પૂરાં પાડે છે. એ રીતે ‘દ્વાકરા’ જૂથોની ક્ષમતા જ વિકસી છે એવું નથી પણ તેઓ સક્ષમ અને પગભર થયાં છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા આ ઉત્પાદક જૂથો તેમનાં કાર્યક્રમો અને સંગઠનોના માલિકો અને સંચાલકો બન્યા છે. ‘દ્વાકરા’ જૂથોનું એસોસિયેશન બનાવવાના અનેક લાભો છે :



ઉત્પાદકોનું જૂથ રચવાનું મહત્ત્વ

૧. ગરીબ ગ્રામીણ નિરક્ષર મહિલાઓ માટે જૂથનું સંચાલન કરવાનું અને આપમેળે સ્થાનિક સરકારી કચેરીઓ સાથે સંપર્ક સાધવાનું અને સ્થાનિક વેપારીઓ સાથે કામ પાર પાડવાનું મુશ્કેલ હોય છે. બીડીએમએસએ આ ભૂમિકા ભજવે છે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે. ૨. મીઠું પકવવાની કામગીરીને ટકાઉ બનાવવા માટે નાણાંની જરૂર પડે છે અને સરકાર દ્વારા ભંડોળ જારી કરાવવામાં વિલંબ થાય છે તેથી કામગીરીને વિપરીત અસર પહોંચે છે. કારણ કે મીઠું પકવવાની કામગીરી ઋતુગત છે. મહામંડળ ટૂંકા ગાળા માટે તત્કાળ લોન આપે છે તેથી તે બફર તરીકે કામ લાગે છે. આથી જૂથો ખાનગી વેપારીઓની પકડમાંથી મુક્ત બને છે અને તેઓ જાતે જ તેમની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પર અંકુશ મેળવી શકે છે. ૩. ઉત્પાદનની ક્ષમતા વધારવા અને પોતાની સોદાશક્તિ વધારવા માટે ઉત્પાદન પહેલાં અને પછી જરૂરી જોડાણ ઊભા કરવાનું દરેક દ્વાકરા જૂથ માટે મુશ્કેલ હોય છે. જો કે, બીડીએમએસએ આ સંબંધો ઊભાં કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ ટેકાથી અગરિયાઓને ઉત્પાદકનો દરજ્જો મળે છે. ૪. ‘દ્વાકરા’ જૂથો બીડીએમએસએના ટેકાથી તેમની પોતાની વેચાણની વ્યૂહરચના ઊભી કરવામાં અને સંબંધો પ્રસ્થાપિત

કરવામાં સફળ થયાં છે. તેથી દરેકની વ્યક્તિગત રીતે તેમ જ સામૂહિક આવક તથા રોજગારીની ક્ષમતા વધી છે. પ. બીડીએમએસએ દ્વારા હસ્તક્ષેપ થવાને કારણે વ્યાપાર સંબંધી નીતિઓ અને સંબંધો બદલાયાં છે. એનાથી આ કાર્યક્રમ ટકાઉ બન્યો છે એટલું જ નહિ પણ જીવનનિર્વાહની તરાહ સુધરી છે.



કામદાર/ઉત્પાદકો ઉત્પાદનના માલિક બની શકે છે

મહામંડળની લાંબા ગાળાની અસરો

કામદારને ઉત્પાદકનો દરજ્જો :

અત્યાર સુધી અગરિયાઓ માત્ર મજૂર તરીકે કામ કરતા હતા. તેમનું શોષણ થતું હતું અને તેઓ ભારે દેવાદાર હતા. હવે તેઓ જાતે ઉત્પાદકો બન્યા છે. 'દ્વાકરા' કાર્યક્રમ હેઠળ તેઓ સંગઠિત થતાં અગરિયાઓના વેતન દર રોજના રૂ. ૨૦થી વધીને રૂ. ૬૦ થયા છે. ઉપરાંત, સહાયક સેવાઓને લીધે તેમની કામની અને જીવનની સ્થિતિ સુધરી છે.

કામ અને આવકની સલામતી :

અગાઉ અગરિયાઓ મીઠું વેચવા માટે સંપૂર્ણપણે વેપારીઓ એટલે કે વચેટિયાઓ પર આધાર રાખતા હતા. વર્ષમાં છથી આઠ મહિના સખત મહેનત કરવા છતાં તેમને કિલોગ્રામના માત્ર પાંચ પૈસાના ભાવે મીઠું વેચવું પડતું હતું. બીડીએમએસએના ટેકાથી આ 'દ્વાકરા' જૂથો માટે તમામ બજારલક્ષી સંબંધો ઊભા કરવામાં આવ્યા. એને પરિણામે આજે મીઠાના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા સક્ષમ અને સ્વાવલંબી બની છે.

અનુભવથી મેળવેલ શીખ

ખાસ કરીને ગરીબ મહિલાઓ માટેની પ્રવૃત્તિઓ ટકાઉ બને તે

અંગેના દાયકાઓના અનુભવમાંથી 'સેવા'ને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. ઉપરોક્ત ઉદાહરણને આધારે એ ટૂંકમાં નીચે મુજબ જણાવી શકાય :

સમુદાયની જરૂરિયાત પૂરી કરવી :

સ્થાનિક લોકોને જે જરૂરી લાગતું હોય એવી જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખી કાર્યક્રમો રચવા જોઈએ. ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં અગરિયાઓને ધિરાણની અને બજાર સુધીની પહોંચની જરૂર હતી.

સંગઠન માટે જૂથની રચના :

સ્થાનિક મહિલાઓએ તેમનું પોતાનું સંગઠન બનાવવું અને ક્ષમતા ઊભી કરવી કે જેથી તેઓ સ્વતંત્રપણે તેમની પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કરી શકે. જો કે, સ્થાનિક મહિલાઓના ક્ષમતાવર્ધન માટે અને તેઓ અંતે તેમનાં સંગઠનો સંભાળે અને ચલાવે તે માટે તેમને જરૂરી ટેકો પૂરો પાડવો જોઈએ. અગરિયાઓની સહકારી મંડળીઓ, પાણી વપરાશકારનાં જૂથો, કારીગરોનાં મંડળો, સ્વસહાય બચત મંડળો, હસ્તકલા મંડળો, મજૂર સંઘો વગેરે આનાં ઉદાહરણો છે. લોકશાહી પદ્ધતિએ પ્રતિનિધિઓ દ્વારા મહામંડળ રચાય એ અન્ય પ્રકારનાં સંગઠનો કરતાં વધુ ઈચ્છનીય છે, કારણ કે આ પ્રક્રિયા દ્વારા મહિલાઓ તેમનાં સંસાધનો પર વધુ અંકુશ મેળવી શકે છે.

પરિયોજનાની સિદ્ધિ માપવા માટેના માપદંડો વાસ્તવિક હોવા જોઈએ:

જો સ્થાનિક સભ્યોને તેમની જિંદગીમાં તત્કાળ લાભ થતો ન દેખાય તો તેઓ પરિયોજનામાં રસ નહિ ધરાવે. ગરીબ મહિલાઓને સામેલ કરતી પરિયોજનાઓ માટે આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે, કારણ કે તેઓ લાંબા સમય સુધી રાહ જોઈ શકતી નથી.

અગાઉ જણાવ્યા મુજબ 'સેવા'નો હેતુ પૂર્ણ રોજગાર પ્રાપ્ત કરવાનો અને સભ્યોને સ્વાવલંબી બનાવવાનો છે. આ હેતુને સિદ્ધ કરવા તેને નીચેના માપદંડો અનુસાર જોવામાં આવ્યો છે :

- 'સેવા'ની દરમ્યાનગીરીથી સભ્યોને વધુ રોજગારી પ્રાપ્ત થઈ છે ખરી ?
- તેમની આવક વધી છે ?
- તેમને ખોરાકની સલામતી અને પોષણ મળ્યાં છે ખરાં ?
- તેમના આરોગ્યનું રક્ષણ થયું છે ?
- બાળ સંભાળ સેવાઓ તેમને મળી છે ખરી ?
- તેમને આવાસ અને સંબંધિત અન્ય સેવાઓ મળી છે ?
- સાધન-સંપત્તિ પરની તેમની માલિકી વધી છે ? આ સાધન-સંપત્તિમાં તેમની બચત, જમીન, ઘર, કામનું સ્થળ, કામનાં સાધનો, પરવાના, ઓળખપત્ર, ઢોર, સહકારી મંડળીના શેર વગેરેનો



અન્ય વ્યક્તિઓએ સંસ્થાઓ સાથે સંપર્ક સાધવો

સમાવેશ થાય છે. આ બધાની સત્તાવાર માલિકી મહિલાઓની હોવી જોઈએ.

- મહિલાઓનું સંગઠન મજબૂત થયું છે ?
- મહિલાઓમાં નેતૃત્વ ઊભું થયું છે ?
- મહિલાઓ વ્યક્તિગત અને સામૂહિક બંને રીતે સ્વાવલંબી બની છે ?

અન્ય સંસ્થાઓ સાથેનાં જોડાણો :

સ્થાનિક સંગઠનોએ સરકારી યોજનાઓ, વિરાણ કે બજાર જેવા પ્રાપ્ય માળખાગત ટેકા સાથે જોડાણો ઊભાં કરવાં જોઈએ. નાણાંની પ્રાપ્તિ, સરકારની વિકાસલક્ષી યોજનાઓનો ઉપયોગ, દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી, ગામનું વહીવટી તંત્ર અથવા કામદાર પરિષદ જેવાં અન્ય સંગઠનોમાં ભાગીદારીના સંદર્ભમાં આ સંબંધો પ્રસ્થાપિત થવા જોઈએ.

અનેક સ્ત્રોતોમાંથી નાણાંની પ્રાપ્તિ :

સ્થાનિક સંગઠને અનેક સ્ત્રોતોમાંથી નાણાં મેળવવાં જોઈએ. એમાં સરકારી યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો, સ્થાનિક લોકોનો ફાળો, આવક સર્જતી પ્રવૃત્તિનો ફાળો અથવા અન્ય સ્ત્રોતોનો સમાવેશ થાય છે. દાતાનું વલણ બદલાય, સરકારની નીતિ બદલાય કે બજારનાં પરિબળો વિરુદ્ધમાં જાય ત્યારે જો નાણાં અનેક રીતે મેળવાતાં હોય તો ટકી શકાય છે.

કટોકટીની પરિસ્થિતિ માટે જોગવાઈ :

તમામ પરિયોજનાઓ, કાર્યક્રમો કે પ્રવૃત્તિઓમાં કુદરતી કે માનવસર્જિત

દુર્ઘટના ઊભી થઈ શકે છે એ સ્વીકારવું જોઈએ અને એ દુર્ઘટનાની અસર ઓછી થાય તે માટે સંસાધનોની જોગવાઈ કરવી જોઈએ તથા ભવિષ્યમાં તેવી દુર્ઘટના ન ઘટે અથવા એની શક્યતા ઘટે તે માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ગરીબ મહિલાઓમાં કુદરતી દુર્ઘટનાઓનો સામનો કરવા માટેની તાકાત તેમની રોજિંદી કૌટુંબિક બાબતોના સંચાલનની શક્તિમાંથી જ ઊભી થાય છે, કારણ કે દુર્ઘટનાઓની મહિલાઓને સૌથી વધારે અને સૌ પ્રથમ અસર થાય છે. પરંતુ મહિલાઓના વિકાસની મોટા ભાગની પરિયોજનાઓમાં આવી જોગવાઈ કરવામાં આવતી નથી અને તેને પરિણામે પૂર કે દુકાળની પરિસ્થિતિમાં એ પરિયોજનાઓ ભાંગી પડે છે.

સાવચેતી અને પસંદગી :

બધી જ પરિયોજનાઓ ટકાઉ બની શકતી નથી અને એ જરૂરી પણ નથી. ગ્રામીણ વિધવાઓ માટે કે પૂરના અસરગ્રસ્તો માટે તાકીદના ધોરણે જે રાહત કાર્યક્રમ ચલાવવામાં આવે તેને બહારની મદદની જરૂર નથી. તેમ છતાં, આવી પરિયોજનાઓને કે પ્રવૃત્તિઓને તદ્દન રદ ન કરી શકાય કે પછી તે ટકાઉ હોય જ એવો આગ્રહ પણ ન રાખી શકાય.

ટકાઉપણાનું ખર્ચ :

મહદંશે કાયમી ધોરણની કરતાં નિશ્ચિત સમયની પરિયોજનાનો અમલ કરવામાં ખર્ચ ઓછું થાય છે. જે પરિયોજનાઓ લાંબા ગાળા સુધી ટકાઉ બનાવવાનું ધ્યેય રાખતી હોય તેમાં વધુ સંસાધનોની જરૂર પડે છે. પૂરતા ટેકા વિના અને આગોતરી તૈયારી વિના પરિયોજનાને ટકાઉ બનાવવાનું શક્ય નથી.

‘સેવા’નો અનુભવ ઉપર જણાવ્યા બાદ અત્રે એ નોંધવાની જરૂર છે કે પરિયોજના કાયમી બને અને પગભર થાય તેવો ઉદ્દેશ રાખતી પરિયોજનામાં સ્થિરતા આવી જાય અને સત્તાના પ્રવર્તમાન અસમાન સંબંધોને તે ચાલુ રાખે એવું શક્ય બની શકે છે. કાયમી ધોરણે પરિયોજના ચાલે તે ધ્યાનમાં રાખવાની સાથે સાથે મહિલાઓની ક્ષમતા વધે એ હેતુ ભુલાઈ જવો ન જોઈએ. કાર્યક્રમો લાંબા ગાળા માટે ચાલે અને તેમાં મહિલાઓની ગરીબી સામે લડત અપાય એ લાંબી અને થકવી નાખનારી પ્રક્રિયા છે અને તે પરિયોજનાના અભિગમથી સિદ્ધ કરવાનું શક્ય નથી. એમાં ભાગીદારી અને સહયોગનાં તત્ત્વો પર આધારિત અભિગમ હોય તો જ પરિયોજના ટકાઉ બને છે.

રજૂઆત : રીમા નાણાંવટી, સ્વાશ્રયી મહિલા સેવા સંઘ (સેવા), વિકટોરિયા ગાર્ડન સામે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧.

રાજસ્થાનના ચાર રણ વિસ્તારમાં ખેતી સિવાયનાં ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓના જીવનનિર્વાહ માટેના 'સ્યોર'ના પ્રયાસો

'સોસાયટી ટુ અપલિક્ટ રુલ ઈકોનોમી' (સ્યોર) ભારતે જિલ્લાના ચોટન બ્લોકમાં કામ કરે છે. તેનો મુખ્ય હેતુ મહિલાઓને તેમની કુશળતા પ્રમાણે નિયમિત વળતરજન્ય રોજગારી પૂરી પાડવાનો છે. ૧૯૬૫ અને ૧૯૭૧ દરમ્યાનનાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનાં યુદ્ધો દરમ્યાન નિર્વાસિત બનેલી મહિલાઓ માટે જીવનનિર્વાહનો કાર્યક્રમ તેણે વિકસાવ્યો છે. આ પ્રદેશનું અર્થતંત્ર ખેતી અને પશુપાલન પર ખૂબ જ અવલંબિત છે. વરસાદના અભાવે અને પ્રતિકૂળ આબોહવાને લીધે ખેતીનું કામ વર્ષમાં માત્ર ત્રણ માસ જ હોય છે. વારંવાર દુકાળ પડવાને લીધે અર્થતંત્ર વધુ ખોરંભે પડે છે. ખેતીમાંથી થતી કમાણી નજીવી હોય છે અને તેથી રોજગારી મેળવવા નજીકનાં શહેરોમાં સ્થળાંતર એ સામાન્ય ઘટના છે.

ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધની નિર્વાસિત સ્ત્રીઓ પાસે ભરતગૂંથણની પરંપરાગત કુશળતા હતી જ. ૧૯૮૦ના દાયકાના ઉત્તરાર્ધમાં વ્યાપારી સાહસોએ જંગી નફો રળવા માટે આ કૌશલ્યનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સ્ત્રીઓ પાસેથી પીસ રેટના ધોરણે કામ લેવાતું હતું. પણ તેમનું કૌશલ્ય વધે એ માટે કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આવતો નહોતો. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષો દરમ્યાન ટૂંકા ગાળામાં નીચી ગુણવત્તાવાળી ચીજો બનાવવા પર ભાર મુકાયો અને તેથી તે સ્ત્રીઓની પરંપરાગત કુશળતાને થોડું નુકસાન પહોંચ્યું. વચેટિયાઓ દ્વારા ગોઠવાયેલા શોષણના ચક્રમાંથી સ્ત્રીઓને મુક્ત કરવા 'સ્યોર' દ્વારા આ કાર્યક્રમ શરૂ કરાયો. રાજસ્થાનના 'ઉર્મૂલ ટ્રસ્ટ'ના અનુભવમાંથી તેણે આ કાર્યક્રમ માટે પ્રેરણા લીધી હતી.

પ્રથમ તબક્કો

મહિલાઓના જૂથની રચના

૧૯૮૧માં 'સ્યોર' દ્વારા ચોટન વિભાગનાં ૫ ગામો નક્કી કરવામાં આવ્યાં અને દરેક ગામમાંથી ૨૦ મહિલાઓ પસંદ કરીને ૧૦૦ મહિલાઓના જૂથની રચના કરવામાં આવી. મહિલાઓની પસંદગી તેમની ભરતગૂંથણની કુશળતાને આધારે કરવામાં આવી હતી. આ તમામ મહિલાઓ ગરીબ કુટુંબોની હતી અને તેથી તેમની ગરીબીનું નિવારણ આ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ હતો. અત્રે એ નોંધનીય છે કે સંબંધિત જૂથોના સભ્યોની પસંદગી એ જ જૂથની વધુ કુશળતા ધરાવતી મહિલાઓએ જ કરી હતી.

ઊંચી કુશળતા ધરાવતી મહિલાઓની દેખરેખ હેઠળ ઉત્પાદનની

પ્રક્રિયાનો આરંભ કરવામાં આવ્યો. આરંભમાં, 'સ્યોર' દ્વારા કાચો માલ પૂરો પાડવામાં આવ્યો અને કામની ફાળવણી કરવામાં આવી. કુશળતામાં વધારો થાય એ એ એક મહત્વનું પાસું હતું અને એના પ્રત્યે ધ્યાન આપવાની જરૂર હતી. ઊંચી કુશળતા ધરાવતી મહિલાઓને અન્ય મહિલાઓની કુશળતા વધારવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. અનેક ઔપચારિક અને અનૌપચારિક બેઠકો દ્વારા તેમને તાલીમ આપવામાં આવી અને તેમનું કામ ચાલતું હોય ત્યારે પણ તેમણે કુશળતા શીખવવામાં આવી. આ પ્રક્રિયાને લીધે વધારે સારી ચીજો બની અને સ્થાનિક બજારોમાં તે વેચવાનું 'સ્યોર' દ્વારા શરૂ કરાયું. જયપુર અને દિલ્હીમાં પ્રદર્શનોમાં અને 'કાપાર્ટ' દ્વારા યોજાયેલાં પ્રદર્શનોમાં પણ એ વસ્તુઓ વેચવામાં આવી.



પ્રથમ સાત માસ દરમ્યાન, પાંચ જૂથોની ૧૦૦ મહિલાઓને રોજગારી પૂરી પડાઈ. અન્યથા તેઓ વર્ષના આ ગાળા દરમ્યાન બેકાર જ રહી હોત. વચેટિયાઓએ આ પ્રક્રિયા ખોરંભે પાડવાના અનેક પ્રયાસો કર્યા. એમ પણ જણાયું કે પોતાની ધિરાણની જરૂરિયાતો માટે મહિલાઓ વચેટિયાઓની પકડમાં જ છે.

દ્વિતીય તબક્કો

જુદાં જુદાં વ્યક્તિ/માળખાં સાથે સંબંધોની સ્થાપના

આ તબક્કામાં મહિલાઓને અને 'સ્યોર'ના કાર્યકરોને એમ બંનેને એમ લાગ્યું કે એક વ્યવસાયી ડિઝાઈનરની જરૂર છે. ગ્રાહકોને વસ્તુ વિશે શું લાગે છે તેની માહિતી મેળવવાની પણ કોઈ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી નહોતી કે જેથી ડિઝાઈનની દૃષ્ટિએ તેને આધુનિક બનાવવા

માટેનો માર્ગ મોકળો થાય. બજાર શોધવાની અને બજાર ઊભું કરવાની જરૂરિયાત પણ જણાઈ.

બીજા વર્ષથી વધુ ૫ ગામોને અને તેમની ૭૫ મહિલાઓને આવરી લેવાયાં. દરેક જૂથમાં ૧૫ મહિલા એમ વધુ ૫ જૂથોની રચના કરવામાં આવી. સભ્યોની કુલ સંખ્યા એ સમયે વધીને ૧૭૫ થઈ અને પછી તે ૧૯૯૪માં ૨૫૦ થઈ, જ્યારે કુલ જૂથની સંખ્યા ૨૦ થઈ. ‘એક્શન એઈડ-ઈન્ડિયા’ એ આ સાહસને ટેકો પૂરો પાડ્યો. નવા સભ્યોને તાલીમપ્રાપ્ત સભ્યોએ પ્રશિક્ષણ આપ્યું.

૧૦ ગ્રામ સ્તરીય કાર્યકરોની ભરતી કરવામાં આવી અને તેમને ગુણવત્તા નિયંત્રણ, સમયસર કાચા માલના પુરવઠાની વ્યવસ્થા અને સભ્યોને વેતનની વહેંચણીનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. તૈયાર થનારી વસ્તુને નવો જ આકાર આપવા એક વ્યવસાયી ડિઝાઈનરની ભરતી કરવામાં આવી. આધુનિક ડિઝાઈન અને બજારની માંગ અનુસાર તે માર્ગદર્શન પૂરું પાડે એ અપેક્ષિત હતું. જૂથના સભ્યોએ જૂથની અંદર જ ધિરાણની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે સ્વસહાય જૂથ (સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ-એસ.એચ.જી)ની રચના કરી. જૂથોની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ સ્વસહાય જૂથો સાથે સંબંધિત હતી. આથી ખાનગી વેપારીઓ અને શાહુકારોનો પ્રભાવ ઘટાડવામાં મદદ મળી.

‘સ્યોર’ સાથેના સહયોગમાં મહિલાઓએ તેમનાં પોતાનાં ગામોમાં અનૌપચારિક ઉત્પાદન કેન્દ્રો વિકસાવ્યાં છે. મહિલાઓ સાથે બેસીને રોજના ૪-૫ કલાક કામ કરે છે. સાથે મળીને કામ કરવાથી તેઓ વસ્તુની ડિઝાઈન અને તેની ગુણવત્તા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી થઈ છે. આ તબક્કા દરમ્યાન વિવિધ પેઢીઓ તરફથી નિકાસ માટેના ઓર્ડર પણ મળ્યા છે. ઉત્પાદકો જેમાં પોતાની ચીજોનું વેચાણ કરે છે એવા અનેક મેળાઓની ખબર પણ ‘સ્યોર’ને પડી છે.

બજારના અત્યંત નબળા પ્રતિભાવ અને ભારે સ્પર્ધા છતાં ‘સ્યોર’ દ્વારા એક વર્ષમાં ૪થી ૬ માસ સુધી લગભગ ૨૫૦ મહિલાઓને રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવી છે. જૂથની રચનાની પ્રક્રિયા અને નિયમિત મળતી જૂથની બેઠકોએ સ્ત્રીઓમાં વિશ્વાસ વધાર્યો છે. ઉત્પાદન કેન્દ્રોના વિકાસને કારણે અને સામૂહિક રીતે કામ થતું હોવાને લીધે મહિલાઓમાં માલિકિયતની ભાવના પ્રબળ બની છે. પરંતુ ‘સ્યોર’ને લાગે છે કે આ પ્રક્રિયાથી મહિલાઓ હજુ પૂરતી સક્ષમ બની નથી કારણ કે પ્રવૃત્તિનું સંચાલન મહિલાઓનાં જૂથો દ્વારા થતું નથી.

ચાલુ તબક્કાના અનુભવને આધારે ‘સ્યોર’ને એમ લાગે છે કે જૂથના સભ્યોને પ્રવૃત્તિના સંચાલનનાં પાસાં અંગે યોગ્ય તાલીમ આપવાની

જરૂર છે. સક્રિય સભ્યોને પૂરતો અવકાશ અને તક પૂરાં પાડવામાં આવે તો અને વિકેન્દ્રીકરણની પ્રક્રિયામાં તેમની સક્રિય સામેલગીરી કરાય તો એ શક્ય બની શકે તેમ છે.

તૃતીય તબક્કો

મહિલા જૂથોનું ક્ષમતા વર્ધન

દિલ્હીની એક સંસ્થા ‘ઉદ્યોગિની’ એ આ જૂથોને ક્ષમતા વર્ધનમાં જરૂરી ટેકો પૂરો પાડવાની જવાબદારી ઉપાડી. એમણે સાહસનું સંચાલન અને સંચાલન અંગેનાં અન્ય પાસાંના ક્ષેત્રે આ ટેકો પૂરો પાડ્યો.

જૂથના સભ્યોને વિવિધ મેળાઓમાં હાજરી આપવા માટે પ્રોત્સાહન અપાયું કે જેથી ગ્રાહકો સાથે તેઓ સીધા સંપર્કમાં આવે અને તેઓ કઈ બાબતો વિશે ચિંતિત છે એ જાણે અને એ બાબતોનો ઉકેલ લાવવા વિચારે. ‘સ્યોર’ દ્વારા કરાયેલા આ પ્રયાસોથી મહિલાઓનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે. દિલ્હીની બીજી એક સંસ્થા ‘દસ્તકાર’ પણ તેમને ડિઝાઈનની બાબતમાં ટેકો આપીને તેમની ક્ષમતા વધારી રહી છે.

આ તબક્કા દરમ્યાન વિવિધ નિકાસકાર પેઢીઓ તરફથી નિકાસ માટેના ઓર્ડર મળ્યા છે. મોટી કંપનીઓ તેમનાં બ્રાન્ડ નામો સાથે બજારમાં છે અને તેમની સામેની તીવ્ર સ્પર્ધાનો સામનો કરવાનો હોય છે. તેઓ ઘણું મોટું બજાર કબજે કરીને બેઠેલી છે. નયતાલા ગામના એક મહિલા જૂથને વિકેન્દ્રીકરણ અને ક્ષમતા વર્ધનના ભાગરૂપે સ્વતંત્રપણે કામ કરતું કરાયું છે.

૩. ૧૦ લાખનો તૈયાર માલ ભેગો થઈ ગયો ત્યારે ખરી સમસ્યા ઊભી થઈ. મહિલાઓનાં જૂથોને પ્રોત્સાહન આપવા અને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાના સંચાલન માટે ‘સ્યોર’ દ્વારા વ્યવસાયી ટેકો પૂરો પાડવામાં આવ્યો જ છે. નિયમિત ધોરણે સલાહ મેળવવા માટે પૂર્ણ સમયના ડિઝાઈનર અને મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. દરેક પ્રકારની વસ્તુમાં કેટલું ખર્ચ કરવામાં આવ્યું છે તે શોધી કાઢવા, જથ્થો ગણવા તથા ભાવ નક્કી કરવા વગેરે માટે નિશ્ચિત વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. બજાર અંગેની માહિતી વ્યવસ્થિતપણે મળે તે માટેનું તંત્ર ઊભું કરાયું છે કે જેથી તૈયાર માલ વેચાણ માટે મોકલાય અને ગ્રાહકોની અભિરુચિની માહિતી પણ મળે. આ પ્રક્રિયા દરમ્યાન મહિલાઓને એ પણ ખબર પડી કે તેમની ભૂમિકા શી છે. ‘સ્યોર’ દ્વારા જે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તે અને તાજેતરમાં તેમાં જે વ્યવસાયીપણું દાખલ કરવામાં આવ્યું છે તે યોગ્ય અને સાનુકૂળ પરિણામો આપે છે કે કેમ તે હવે જોવાનું રહે છે.

રજૂઆત : સુજીત સરકાર, ઉગ્રતિ.

સાંપ્રત પ્રવાહ

ગાંધીવાદી રચનાત્મક કાર્યકર શ્રી નારણભાઈ રાઠોડને ભાનુભાઈ અધ્વર્યુ એવોર્ડ અર્પણ :

૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૯૮ને રવિવારના રોજ અમદાવાદના મહેંદી નવાઝ જંગ હોલમાં ૧૯૯૭નો ભાનુભાઈ અધ્વર્યુ એવોર્ડ - અર્પણ સમારંભ યોજાઈ ગયો. શ્રી ભાનુભાઈ અધ્વર્યુ આજીવન શિક્ષક અને ગુજરાતના દલિતો-પીડિતો-વંચિતોના સંગઠક તથા માર્ગદર્શક હતા. તેઓ તેજસ્વી, લોકાભિમુખ અને લોકપ્રિય પત્રકાર પણ હતા. તેમના સ્મરણ અર્થે આ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. ડાંગ-વલસાડના દુર્ગમ વિસ્તારોમાં આશરે ૫૫ વર્ષ સુધી સંનિષ્ઠપણે કાર્યરત રહેનારા, સતત સંઘર્ષશીલ, ગાંધીવાદી રચનાત્મક કાર્યકર નારણભાઈ માધવભાઈ રાઠોડને ૧૯૯૭નો ભાનુભાઈ અધ્વર્યુ એવોર્ડ અર્પણ થયો. નીડર અને નિઃસ્વાર્થ લોકસેવક નારણભાઈ રાઠોડને મળવું એ એક લહાવો છે. દેશને આઝાદ કરવા માટે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં અનેક લોકોએ ભાગ લીધો. એમાંથી જે લોકસેવકો મળ્યા તેમાંના કેટલાક મૂકસેવક હતા. નારણભાઈએ પ્રસિદ્ધિની કશી જ ખેવના રાખ્યા વગર, નિષ્ઠાપૂર્વક આખું જીવન રચના અને સંઘર્ષનાં કામોને સમર્પિત કર્યું છે. નારણભાઈએ સ્વાતંત્ર્ય-સંગ્રામમાં ભાગ લીધો, ખાદી-ગ્રામોદ્યોગની પ્રવૃત્તિ કરી, બે ટર્મ સુધી ધારાસભ્યપદે રહીને દલિતો-આદિવાસીઓની અનેક સમસ્યાઓ અંગે કામ કર્યું છે. વળી, હરિજન સેવક સંઘથી માંડીને ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ આર્થિક વિકાસ નિગમના અધ્યક્ષ તથા રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાની અનેક સમિતિઓમાં સભ્ય તરીકે સેવાઓ આપીને રાજકીય-સામાજિક ક્ષેત્રે ઘણું પ્રદાન કર્યું છે.

જાણીતા પત્રકાર શ્રી બટુકભાઈ દેસાઈના પ્રમુખ સ્થાને યોજાઈ ગયેલા આ સમારંભમાં પ્રખર સાહિત્યકાર-પત્રકાર શ્રી પ્રકાશભાઈ ન. શાહ,



અને ભાવનગર યુનિવર્સિટીના કુલપતિશ્રી વિદ્યુતભાઈ જોષીએ વિશેષ આમંત્રિતો તરીકે ઉપસ્થિત રહીને મનનીય વક્તવ્યો આપ્યાં હતાં. જનપથના પ્રમુખશ્રી રાજેશ શાહના ઉષ્માભર્યા સ્વાગત પ્રવચનથી આ એવોર્ડ-અર્પણ સમારોહનો પ્રારંભ થયો હતો. પ્રા. શ્રી હર્ષદભાઈએ સન્માનપત્રનું વાચન કર્યું હતું. શ્રી ઈન્દુકુમાર જાનીએ શરૂઆતથી અત્યાર સુધી, ભાનુભાઈ એવોર્ડ મેળવનાર મહાનુભાવોનો પરિચય આપીને એવોર્ડનું ગૌરવસ્થાપન કર્યું હતું. શ્રી નારણભાઈનો વિસ્તૃત જીવન-કાર્ય પરિચય આપ્યા પછી ઈન્દુભાઈએ અંતે ઝવેરચંદ મેઘાણીની કવિતા 'છેલ્લી પ્રાર્થના' ગાઈ સંભળાવીને વાતાવરણ જોમવંતું બનાવી દીધું હતું. માનનીયશ્રી નારણભાઈએ પોતાના સન્માનનો પ્રત્યુત્તર વાળતાં નિખાલસ અને જુસ્સાભરી વાણીમાં હૃદયસ્પર્શી પ્રવચન કર્યું હતું. તેમાંથી તેમના નમ્ર વ્યક્તિત્વની પારદર્શકતા અને કર્મશીલ તરીકેની પ્રતિબદ્ધતા નીતરતાં હતાં. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના સંગઠન 'જનપથ' અને પ્રગતિશીલ સામયિક 'નયામાર્ગ'ના ઉપક્રમે ૧૯૯૩માં 'ભાનુભાઈ અધ્વર્યુ સ્મૃતિ સમિતિ' રચાઈ હતી. સમાજ પરિવર્તનના કામમાં પાયાના કાર્યકરની ભૂમિકા ભજવનાર નિષ્ઠાવાન કર્મશીલને દર વર્ષે આ સમિતિના ઉપક્રમે રૂ. ૧૧, ૦૦૦/-નો પુરસ્કાર અને સન્માન-પત્ર અર્પણ કરવામાં આવે છે. ૧૯૯૩માં સૌ પ્રથમ વાર આ એવોર્ડ ધરમપુર, વલસાડના મંછુભાઈ ગામીતને, ૧૯૯૪માં વી.ટી.પરમારને અને ૧૯૯૫માં પ્રા. પાનાચંદ પરમારને એનાયત થયો હતો. ૧૯૯૬માં આ એવોર્ડ માટે કોઈની પસંદગી કરાઈ ન હતી.

સમારંભમાં ગુજરાતભરની જુદી જુદી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના કર્મશીલોએ ભાગ લીધો હતો. જનપથના મંત્રી શ્રી પ્રફુલ્લભાઈએ સૌનો આભાર માનીને સમાપન કર્યું હતું.

સંવાદ - વિકાસ મેળો :

૨થી ૫ જાન્યુઆરી, ૧૯૯૮ દરમ્યાન અમદાવાદ ખાતે સંવાદ - વિકાસ મેળો યોજાઈ ગયો. અમદાવાદ સ્થિત સ્વૈચ્છિક સંસ્થા 'ચેતના - સેન્ટર ફોર હેલ્થ એજ્યુકેશન ટ્રેનિંગ એન્ડ ન્યુટ્રીશન અવેરનેસ'ના ઉપક્રમે સંસ્કાર કેન્દ્ર, પાલડી ખાતે યોજાઈ ગયેલા આ મેળામાં ગુજરાતની જુદી જુદી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, ઔદ્યોગિક ગૃહો અને જુદા જુદા સરકારી વિભાગોએ પોતાની પ્રવૃત્તિઓનું નિદર્શન કર્યું હતું.

આઝાદીની સુવર્ણજયંતી નિમિત્તે યોજાયેલા આ વિકાસમેળામાં સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, ઔદ્યોગિક ગૃહો અને સરકારી વિભાગો મળીને કુલ ૪૬

એકમોએ ભાગ લીધો હતો તેમાં ઉન્નતિએ પણ ભાગ લીધો હતો. વિકાસ મેળાનો હેતુ વિકાસની દિશામાં કાર્યરત કર્મશીલો અને આમજનતા વચ્ચે વિકાસને લગતા સંવાદની શરૂઆત કરવા માટેનો એક મંચ પૂરો પાડવાનો હતો. ઉપરાંત, તેઓ એકબીજાના દૃષ્ટિકોણ જાણી શકે અને નીતિવિષયક પરિવર્તન માટે પ્રયત્નો અને પ્રગતિ કરી શકે તે પણ 'સંવાદ' નો હેતુ હતો. મેળાનું ઉદ્ઘાટન જાણીતા સામાજિક-કાર્યકર અને અભિનેત્રી શ્રી શબાના આઝમી દ્વારા થયું હતું. મેળા દરમ્યાન 'વિકાસમાં ભાગીદારી' તથા 'બિનસરકારી સંસ્થાઓ અને વ્યવસાયિકતા' વિષયો ઉપર ચર્ચા-ગોષ્ઠી યોજાયાં હતાં. મેળા દરમ્યાન રોજ સાંજે અમદાવાદની કલા સંસ્થા 'દર્પણ અકાદમી' દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ રજૂ થયા હતા.



'સંવાદ' મેળામાં બાળકોનો 'બાલ વાટિકા' વિભાગ ધ્યાન ખેંચે તેવો હતો. તેમાં ચિત્રકામ, રંગકામ, ચમત્કારો પાછળ રહેલું વિજ્ઞાન દર્શાવતાં નિદર્શનો વગેરે પ્રવૃત્તિઓ યોજાઈ હતી. તેમાં 'ચેતના' દ્વારા બાળકો માટે પોષણ અને સ્વાસ્થ્યલક્ષી રમતોનું આયોજન થયું હતું. મેળાના અંતિમ દિવસે મેળાનું મૂલ્યાંકન થયું હતું. તેમાં જુદા જુદા સામાજિક કાર્યકરો અને મેળામાં ભાગ લેનારા લોકોએ પોતાનાં સૂચનો આપ્યાં હતાં.

આદિવાસી સ્વશાસન વિશે યોજાયેલ પરિસંવાદ

તા. ૪ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૮૮ના રોજ ઉન્નતિએ આદિવાસી સ્વશાસનના મુદ્દા પર એક સેમિનારનું આયોજન કર્યું હતું. તેમાં આદિવાસી વિસ્તારમાં કામ કરતી સ્વયંસેવી સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ, આ વિષયમાં રુચિ ધરાવતા નિષ્ણાતો, આદિવાસીઓની જીવનશૈલી પર સંશોધન કરનાર સંશોધકો તથા પત્રકારે હાજરી આપી હતી.

તા. ૨૦ ડિસેમ્બર, ૧૯૮૭ના રોજ ગુજરાત સરકારે અનુસૂચિત વિસ્તારો માટેના અધિનિયમ તરીકે વટહુકમ બહાર પાડ્યો છે. તેને અનુલક્ષીને આ સેમિનાર યોજાયો હતો. સેમીનારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આ વટહુકમને સમજવો તથા તેને આદિવાસી અનુકૂળ બનાવવા સરકારને સૂચનો કરવાનો હતો.

શ્રી પી. બાસુ. (એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી)એ સેમિનારમાં ઉપસ્થિત રહી સહભાગીઓના સૂચનો સાંભળ્યાં તથા આ વટહુકમમાં જરૂરી સુધારાઓ દાખલ કરવા માટે એક સમિતિ બનાવી તેના પર ફરીથી ચર્ચા વિચારણા કરવી એમ નક્કી થયું હતું. ગુજરાતના ઈતિહાસમાં કદાચ પ્રથમ વાર કાયદો બનાવવા સ્વયંસેવી સંસ્થાઓનાં સૂચનો ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.

સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓએ ગુજરાત રાજ્ય નાણાં પંચને સુપરત કરેલું આવેદનપત્ર:

ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૮૩માં કરાયેલી જોગવાઈ અનુસાર રાજ્ય સરકારે દર પાંચ વર્ષે પંચાયતો નગરપાલિકાઓ તથા મહાનગરપાલિકાઓને રાજ્ય સરકાર તરફથી નાણાંની ફાળવણી કરવા માટે એક રાજ્ય નાણાંપંચની નિમણૂક કરવી ફરજિયાત છે. આ મુજબ ૧૯૮૩થી રાજ્ય સરકારે નાણાંપંચની રચના કરી છે.

તા. ૮ જાન્યુઆરી ૧૯૮૮ના રોજ 'પશ્ચિમ ભારત પંચાયતી રાજ મંચ' તરફથી આ નાણાં પંચના સભ્ય પ્રોફેસર શ્રી મહેશ ભટ્ટને સ્વયંસેવી સંસ્થાઓએ મળીને પંચાયતને લગતી નાણાકીય જોગવાઈ અંગેના સૂચનો સુપરત કર્યાં હતાં. ત્યાર બાદ તા. ૨૨, જાન્યુઆરી ૧૯૮૭ના રોજ છ વ્યક્તિઓની બનેલ સમિતિએ સમગ્ર નાણાંપંચ સમક્ષ આ સૂચનોનું આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું. તેમાં સૂચનો ઉપર સંયુક્ત ચર્ચા બાદ યોગ્ય અને વ્યાવહારિક સૂચનોનો નાણાં પંચે સ્વીકાર કરવાની ખાતરી આપી હતી. પંચાયતો આર્થિક રીતે સદ્ધર બને અને સ્થાનિક સ્તરે સરકાર તરીકે અસરકારક રીતે કામ કરી શકે તેવી નાણાકીય ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે તે હેતુ સાથે આ સૂચનો કરવામાં આવ્યાં હતાં. શાસનની નાણાંવ્યવસ્થામાં પ્રથમવાર આ રીતે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓએ પોતાની સક્રિય ભૂમિકા અદા કરી હતી.

થોમસ કોચરીએ નકારી કાઢેલો એવોર્ડ :

ભારતના ૮૦ લાખ માછીમારોના અધિકારો માટે જંગે ચડનારા ૫૭ વર્ષીય અમેરિકાના પેવ ફાઉન્ડેશન ઓફ મેસેચ્યુસેટ્સની ૧.૫૦ લાખ ડોલરની ફેલોશિપ નકારી કાઢીને સમાચારોમાં ચમક્યા હતા. તેઓ તાજેતરમાં જ 'વર્લ્ડ ફોરમ ઓફ ફિશ વર્કર્સ એન્ડ ફિશ હાર્વેસ્ટર્સ' (ડબ્લ્યુએફએફ)ના મહાસંયોજક તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટાયા છે. દુનિયાભરના ૧૦ કરોડ માછીમારોના અધિકારો માટે લડવા આ ફોરમની રચના કરવામાં આવી છે. તેમણે શા માટે ફેલોશિપ ફગાવી દીધી એવું પૂછવામાં આવતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "આ એવોર્ડ એ અમારા આંદોલનની સ્વીકૃતિ છે પણ આ એવોર્ડ સાથે સંકળાયેલાં નાણાંનો અર્થ કંઈક જુદો જ છે. ફિલાડેલ્ફિયાના આ પેવ ફાઉન્ડેશનને 'સન' નામની એક તેલ કંપની નાણાં આપે છે અને તેણે કેટલાંય વર્ષોથી દરિયાઈ પ્રદૂષણ ફેલાવ્યું છે. એક પ્રદૂષક પર્યાવરણના જતન માટે એવોર્ડ આપે એ વિરોધાભાસ છે. એક પ્રદૂષક કંપની પાસેથી

એવોર્ડ સ્વીકારવો એ અનૈતિક છે. મહત્વનું તો એ છે કે માછીમારોની જિંદગીને જોખમમાં મૂકતાં પરિબળો સામે લડવું.”

(સ્રોત : ડાઉન ટુ અર્થ, માર્ચ-૧૯૯૮)

‘વૈશ્વિક પર્યાવરણ સવલત’ની પ્રથમ સભામાં :

‘વૈશ્વિક પર્યાવરણ સવલત’ (ગ્લોબલ એન્વાયર્નમેન્ટ ફેસિલિટી-જીઈએફ)ની ૧૯૯૧ સભ્ય દેશોની પ્રથમ સભા ૧થી ૩ એપ્રિલ-૧૯૯૮ દરમ્યાન નવી દિલ્હીમાં મળી રહી છે. તેની સ્થાપના ૧૯૯૧માં થઈ હતી અને તે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ(યુએનડીપી), સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ (યુએનઈપી) અને વિશ્વ બેંકની એક સંયુક્ત પરિયોજના છે. તેનું કામ પર્યાવરણની સમસ્યાઓનો ઉકેલ શોધવાનું છે. તેમાં ત્રણ સ્તરે વહીવટની સંકુલ વ્યવસ્થા છે. તેનું મુખ્ય સંચાલક મંડળ ‘કાઉન્સિલ’ (પરિષદ) છે. તેમાં ૧૯ વિકસતા દેશોમાંથી, ૧૪ વિકસિત દેશોમાંથી અને ૨ બહુરાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રોમાંથી સભ્યો છે. ‘એસેમ્બલી’ (સભા)માં તમામ સભ્ય દેશો છે. સચિવાલય પરિષદ, સભા અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ વચ્ચે મધ્યસ્થી કરે છે. ‘સભા’ એપ્રિલમાં ‘પરિષદ’ના સભ્યોએ જે પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરવાની છે તેને વિશે ચર્ચા કરશે. આગામી બેઠકમાં તેણે દાતાઓને પ્રદૂષકો છોડવા અંગેના મુદ્દા અને જૈવિક વિવિધતાના જતન અંગેના વિકસતા દેશો સામેના પર્યાવરણીય પડકારો અંગે પ્રતિભાવ આપવા મનાવવાના છે. બીજો એક એ મુદ્દો ઉઠાવવાની જરૂર છે કે વિવિધ સરકારો દ્વારા હાથ પર લેવાયેલી પરિયોજનાઓની જવાબદારી કોણ કેટલી લે. સરકારો સર્વસામાન્ય પર્યાવરણીય પ્રશ્નો અંગે વાટાઘાટો કરવા અક્ષમ છે કારણ કે જીઈએફ એક એવું ફોરમ બની ગયું છે કે જ્યાં તેમણે નાણાં

માટે એકબીજા સાથે સ્પર્ધામાં ઊતરવું પડે છે. વિકસતા દેશોની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ આરંભથી જીઈએફની સ્થાપનાનો વિરોધ કરતી રહી છે કારણ કે કઈ પરિયોજના માટે નાણાં આપવાં તેમાં વિશ્વ બેંક મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જો કે, હાલની ‘સભા’માં મોટા ભાગની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓને નિમંત્રણ અપાયું નથી પરંતુ માત્ર ૨૮ જેટલી જ સંસ્થાઓને હાજર રહેવા માટે નાણાં અપાઈ રહ્યાં છે. આથી વિકસતા દેશોની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ ચોંકી ગઈ છે અને તેથી તેઓ માત્ર જીઈએફની નાણાં પૂરાં પાડવાની પદ્ધતિ સામે જ વાંધો નથી ઉઠાવતી પરંતુ પર્યાવરણના જતન અંગેની તેની ચિંતા સામે જ શંકા ઉઠાવે છે. તા.૬-૧-૧૯૯૮ના રોજ જીઈએફના હટન આર્શર અને એલેક્ઝાન્ડ્રિયા બેઝેદી નવી દિલ્હીમાં અનેક સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓને ‘પરિષદ’ની બેઠક માટેની કાર્યસૂચિ તૈયાર કરવા માટે મળ્યા હતા. આ બેઠકમાં જ જીઈએફના પ્રતિનિધિઓ સામે અનેક ફરિયાદો કરવામાં આવી હતી. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓએ એવી ફરિયાદ કરી કે પરિયોજનાઓ માટેનાં નાણાં મંજૂર કરવામાં આવતાં નથી અને આ પરિયોજનાઓ સંબંધી પત્રવ્યવહારને અવગણવામાં આવે છે. જેમણે આ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો તેમાં સોસાયટી ફોર ધ પ્રમોશન ઓફ વેસ્ટલેન્ડ ડેવલપમેન્ટ (એસપીડબ્લ્યુડી), વર્લ્ડ વાઈલ્ડલાઈફ ફંડ (ડબ્લ્યુડબ્લ્યુએફ) - ઈન્ડિયા, ડેવલપમેન્ટ ઓલ્ટર્નેટિવ્ઝ, પાર્ટિસિપેટરી રિસર્ચ ઈન એશિયા (પીઆરઆઈએ) અને રણથંભોર ફાઉન્ડેશનનો સમાવેશ થાય છે. (સ્રોત : ડાઉન ટુ અર્થ, માર્ચ-૧૫, ૧૯૯૮.)

પૃષ્ઠ ૧૯નો શોષ ભાગ

સુધારા કરવા અને સંસ્થાને ફરી ચેતનવંતી બનાવવી એ વિશ્વ બેંકમાંના અને વિશ્વ બેંકની પરિયોજનાઓનો અમલ કરનારી ઘણી સરકારી સંસ્થાઓમાંના સંસ્થાગત સુધારામાં મહત્વની બાબત બની રહે છે.

તત્કાળ પગલાં લેવા માટેનાં જરૂરી ક્ષેત્રો

ઉપરોક્ત મેળવેલી શીખનાં સંદર્ભમાં વિશ્વ બેંકે જે ક્ષેત્રોમાં તાકીદના ધોરણે કામ કરવાનું છે તે નીચે મુજબ છે:

૧. વિશ્વ બેંકનું વડું મથક તેમ જ જે તે દેશ અને પ્રદેશમાંની તેની કચેરીઓએ માહિતીના પ્રસારની બાબતમાં વધુ સક્રિય થવાનું છે. આરંભમાં, પ્રાદેશિક સહભાગિતા કાર્યલક્ષી યોજનાઓમાં (આર.પી.એ.પી.) જે નીતિવિષયક બાબતો અને પરિયોજનાઓ અંગે માહિતીના પ્રસાર માટે સક્રિયતા કેવી રીતે દાખવવી તેની યોજના

ઘડવા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. આ કામ કાર્યકારી જૂથ સાથે મળીને થઈ શકે કે જેથી બંનેના પ્રયાસોનું સંકલન કરી શકાય.

૨. વિશ્વ બેંકે સહભાગિતા સંયોજકોની નિશ્ચિત ભૂમિકા અને કાર્યકારી જૂથના પ્રાદેશિક વિભાગો સાથેના તેમના સંબંધો અંગે વિશ્વ બેંકે સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ. માહિતીના પ્રવાહ અને વ્યવસ્થા અંગેના ઉત્તરદાયિત્વ અંગે પણ સ્પષ્ટતા થવી ઘટે.

૩. દેખરેખ અને ક્ષમતા નિર્માણ મહત્વના પ્રશ્નો છે. વિશ્વ બેંકે જે તે દેશમાં એને માટેની પ્રક્રિયાને ટેકો આપવો જોઈએ. ક્ષમતા નિર્માણ માટેનું વાતાવરણ ઊભું થાય તે માટેનાં વિવિધ પાસાંઓ અંગે જે તે દેશમાં ત્રિપક્ષી સંવાદ થાય તે માટેનો માર્ગ તેનાથી પ્રશસ્ત થશે.

ડૉ. રાજેશ ટંડન દ્વારા રજૂ થયેલું મંતવ્ય ‘ગ્લોબલ એલાયન્સ ન્યૂઝ, ડિસેમ્બર, ૯૬’ના અંકમાંથી લેવામાં આવ્યું છે.

આગામી કાર્યક્રમ

સામાજિક સંચાલકો માટે તાલીમ કાર્યક્રમ

જુન-૧૯૮૮થી જાન્યુઆરી-૧૯૯૯ દરમ્યાન (૯ મહિનાનો) વિકાસને લગતા અનેક વિષયો અને મુદ્દાઓને આવરી લેતો એક લાંબા ગાળાનો સઘન કાર્યક્રમ બિહેવિયરલ સાયન્સ સેન્ટર-અમદાવાદ ખાતે યોજવામાં આવી રહ્યો છે. તેનો મુખ્ય હેતુ વિકાસલક્ષી સંસ્થાઓના કાર્યના પરિપ્રેક્ષ્ય તરીકે સમાજના શોષણના માળખાની પાયાની સમજણ આપવાનો તથા વિકાસના ક્ષેત્રમાં સાંપ્રત સમસ્યાઓ, શોષણનું દેશવ્યાપી સ્વરૂપ અને સામાજિક-રાજકીય લોક ચળવળોને સમજીને સંસ્થાઓના કાર્યને દિશાસૂચન પૂરું પાડવાનો છે.

આ કાર્યક્રમમાં સમસ્યાઓની બૌદ્ધિક સમજણ ઉપરાંત આ ક્ષેત્રને લગતી જાણકારી અને આવડતોનો વિકાસ, સરકારી નીતિઓને અસર કરીને લોકહિતને ટેકો આપવા એડવોકેસી, નેટવર્કિંગ વિશે જાણકારી, જૂથ વર્તન અને સાંગઠનિક વ્યવહારને લગતી તાલીમ, સંસ્થાઓનાં પોતાનાં સંચાલન માટે નાણાકીય વ્યવસ્થા, ફંડિંગ, બજેટ વગેરે અંગે તાલીમ આપવામાં આવશે. કાર્યક્રમના અંતે દરેક તાલીમાર્થી માટે કોઈ એક ગ્રામીણ વિસ્તારમાં કોઈ નક્કર પ્રોજેક્ટ લઈ તે દ્વારા અભ્યાસ માટેની વ્યવસ્થા થશે.

આ કાર્યક્રમમાં સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના સંચાલકો સ્થાનિક સંગઠનો અને જૂથોના અનુભવી કાર્યકરો સભ્યો તેમ જ વિકાસના ક્ષેત્રમાં રસ ધરાવતા બિનઅનુભવી કાર્યકરો પણ ભાગ લઈ શકશે. જરૂરિયાત પ્રમાણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ક્ષેત્રીય અનુભવની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરશો. અનિતા કે. દીક્ષિત, બિહેવિયરલ સાયન્સ સેન્ટર, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯. ફોન નં. ૪૬૪૯૨૮ ફેક્સ ૬૫૬૧૮૪૫.

પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના ક્ષમતાવર્ધન માટેનો તાલીમ કાર્યક્રમ

સ્વયંસેવી સંસ્થાઓના કાર્યકર્તાઓ માટે પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના ક્ષમતાવર્ધન ઉપર ઉન્નતિ દ્વારા એક તાલીમ કાર્યક્રમનું આયોજન તા. ૨૭થી૩૦ મે, ૧૯૯૮ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. આ તાલીમ કાર્યક્રમના મુખ્ય બે ઉદ્દેશ છે: ૧. પંચાયતી રાજ ઉપર સમજ વિકસાવવી. ૨. ગ્રામીણ વિકાસના કાર્યક્રમમાં પંચાયતોને સાથે લઈ કામ કરવા અંગેની ક્ષમતા વિકસાવવી. તાલીમમાં મુખ્યત્વે નવો પંચાયત અધિનિયમ, સ્વશાસન, શાસનમાં મહિલાઓની ભાગીદારી, શાસનમાં પારદર્શિતા વગેરે વિષયોને આવરી લેવામાં આવશે. તાલીમ કાર્યક્રમમાં સ્વયંસેવી સંસ્થામાં બે વર્ષના કામનો અનુભવ હોય તેવા કાર્યકર્તાઓ ભાગ લઈ

શકશે. કાર્યક્રમની નોંધણી ફી રૂ. ૫૦૦/- છે. કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા ઈચ્છતી સંસ્થાએ સંપર્ક કરવો : ઉન્નતિ, અમદાવાદ.

રણનીતિક આયોજન (સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ) અંગે કાર્યશાળા

ગુજરાતની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ માટે વ્યૂહાત્મક આયોજન અંગે ૨૭થી૫ જુન-૧૯૯૮ દરમ્યાન એક કાર્યશાળાનું આયોજન કરાશે. આ કાર્યશાળાના હેતુઓ નીચે મુજબ રહેશે :

૧. સંસ્થાઓને તેમના હેતુઓ અને કાર્યક્ષેત્ર તેમની આંતરિક ક્ષમતાના સંદર્ભમાં સ્પષ્ટ કરવા માટે સક્ષમ બનાવવી. ૨. સંસ્થાની તાકાત અને નબળાઈઓના સંદર્ભમાં બાહ્ય માહોલનું વિશ્લેષણ કરવા સંસ્થાઓને સક્ષમ બનાવવી. ૩. વ્યૂહાત્મક ઉદ્દેશો, પ્રશ્નો / મુદ્દાઓ અને સંસાધનોની જરૂરિયાતો નક્કી કરવા સંસ્થાઓને સક્ષમ બનાવવી. ૪. સંસ્થાઓને તેમની પોતાની વ્યૂહાત્મક યોજનાઓ તૈયાર કરવા અને વિકસાવવા સક્ષમ બનાવવી. ઉપરોક્ત કાર્યક્રમ માટે સહભાગી દીઠ રૂ. ૫૦૦ની ફી રહેશે. વિગતો માટે સંપર્ક સાધો : ઉન્નતિ.

૩. સહભાગી દેખરેખ અને મૂલ્યાંકન (મોનિટરિંગ એન્ડ ઈવેલ્યુએશન) અંગે કાર્યશાળા

ગુજરાતની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ માટે ૧૭-૨૦, ઓગસ્ટ-૧૯૯૮ દરમ્યાન સહભાગી દેખરેખ અને મૂલ્યાંકન (મોનિટરિંગ એન્ડ ઈવેલ્યુએશન) અંગે એક કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યશાળાના મુખ્ય હેતુઓ નીચે મુજબ છે :

૧. દેખરેખ અને મૂલ્યાંકનમાં સહભાગી પદ્ધતિઓ વિશે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓની વિભાવનાત્મક સમજ વિકસાવવી. ૨. સંસ્થાની અંદર સહભાગી દેખરેખ અને મૂલ્યાંકનની પદ્ધતિ ઊભી કરવાનું કૌશલ્ય સ્વૈચ્છિક સંસ્થામાં વિકસાવવું. સહભાગી દીઠ રૂ. ૫૦૦ની ફી રાખવામાં આવી છે. વધુ વિગતો માટે સંપર્ક સાધો : ઉન્નતિ.

નોંધ :

સંસ્થા સંચાલન (ઓર્ગનાઈઝેશનલ મેનેજમેન્ટ) અંગેનો કાર્યક્રમ જે તા. ૧૮થી ૨૧ મે, ૧૯૯૮ દરમ્યાન યોજાવાનો હતો તે અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે અચોક્કસ મુદત સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમની નવી તારીખ નક્કી થયા બાદ સંસ્થાઓને જણાવવામાં આવશે.

સંદર્ભ સાહિત્ય

લેસર હ્યુમન્સ : આ એક દસ્તાવેજી વિડિયો ફિલ્મ છે. તે 'વાલ્મિકી સમુદાય' ની માથે મેલું ઉપાડવા અંગેની વ્યાવસાયિક કામગીરી માટે જ્ઞાતિગત, આર્થિક, મહિલાલક્ષી પરિબળો તથા રાજ્યની ભૂમિકા કેવી રીતે જવાબદાર છે તેની તપાસ કરે છે અને તેનું વિશ્લેષણ કરે છે. ગુજરાતનાં ગામડાંમાં આ પ્રથા અમલમાં છે અને સ્ત્રીઓ ટોપલામાં મેલું માથે ઉપાડીને જતી આજે પણ જોવા મળે છે. આજે ૨૦મી સદીમાં આ જોવા મળે એ દુઃખ છે. આપણા દેશના અમુક વર્ગના લોકોને માનવીઓના મળનો નિકાલ કરવાના વ્યવસાયમાં ગુલામ બનાવી દેવાયા છે કારણ કે તેઓ એવા જૂથમાં જન્મ્યા છે કે જેઓ પરંપરાગત રીતે અતિ શુદ્ધ (લેસર હ્યુમન્સ) ગણવામાં આવે છે. 'લેસર હ્યુમન્સ' ફિલ્મને 'મુંબઈ ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ-૧૯૯૮'માં દ્વિતીય ક્રમે શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ ગણીને રજત ચંદ્રક એનાયત કરાયો છે. એની કેસેટ ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાતીમાં લેવાયેલી મુલાકાતોને અંગ્રેજી સબટાઈટલ સાથે દર્શાવાઈ છે.

રજૂઆત: નવસર્જન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ. નિર્માણ : દૃષ્ટિ મિડિયા કલેક્ટિવ, દિગ્દર્શન-સ્ટાલિન કે., સમય : ૫૯ મિનિટ, રૂ.૪૩૦. નકલ માટે સંપર્ક સાધો : દૃષ્ટિ, બી-૧, દિવ્યા એપાર્ટમેન્ટ્સ, શ્રદ્ધા પેટ્રોલ પંપ સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

રાજસ્થાનકી કૃષિમેં મહિલાઓંકી ભાગીદારી : રાજસ્થાનમાં સૂકી, પહાડી, પથરાળ જમીન, પથરાયેલી રેતી, ઓછો વરસાદ વગેરે જેવી પ્રતિકૂળ સ્થિતિ છતાંય આ પ્રદેશના ૪૭ ટકા જેટલા લોકો કૃષિ અથવા કૃષિ આધારિત પ્રવૃત્તિઓને સહારે પોતાની આજીવિકા કમાય છે. રાજસ્થાનમાં કોઈક જ એવો દાખલારૂપ ખેડૂત પરિવાર જોવા મળશે કે જેમાં બીજની વાવણીથી બીજના સંગ્રહ સુધીની પ્રક્રિયાના જુદા જુદા તબક્કે મહિલાઓએ શ્રમ દ્વારા પોતાનું યોગદાન ન આપ્યું હોય. પરંતુ આ વ્યાપક ભૂમિકા બાદ પણ ખેતીવાડીમાં મહિલાઓના યોગદાનને ના કેવળ આમ જનતા પરંતુ સરકાર પણ 'જોયું ન જોયું' કરે છે. ત્યાં સુધી કે સ્વયં ગ્રામીણ મહિલા પણ પોતાને કૃષિકાર્યથી જોડાયેલી વ્યવસાયી મહિલાના રૂપમાં ન જોતાં 'ઘરેલુ' કામ કરનાર મહિલા જ માને છે. આ સંદર્ભમાં ખેતીમાં મહિલાઓની ભૂમિકાને ઓળખવા અને પરિભાષિત કરવા માટે એક અધ્યયન કરવામાં આવ્યું. પૂર્વાયાજિક કુશવાહા અને એસ. રામનાથને આ અધ્યયનના નિષ્કર્ષને અને અધ્યયન દરમ્યાન તૈયાર કરવામાં આવેલા કેસ સ્ટડીઝને ત્રણ પુસ્તિકાઓની શૃંખલામાં પ્રસ્તુત કરી છે. પ્રથમ પુસ્તકમાં રાજસ્થાનમાં અધ્યયન ક્ષેત્રમાં ખેતીના કામ સાથે જોડાયેલી મહિલાઓની ભૂમિકાને પરિભાષિત કરી છે સાથે સાથે કૃષિવિસ્તારની પ્રવૃત્તિઓમાં મહિલાઓને જોડવાના રાજસ્થાન સરકારના પ્રયાસ પર નજર નાંખી છે. સાથે સાથે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપાતી કૃષક મહિલા તાલીમને

વધુ સારી બનાવવા સંબંધે કેટલાંક સૂચનો પણ આપ્યાં છે. દ્વિતીય તથા તૃતીય પુસ્તકમાં કેટલાક ખેડૂત બહેનોનાં વૃતાંત દર્શાવ્યાં છે. પુસ્તકની ભાષા હિન્દી છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક સાધો : એસ. રામનાથન ૪/૯૪, જવાહરનગર, જયપુર-૩૦૨૦૦૪ ફોન/ફેક્સ ૦૧૪૧-૬૫૨૬૩૧.

ગ્રામ પંચાયત ક્ષમતાવર્ધન તાલીમ સહાયક સામગ્રી : નવો પંચાયતી રાજ ધારો-૧૯૯૩, જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ સ્તરે સ્વશાસનના માળખાને મજબૂત કરવાનો ઉદ્દેશ ધરાવે છે. પંચાયતોએ પહેલી જ વાર બંધારણીય માન્યતા મેળવી છે. આ પરિવર્તન લોકોની માંગણીને લીધે નહિ પણ સંસદના સુધારા દ્વારા થયું છે. નવા કાયદામાં કરાયેલી જોગવાઈ અનુસાર વિકેન્દ્રિત ઢબે સ્વશાસન કરવા માટે સ્થાનિક સ્તરે તૈયારીનો અભાવ છે. સ્વશાસન અંગે પાયાની સમજ વિકસાવવા માટે 'ઉન્નતિ' એ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ માટે અનેક પુસ્તિકાઓ, પત્રિકાઓ અને વિડિયો કેસેટ તૈયાર કર્યાં છે. આ જ સંદર્ભમાં ઉન્નતિએ હાલમાં સ્વશાસનનાં સંદર્ભ, પ્રસ્તુતતા અને મહત્ત્વ વિશે સ્પષ્ટતાઓ કરતી તાલીમ સામગ્રીનો સંપુટ તૈયાર કર્યો છે. તે ચાર ભાગોમાં વહેંચાયેલો છે અને તે દરેક વિભાગ ક્રમશઃ નીચેના મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરે છે: ૧. વિકાસ એટલે શું ? ૨. વિકાસ ન થવા માટેનાં કારણો. ૩. વિકલ્પ શું છે ? ૪. નવો પંચાયતી રાજ ધારો : સ્વશાસનની દિશામાં. દરેક વિભાગમાં ૫ થી ૫૦ દૃશ્યો છે. તે ચર્ચા દરમ્યાન ઉપયોગી બનશે. તાલીમ દરમ્યાન કેવી રીતે આ ચિત્રોનો ઉપયોગ કરવો તેનું દરેક વિભાગ ઉપર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. તથા આ મુદ્દાઓને દરેક સંપુટ ઉપર વિસ્તૃત રીતે સમજાવવામાં પણ આવ્યાં છે. આ ચારે સંપુટો ગુજરાતી ભાષામાં છે. તેની કિંમત રૂ. ૨૫૦ છે. પ્રાપ્તિ સંસ્થાન : 'ઉન્નતિ'.

જલાગમ પ્રબંધન : વોટરશેડની યોજનાની પ્રક્રિયાને ઘણી સંસ્થાઓ ખૂબ ગુંચવાડા ભરી અને ટેકનિકલ માનીને તેનાથી મુંઝવણ અનુભવે છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને 'સોસાયટી ઓફ પીપલ ફોર ડેવલપમેન્ટ' દ્વારા આ પુસ્તિકા પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. આ પુસ્તિકામાં વોટરશેડથી સંબંધિત વિવિધ જાણકારી જેવી કે વોટરશેડ શું છે, વોટરશેડ શા માટે, વોટરશેડ પ્રબંધ, વોટરશેડના આધાર સ્તંભ તથા વોટરશેડનાં સંસાધનોની વિવરણિકાનો સમાવેશ કરાયો છે. આ જાણકારીને આ પુસ્તકમાં ખૂબ સરળ રીતે જ્યાં જરૂર છે ત્યાં રેખાચિત્રો અને આલેખ દ્વારા સમજાવાઈ છે. પુસ્તિકાની વિશિષ્ટતા એ છે કે તે એક સાથે જ બે ભાષામાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે. એક તરફ અંગ્રેજી છે અને બીજી તરફ ગુજરાતી પુસ્તિકાની કિંમત : રૂ. ૪૫ પ્રાપ્તિસ્થાન : સોસાયટી ઓફ પીપલ ફોર ડેવલપમેન્ટ ૫૮ દૂન વિહાર રાજપુર રોડ, દહેરાદૂન-૨૪૮૦૦૧. જુઓ પૃષ્ઠ ૨૫

પંચાયતી રાજના મુદ્દે અમે પંચાયતોની નાણાં વ્યવસ્થા અંગે તથા પંચાયત ધારો આદિવાસી વિસ્તારોને લાગુ પાડવા અંગે સરકાર સાથે સીધો સંપર્ક સાધ્યો. ૯-૧-૧૯૯૮ના રોજ ગુજરાત રાજ્ય નાણાં પંચના સભ્યો સાથે એક બેઠકનું આયોજન કરાયું અને પછી ૨૨-૧-૧૯૯૮ના રોજ છ સભ્યોની એક સમિતિએ નાણાં પંચને એક આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું.

તા. ૪-૨-૧૯૯૮ના રોજ આદિવાસી સ્વશાસન અંગે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ સાથે એક બેઠકનું આયોજન કરાયું. આ બેઠકમાં સરકાર દ્વારા બહાર પડાયેલા જાહેરનામાની ટીકા કરાઈ અને ધારો ફરીથી ઘડવા સૂચનો કરવામાં આવ્યાં. પંચાયતી રાજ વિભાગના સચિવ શ્રી બસુ પણ આ બેઠકના અંત ભાગમાં હાજર રહ્યા અને તેમને આ સૂચનો જણાવાયાં. સ્વશાસન અંગે આદિવાસીઓની વિભાવના વિશે પથી૭ માર્ચ, ૧૯૯૮ દરમ્યાન એનપીવાયએમ સાથે એક કાર્યશાળાનું આયોજન કરાયું. આવશ્યક દવાઓની નીતિની એડવોકસી માટેનું કામ વ્યવસ્થિત ઢબે આગળ વધી રહ્યું છે અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોનો અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. આગામી મહિનાઓમાં અન્ન સલામતી માટેની ઝુંબેશ હાથ ધરવાનું પણ આયોજન કરી રહ્યા છીએ.

અમે અમારી સહયોગી સંસ્થાઓને એ જણાવતાં આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ કે અમે રાજસ્થાનમાં જોધપુર ખાતે એક ક્ષેત્રીય કાર્યાલય શરૂ કર્યું છે. રાજસ્થાનમાંનાં સહયોગી જૂથો માટે અમે કાર્યક્રમ સમીક્ષા અંગે એક કાર્યશાળાનું આયોજન કર્યું હતું. તેનો હેતુ રણ પ્રદેશમાં મૂળભૂત અધિકારો અને આજીવિકાના પ્રશ્નો ઉકેલવાની રણનીતિઓ સમજવાનો હતો.

આ પ્રક્રિયામાં ૫ સંગઠનોએ ભાગ લીધો અને હવે સહભાગી કાર્યક્ષમ સમીક્ષા હાથ ધરાશે. જેન્ડર અંગે સંવેદનશીલતા કેળવવા તથા તેનો આયોજનમાં સમાવેશ કરવા માટે અમે એક કાર્યશાળાનું આયોજન કર્યું. તેમાં ૧૭ સંસ્થાઓમાંથી ૨૭ સહભાગીઓએ ભાગ લીધો. ‘નેશનલ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયા’ના બે સાથીઓએ તેમાં ભાગ લીધો અને મહિલાઓના પ્રશ્નો અંગેની સંસ્થાગત નીતિઓ વિશે વિચારોની આપલે કરી. અમારા એક સહયોગી જૂથ એમએમવીએસ દ્વારા અમારા સહયોગથી ૧૦થી ૧૩ જાન્યુઆરી, ૧૯૯૮ દરમ્યાન ગ્રામ પંચાયત અંગે મહિલાઓમાં જાગૃતિ લાવવા માટેના એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું. આ કાર્યક્રમનો હેતુ પંચાયતોમાં ભવિષ્યમાં નેતાઓ તરીકે મહિલાઓ તૈયાર થાય તે હતો. ઉદયપુરના આદિવાસી પ્રદેશમાં અમારી સહયોગી સંસ્થા ‘અંકુર’ દ્વારા ૭થી ૧૪ જાન્યુઆરી-૧૯૯૮ દરમ્યાન ૧૫૭ ગામોમાં આદિવાસી સ્વશાસન અંગે સરકારે જે કાયદો ઘડ્યો છે તે અંગેની સમજના પ્રચાર અર્થે એક પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

રાજસ્થાનના થાર રણ વિસ્તારની અમારી સહયોગી સંસ્થા ‘શાંતિ મૈત્રી મિશન’ દ્વારા સપ્ટેમ્બર-૯૭માં યોજાયેલી પદયાત્રાનો અહેવાલ પ્રકાશિત કરાયો છે. પંચાયતો આ અહેવાલનો ઉપયોગ સ્વશાસન માટે વધુ તક મળે તે માટે એડવોકસી કરવા માટે કરે છે. કારણ કે આ રણપ્રદેશમાં નહેર વિસ્તારમાં મોટા ભાગની શાસકીય સત્તા ‘કમાન્ડ એરિયા ડેવલપમેન્ટ એજન્સી’(સી.એ.ડી.એ.)ના હાથમાં છે. અમારા સાથીઓએ સાલાસર ખાતે ૨૦થી ૨૨ માર્ચ, ૧૯૯૮ દરમ્યાન ‘ઉરમૂલ ટ્રસ્ટ’ ની વાર્ષિક બેઠકમાં ભાગ લીધો. આ બેઠકનું મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ શાંતિ પર હતું તથા ‘ઉલ્કા’ દ્વારા સંજય ઘોષના કરાયેલા અપહરણના સંદર્ભમાં આ મુદ્દે ચર્ચા થઈ હતી. ઉચ્ચતિના રાજસ્થાનના ક્ષેત્રીય કાર્યાલયમાં નવા સાથીઓ જોડાયા છે. ક્ષમતા વર્ધનના કાર્યક્રમ માટે સુશ્રી અનિન્દિતા પટનાયક તથા સ્વશાસન ક્ષેત્રે સુશ્રી શંપા બાતબ્યાલ અને સુશ્રી કીર્તિ શર્મા જોડાયાં છે.

આ ત્રણ માસના ગાળા દરમ્યાન ઓરિસ્સામાં ‘ગ્રામ વિકાસ’ સંસ્થાના કાર્યક્રમોનો અભ્યાસ કરવાની અમને તક મળી. તે ‘ગ્રામીણ આરોગ્ય અને પર્યાવરણ કાર્યક્રમ’ ચલાવે છે. કાર્યક્રમના ટકાઉ આયોજન અંગેની સમજ તેનાથી અમને પ્રાપ્ત થઈ. સાર્વજનિક સંસાધનોના યોગ્ય સંચાલનથી કોઈ પણ સમુદાય ગામ માટે એટલા પ્રમાણમાં પૂરતું ભંડોળ ઊભું કરી શકે છે કે જેનાથી ગામમાં સફાઈ, આરોગ્ય અને શિક્ષણની જરૂરી સવલતોનો નિભાવ થઈ શકે. આ અનુભવમાંથી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ અર્થપૂર્ણ શીખ અને આંતરસૂઝ મેળવી શકે છે.

‘ઉન્નતિ’ છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં

‘સંવાદ’ નામની એક અનોખી ઘટનામાં ‘ઉન્નતિ’ની સહભાગિતા સાથે આ વર્ષનો આરંભ થયો. ‘સંવાદ’ એક વિકાસ મેળો હતો. ‘ચેતના’એ તેનું આયોજન કર્યું હતું. આ બનાવે અમને નાગરિકો, સરકાર અને ઉદ્યોગ ગૃહો સાથે વિકાસના વિવિધ પ્રશ્નો અને વ્યૂહરચનાઓ વિશે વિચારોની આપણે કરવાની તક પૂરી પાડી. છેલ્લા દાયકા દરમિયાન સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓની શી અસર પડી છે તેના વિશે પણ આદાન-પ્રદાન થયું. આ મેળાએ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, સરકાર અને ઉદ્યોગ ગૃહો વચ્ચે સંવાદનો માર્ગ મોકળો કરી આપ્યો. ‘ઉન્નતિ’એ આ મેળામાં ભાગ લીધો, સ્ટોલ દ્વારા સામગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યાં ચાલી રહેલી ચર્ચામાં ભાગ પણ લીધો. આ ચર્ચા દરમિયાન ‘ઉન્નતિ’ આંતરક્ષેત્રીય સહયોગ માટે તૈયાર હતી પરંતુ સામાજિક ન્યાયનાં પાયાનાં મૂલ્યો પર તથા વિકાસના હેતુ માટે જાળવાયેલાં નાણાંના ઉપયોગમાં કરકસર વર્તાય તેના પર તેણે ભાર મૂક્યો.

ગુજરાતમાં તાલીમકારોની ક્ષમતા વધારવા માટેની તાલીમના બીજા તબક્કામાં ૧૪ સંસ્થાના ૨૪ સહભાગીઓએ ભાગ લીધો. અમારી સહભાગી સંસ્થા ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટ (દ્વારકા)એ આ કાર્યક્રમનું યજમાનપદ સંભાળ્યું હતું. સહભાગીઓની પ્રક્રિયાને આગળ ધપાવવાની કુશળતા (ફેસિલિટેશન સ્કેલ) વધે તેના ઉપર આ કાર્યક્રમમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત, ઓખામંડળ પ્રદેશમાં પ્રાકૃતિક સંસાધનના સંચાલન ક્ષેત્રે શું કામ થાય છે તે જોવાની તક પણ સહભાગીઓને મળી. ઘણા સહભાગીઓએ પહેલી જ વાર દ્વારકાધીશનાં દર્શન કર્યાં.

‘વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમોમાં દસ્તાવેજીકરણની જરૂરિયાત અને મહત્વ’ અંગે બીજી એક કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ૨૮થી ૩૦ જાન્યુઆરી, ૧૯૯૮ દરમિયાનની આ કાર્યશાળામાં ૧૪ સંસ્થાઓના ૨૬ સહભાગીઓ ઉપસ્થિતિ રહ્યા હતા.

‘સહભાગી કાર્યક્રમ આયોજન’ અંગે ૩૧ માર્ચથી ૧ એપ્રિલ-૧૯૯૮ દરમિયાન એક કાર્યશાળાનું આયોજન કરાયું તેમાં ૨૦ સંસ્થાઓના ૨૮ સહભાગીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં સહભાગીઓને સહભાગી આયોજનનો હેતુ શો હોય છે તેની સમજ અપાઈ અને સહભાગી કાર્યક્રમ યોજનાઓ હાથ ધરવા માટેનાં વિવિધ સાધનો અને પદ્ધતિઓ વિશે તેમને સમજ આપવામાં આવી. બીજી એક કાર્યશાળા સહભાગી સંસ્થા ‘એક્શન એઈડ’ના ૧૨ કાર્યકરો માટે ૧૦થી ૧૨ માર્ચ-૧૯૯૮ દરમિયાન ‘પર્સપેક્ટિવ પ્લાનિંગ’ વિશે યોજવામાં આવી. આ પ્રકારના આયોજનમાં સામેલ પ્રક્રિયાઓ વિશેની સામૂહિક સમજ વિકસાવવાનો આ કાર્યક્રમનો હેતુ હતો. આ ત્રણ માસ દરમિયાન અમે માહિતી (ધોલેરા), જીવીએસટી(ઈડર), મહિલા પેયવર્ક(અમદાવાદ), સમજ ટ્રસ્ટ(વિરમગામ), ગ્રુપ(બાવળા) અને કામદાર સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા મંડળ(અમદાવાદ) સાથે વ્યક્તિગત સંપર્ક સાધી ચર્ચા-વિચારણા કરી. જુઓ પૃષ્ઠ ૩૯



વિકાસ શિક્ષણ સંસ્થાન

જી-૧, ૨૦૦, આઝાદ સોસાયટી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન નં-૬૭૪૬૧૪૫, ફેક્સ નં-૬૭૪૩૭૫૨. ઈ-મેલ : unnati@ad1.vsnl.net.in

ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ૨૧-એ, ૯, પોલ રોડ, બચરાજ જી કા બાગ, જોધપુર-૩૪૨૦૦૩ રાજસ્થાન.

રૂપાંકન : યશોદા કોરિયા અને તરુણ દીપ ગિરધર, ‘ઉન્નતિ’

ચિત્રાંકન : રણજીત બાલમુચુ

મુદ્રણ : સાહિત્ય મુદ્રણાલય પ્રા.લિ., ૫૫/૧૫, સીટી મિલ કમ્પાઉન્ડ, કાંકરિયા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૨, ફોન નં.-૫૩૨૪૯૯૦.

આપ લોકશિક્ષણ કે તાલીમ માટે વિચારમાં પ્રકાશિત સામગ્રીનો સહર્ષ ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉપયોગ કરનારને વિનંતી કે આ સ્રોતનો ઉલ્લેખ કરવાનું ના ભૂલે તથા પોતાના ઉપયોગથી અમને માહિતગાર કરે કે જેથી અમે પણ કાંઈક શીખી શકીએ.